रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D (D)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 29, 1979/आश्विन 7, 1901

No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 29, 1979/ASVINA 7, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1979

का०आ० 3301.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 246-रानीबान्ध (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुनाथ हेमब्रम, ग्राम चुर्कु, डाक० मुचीकाटा, जिला बंकुरा, बकुरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अब, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रघुनाथ हेमब्रम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान-सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[संख्या प०सं०-वि०म०/246/77]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 24th August, 1979

S.O. 3301.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raghunath Hembram, Vill. Churku, P.O. Muchikata, Distt. Bankura, Bankura a contesting candidate for general election to the West Bengal Legislative Assembly held in June, 1977, from 246-Ranibandh (ST) constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And wheras the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said

Shri Raghunath Hembram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. WB-LA/246/77]

M. L. CHANDA, Under Secy.

नई दिल्ली 17 सितम्बर, 1979

का० आ० 3302.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 106 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग, 1979 की निर्वाचन अर्जी सं० 1 में दिया गया उच्च न्यायालय, बिहार, पटना, का तारीख 20 अगस्त, 1979 का आदेश प्रकाशित करता है ।

"IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Election Petition No. 1 of 1979

Patna, the 20th August, 1979

Smt. Tarakeshwari Sinha . . .Petitioner

Vs.

Smt. Tarakeshwari Sinha . . . Petitioner

Mr. S. N. P. Sharma. the learned counsel for the petitioner submits that he has been instructed by the petitioner to intimate that the petitioner does not want to pursue the present election petition and that the same may be dismissed as not pressed.

In the circumstances, the election petition is dismissed as not pressed without costs.

Sd/- Manoranjan Prasad"

True Copy

M. M. Raza

20-8-79.

[सं०-82/बिहार-लो०म०/1/79]

एम०एल० चन्द, अवर सचिव

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1979

का०आ० 3303:—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जून, 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 228-मुलताई निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिवाजी पवार मार्फत बंसीलाल पवार, पोस्ट जौल खेडा, तहसील मुलताई, जिला बेतूल (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिवाजी पवार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-वि०स०/228/77]

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1979

S.O. 3303.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shivaji Pawar C/o Shri Bansi Lal Pawar, P.O. Jaul-kheda, Tehsil Multai, District Betul (Madhya Pradesh) a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in June, 1977 from 228-Multai constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Reiresentation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And wheras the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrfi Shivaji Pawar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/228/77]

आदेश

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 1979

का०आ० 3304:—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 28-बैतूल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल रज्जाक मोहम्मद अकबर शाह, पापुलर टेलर, बेतूलगंज-बैतूल, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारण 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल रज्जाक मोहम्मद अकबर शाह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-लो०म०/28/77]

आदेश से,

ORDER

New Delhi, the 23rd August, 1979

S.O. 3304.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Razzak Mohd. Akbar Shah, Popular Tailor, Betulganj, Betul, Distt. Betul, Madhya Pradesh, a contesting candidate for general election to the House of the People held in 1977 from 28-Betul Parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representaion of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Razzak Mohd. Akbar Shah to be disqualified for

being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP HP/28/77]

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1979

का०आ० 3305:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 24 करैरा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भाव सिंह, ग्राम बेसोरा कलां, पोस्ट डामरोन कलां, तहसील करैरा, जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भाव सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/24/77]

ORDER

New Delhi, the 30th August, 1979

S.O. 3305.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhav Singh, Village—Besora Kalan, Post—Damron Kalan, Teh Karera, District Shivpuri, Madhya Pradesh a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 24-Karera constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhav Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a state for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/24/77]

आदेश

का०आ० 3306.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1977 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 58-पवई निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टीका राम चौरसिया ग्राम व पो०आ०-मोहन्द्रा, तहसील पवई, जिला पन्ना (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री टीकाराम चौरसिया को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र०-वि०स०/58/77]

ओ०ना० नागर, अवर सचिव

ORDER

S.O. 3306.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tikaram Chaurasiya, Village—Mohendra, Tehsil—Pawai, Distt. Panna (M.P.), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in 1977 from 58-Pawai constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tikaram Chaurasiya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/58/77]

O. N. NFGAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1979

का०आ० 3307.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि फरवरी, 1978 में हुए विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 43-बारपेटा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अधर ज्ञान, गांव गायन हट्टी, पो० बारपेटा, जिला कामरुप (आसाम) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अधर ज्ञान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[संख्या आसाम-वि०स०/43/78]

ORDER

New Delhi, the 28th July, 1979

S.O. 3307.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Adhar Gayan, Vill. Gayanhati, P O. Barpeta, District Kamrup (Assam) a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in February, 1978 from 43-Barpeta constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Adhar Gayan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No AS-LA/43/78]

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1979

का०आ० 3308—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, केरल सरकार के परामर्श से श्री एम०पी० माधवन नैयर के स्थान पर, श्री जे०एस० जेसुदासन, आई०ए० एस०, विशेष सचिव, गृह विभाग, केरल सरकार को उनके कार्यभार संभालने की तारीख और अगले आदेशों तक केरल राज्य के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नाम निर्देशित करता है ।

[सं० 154/केरल/79]

New Delhi, the 5th September, 1979

S.O. 3308.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Kerala hereby nominates Shri J. S. Jesudasan, IAS, Special Secretary, Home Department, Government of Kerala, as the Chief Electoral Officer for the State of Kerala with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Shri M. P. Madhavan Nair.

[No 154/KL/79]

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

का०आ० 3309—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, आसाम सरकार के परामर्श से श्री पी० एन० राव के स्थान पर, श्री के०एम० राव, आई०ए०एस०, आयुक्त, हिल्स डिविजन, आसाम सरकार को तारीख 7 सितम्बर, 1979 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक आसाम सरकार के मुख्य निर्वाचन आफिसर के रूप में एतद्द्वारा नामनिर्देशित करता है ।

[सं० 154/आसाम/79]

वी० नागसुब्रमण्यम, सचिव

New Delhi, the 6th September, 1979

S.O. 3309.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Sec. 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of Assam hereby nominates Shri K. S Rao, IAS, Commissioner, Hills Division, Government of Assam, as the Chief Electoral Officer for the State of Assam with effect from the afternoon of 7th September, 1979 and until further orders vice Shri P. N. Rau.

[No. 154/AS/79]

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 7 जून, 1979

(आय-कर)

का०आ० 3310—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 'श्री अय्यप्पा मन्दिर हरद्वार' को उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वत्र विख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 2851 (फा०स० 176/73/77–आई०टी०ए०I)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 7th June, 1979

INCOME-TAX

S.O. 3310—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies 'Shri Ayyappa Temple, Hardwar' to be a place of public worship of renown throughout the State of Uttar Pradesh for the purposes of the said Section.

[No 2851 (F. No. 176/73/77-IT.AI)]

का०आ० 3311—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80 छ की उपधारा 2(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ 'श्री काशी विश्वनाथ स्वामी मंदिर, सेंट-थामस माउन्ट, मद्रास' को, तमिलनाडु राज्य में सर्वत्र प्रख्यात लोक पूजा का स्थान अधिसूचित करती है ।

[सं० 2852(फा०स० 176/87/78–आई०टी० ए–1)]

बी०एम० सिंह, अवर सचिव

S.O. 3311.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (b) of Section 80G of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies 'Sri Kasi Viswanatha Swami Temple, St. Thomas Mount, Madras' to be a place of public worship of renown throughout the State of Tamil Nadu for the purposes of the said Section.

[No. 2852 (F. No. 176/87/78-IT/AI)]

B M SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 1979

आय-कर

का०आ० 3312—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "खेमीसतीजी मंदिर ट्रस्ट, झुनझुनू" को निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए और से उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है ।

[सं० 2898 (फा० सं० 197/191/78 आ०क०/ग1)]

जे० पी० शर्मा, निदेशक

New Delhi, the 30th June, 1979

INCOME-TAX

S.O. 3312.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Khemsatiji Mandir Trust, Jhunjhunu" for the purpose of the said section for and from the assessment year(s) 1975-76.

[No 2898 (F No 197/191/78-IT/AI)]

I P SHARMA, Director

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

बैंकिंग प्रभाग

का०आ० 3313—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की दिनांक 10 जुलाई, 1979 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में "श्रीनगर एवं अनन्तनाग के "जिलों" शब्दों के स्थान पर" श्रीनगर, बडगाम, अनन्तनाग तथा पुलवामा के जिले" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या एफ० 1-4/77-आर०आर०बी० (1)]

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 10th September, 1979

BANKING DIVISION

S.O. 3313.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby makes the following amendment in this Department's Notification of even number dated the 10th July, 1979 namely :—

In the said notification, for the words "districts of Srinagar and Anantnag" the words "districts of Srinagar, Badgam, Anantnag and Pulwama" shall be substituted

[No. F. 1-4/77-RRB(I)]

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1979

का. आ. 3314.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन पी दूबे को सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 2 अक्तूबर, 1979 से प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान उक्त श्री दूबे, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[संख्या एफ. 1-7/79-आर आर बी]

दिनेश चन्द्र, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1979

S.O. 3314.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N P Dubey as the Chairman of the Surguja Kshetriya Gramin Bank, Ambikapur and specifies the period commencing on the 2nd October, 1979 and ending with the 30th September, 1982 as the period for which the said Shri Dubey shall hold office as such Chairman

[No F 1-7/79-RRB]

DINESH CHANDRA, Director

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

का०आ० 3315—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध 29 जनवरी, 1980 तक न्यू बैंक आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध प्लेजी के रूप में इसके द्वारा मैसर्स माजदा थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों की धारिता से है।

[संख्या 15(22)-बी०आ०-III/79]

एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 10th September, 1979

S.O. 3315.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act shall not apply to the New Bank of India Ltd, New Delhi upto the 29th January, 1980 in respect of the shares of M/s Mazda Theatres Pvt. Ltd held by it, as pledgee

[No 15(22)-B O III/79]

N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 1979

का०आ० 3316—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध "बिग कांचीपुरम को-आपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड, कांचीपुरम" पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 1 मार्च, 1981 तक उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध इसके द्वारा ग्राम एरीवाक्कम, कांचीपुरम, तालुक, जिला चिंगलपट, तमिलनाडु में स्थित कुछ गैर बैंकिंग परिसम्पत्तियों अर्थात् सर्वे नं० 53 में 1 06 एकड़ (4 24 एकड़ का चौथाई भाग) की धारिता से है।

[संख्या 8(23)/79-ए० सी०]

New Delhi, the 11th September 1979

S.O. 3316.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to the Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd, Kancheepuram in so far as they relate to its holding of certain non-banking assets viz, 1 06 acres (1/4 share of 4.24 acres) of land in survey No 53 at Erivakkam village, Kancheepuram Taluka Chinglepet District, Tamil Nadu from the date of publication of this notification in the Gazette of India to 1st March, 1981.

[No. 8(23)/79-AC]

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

का०आ० 3317—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध चिपलून अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, चिपलून पर इस अधिसूचना

के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 1 मार्च, 1982 तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहां तक उनका सम्बन्ध इसके द्वारा गैर बैंकिंग परिसम्पत्ति अर्थात् चिपलून म्युनिस्पल हाउस नं० 1396/1625, चिपलून सर्वे नं० 215ए (1)ए की धारिता से है।

[सख्या 8(24)/79-ए०सी०]

यशवन्त राज, अवर सचिव

New Delhi, the 12th September, 1979

S.O. 3317.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of Section 9 of the said Act shall not apply to Chiplun Urban Co-operative Bank Ltd., Chiplun in so far as they relate to its holding of non banking asset viz Chiplun Municipal House No. 1396/1625 at Chiplun Survey No 215A (1)A for a period from the date of the publication of this notification in the Gazette of India to 1 March, 1982.

[No. 8(24)/79-AC]

YASHWANT RAI, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1979

का०आ० 3318—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं का निर्यात से पूर्व निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण किया जाना चाहिए,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए है और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1964 के नियम 2 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है,

अतः अब, उक्त उप-नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 771 तारीख 6 मार्च, 1965 में, जहां तक कि वह झींगा मछली (चिंगट) को, लवण जल में पैक करने या शुष्क पैक करने के लिए डिब्बा बन्दी से संबंधित है तथा डिब्बा बन्द केकड़ा मीट से सबंधित सं० का०आ० 455 तारीख 5 फरवरी, 1977 को भागतः अधिक्रान्त करते हुए उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

2 सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 14/1 बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल) कलकत्ता 700001 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) अधिसूचित करना कि डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पादों का, निर्यात से पूर्व, क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण किया जाएगा;

(2) इस आदेश के उपाबन्ध 1 में यथा उपवर्णित में डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1979 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को, निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसी डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पादों को निर्यात से पूर्व लागू होगा,

(3) इस आदेश के उपाबन्ध 1 में दिए गए विनिर्देशों को, डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बनी वस्तुओं के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना,

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान, डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पादों के निर्यात का तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त अभिकरण द्वारा जारी किया गया उस आशय का निरीक्षण प्रमाण पत्र न हो कि ऐसी डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पाद मानक विनिर्देशों के अनुरूप है तथा निर्यात योग्य है,

(5) इस आदेश की कोई भी बात भावी खेपों को, भूमि, जल या वायु मार्ग द्वारा डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पादों के उन नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका मूल्य 25 रुपये से अधिक नहीं है।

(6) इस आदेश में, डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पाद से, वायुरुद्ध बन्द (टिन्ने) में पैक निम्नलिखित मछली उत्पाद है, अर्थात् :—

(1) लवण जल में या अन्य किसी अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या शुष्क पैक किए हुए सभी प्रकार के झींगे/चिंगट।

(2) खाद्य केकड़ों से, जैसे माइल्ला सिरेटा प्रोटोनस पालजिक्स से प्राप्त लवण जल में बन्द केकड़ों का मांस या कोई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित पद्धति से डिब्बा बन्द केकड़े का मांस।

अनुबन्ध 1

मछली तथा मछली से बने उत्पाद निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1964 को, जहां तक कि उनका सबंध ऐसी झींगा मछली (चिंगट) से है जो लवण जल में डिब्बा बन्द है या शुष्क पैक की गयी है, तथा डिब्बा बन्द केकड़े का मांस निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 को अधिक्रमण करते हुए, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

(1) इन नियमों का नाम डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बनी वस्तु निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाए

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(1) "डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पाद" से

(1) लवण जल या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित रूप मे डिब्बा बन्द या शुष्क पैक सभी प्रकार के झींगे (चिगट) अभिप्रेत है,

(2) खाद्य केकड़ो, जैसे साइल्ला सिरेटा, प्रोटोनस पालिजियम के मास से प्राप्त लवण तथा लवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित रूप मे डिब्बा बन्द या शुष्क पैक केकड़े का मास अभिप्रेत है।

(क) 'मानक विनिर्देशो' से, लवण जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित रूप में या शुष्क पैक डिब्बा बन्द झींगो (चिगट) से सबधित लवण जल मे या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित रूप मे केकड़े के मास से सबंधित विनिर्देश अभिप्रेत हैं।

3 क्वालिटी नियंत्रण

(क) प्रसंस्करण एकको की अपेक्षाए : अभिकरण द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण एकक ही, डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पादो का निर्यात प्रसंस्करण करेंगे। ऐसा अनुमोदन केवल उन एककों को दिया जाएगा जिनके पास नीचे विहित रूप में न्यूनतम सुविधाए होंगी, जिनका न्यायनिर्णयन भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा किया जाएगा।

(1) वातावरण, बनावट तथा अभिन्यास :

केनरी तथा आसपास के क्षेत्र ऐसे होंगे कि उन्हें आपत्तिजनक गंध, धुए, धूल तथा अन्य सदूषणो से मुक्त रखा जा सके। डिब्बा बन्दी एकक के आसपास दलदल, कूड़े का ढेर तथा पशुगृह नही होने चाहिए जिससे स्वच्छता संबंधी कठिनाई उत्पन्न न हो। धूल तथा अन्य सदूषणों से बचाने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र के सभी निकटतम पहुच मार्गों पर, जो प्रसंस्करण-कर्ता के भौतिक नियंत्रण में है, कंकरीट या कोल बिछाया जाना चाहिए या घास उगाई जानी चाहिए। इमारतो में उपस्करों या कर्मचारियों के लिये पर्याप्त स्थान होना चाहिए। उनकी संरचना अच्छी होनी चाहिए तथा उसकी यथासमय उपयुक्त मरम्मत की जाती रहनी चाहिए। वे ऐसी डिजाइन तथाबनावट की होनी चाहिए कि कृन्तको, पक्षियों या अन्य प्रकार के कीड़ों के प्रवेश को रोका जा सके तथा सफाई पर्याप्त रूप से व आसानी से की जा सके।

प्रसंस्करण एकक किसी स्थायी स्वरूप के भवन मे होगा, जहां वर्षा तथा हवा से उड़कर आने वाली धूल जैसे जलवायु सबधी आम खतरो से पर्याप्त सुरक्षा रहे। विभिन्न अनुभागो का अभिन्यास इस ढग से किया जाएगा कि काम सुचारु रूप से चल सके तथा प्रसंस्करण पूर्व अनुभाग से संभव दूषण रोका जा सके।

(2) प्रसंस्करण क्षेत्र :

वह क्षेत्र जहां कच्चा माल प्राप्त तथा भण्डारित किया जाता है, उस क्षेत्र से, जिसमें उत्पाद अन्तिम रूप मे तैयार होता है या उसकी पैकिंग की जाती है, इस ढग से अलग रखा जाएगा कि तैयार उत्पाद जीवाणु दूषण से बच सकें। खाद्य उत्पादो का भण्डार के लिए उपयोग मे लाए जाने वाले क्षेत्र तथा कक्ष उन क्षेत्रो तथा कक्षों से अलग तथा भिन्न होंगे जिनमें अखाद्य सामग्री रखी जाती है। जिन क्षेत्रो में सामग्री उठाई धरी जाती है वे निवास के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त क्षेत्रो से पूर्णतः अलग होंगे।

(3) छत, दीवार तथा फर्श :

छत की डिजाइन तथा बनावट इस प्रकार की होगी कि उसे धूल, वाष्प तथा कृन्तकों के जमा होने से बचाया जा सके तथा उसकी आसानी से सफाई की जा सके। छत की ऊंचाई कम से कम 3 मीटर (10 फीट) होगी। वह दरारो तथा खुले जोड़ो से मुक्त, चिकनी जल सह तथा हल्के रंग वाली होगी।

केनरी की भीतरी दीवारें चिकनी, जल सह, गर्तों तथा दरारों से मुक्त, हल्के रग वाली तथा कम से कम 1 5 मीटर (5 मीटर) ऊंची तथा इस प्रकार कि होगी कि उनकी आसानी से सफाई की जा सके। दीवार मे कोई प्रक्षेप नही होना चाहिए और पाइप और केबिल अच्छी प्रकार से ढके होगे।

फर्श मजबूत, जल सह, अविषैले, अनवशोषी तथा असंक्षारणीय सामग्री से बनाए जाएंगे जिन्हें आसानी से विसक्रामक तथा साफ किया जा सके। वे फिसलन तथा दरारों से मुक्त होने चाहिए और उनमें ढलान ऐसा हो कि वह पानी बहा ले जाने के लिए उपयुक्त हो।

(4) मक्खियो से बचाव, कीड़ों और पशुओं पर नियंत्रण :

प्रसंस्करण क्षेत्र मे मक्खियों से बचाव के लिए प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी तथा अन्य कीड़ो कृन्तकों, पक्षियो, बिल्लियों, कुत्तो आदि के प्रवेश को रोकने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र में उपयुक्त उपाय किए जाएंगे।

(5) प्रकाश तथा संवातन :

सभी कार्य क्षेत्रों में अच्छा प्रकाश होना चाहिए। प्रसंस्करण मेज या उत्पाद की तैयारी के किसी भी प्रक्रम पर प्रकाश के लिए बल्ब तथा फिक्सर सीधे नही लटकाए जाने चाहिए। वे ऐसे सुरक्षित प्रकार के होने चाहिए कि टूटने पर सदूषण रोका जा सके। अत्याधिक ऊष्मा, सघनन तथा अवांछनीय गन्ध, धूल, वाष्प या धुएं को रोकने के लिए परिसर में अच्छी संवातन व्यवस्था होनी चाहिए। अत्यधिक उष्मा, प्रवाष्प, अवांछनीय लपेटे या संदूषण एरोसोल उत्पन्न करने वाले उपकरणों तथा क्षेत्र के प्राकृतिक या यांत्रिक संवातन प्रणाली द्वारा संवातन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सवातन द्वार में परदा लगा होना चाहिए। और यदि अपेक्षित हो तो उपयुक्त वायु फिल्टर लगा होना चाहिए। खिड़कियो पर भी जो संवातन के प्रयोजनों के लिए खोली जाती है, परदे लगे होने चाहिए। सफाई के लिए परदे आसानी से हटाए जा सकने वाले होने चाहिए और वे जगरोधी सामग्री से बने होने चाहिए।

(6) काम करने वाली मेजे तथा बर्तन :

मछली से बने डिब्बा बन्द उत्पादो के प्रसंस्करण के दौरान प्रयुक्त कार्य मेज, कार्य सतह आधान, ट्रे, टैंक या अन्य बर्तन चिकनी, अप्रभावित अविषैली सामग्री के होंगे जो कि जगरोधी होंगे तथा डिजाइन और बनावट इस प्रकार की होगी कि स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा जा सके तथा सुगमता से अच्छी सफाई की जा सके। खाद्य वस्तुओ के सम्पर्क में आने वाली सतहें चिकनी, गढ़ढो, दरारों, मनुष्यों के लिए हानिकारक पदार्थों से मुक्त होंगी। उनकी बार-बार सफाई की जा सकती हो और उन्हें रोगाणुनाशी बनाए रखा जा सकता हो। मेज की सतह स्टैनलैस स्टील या एल्यूमिनियम की होगी और चिकनी तथा गढ़ढो और दरारों से मुक्त होगी। कार्य मेजों की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कार्य सुगमता से किया जा सके। तथा उनके नीचे और आसपास सफाई आसानी से की जा सके। सामग्री धोने वाले टैंकों का डिजाइन इस प्रकार का होगा कि पानी उसमे सभी स्थानो पर जा सके और पानी को लगातार बदला जा सके तथा उनमें नाली का और सुगम सफाई का प्रबन्ध किया जा सके। अखाद्य तथा दूषित सामग्री के लिए प्रयुक्त बर्तनों की पहचान इस प्रकार होनी चाहिए कि खाद्य वस्तुओ की उठाई धराई के लिए उन्हें प्रयुक्त न किया जा सके। प्रसंस्करण क्रिया के दौरान कार्य क्षेत्रो से अपशिष्ट सामग्री शीघ्र हटाने के लिए पर्याप्त अपशिष्ट आधानों की व्यवस्था की जाएगी।

(7) उपस्कर तथा मशीनें

मशीनों तथा उपस्करों की डिजाइन इस प्रकार की होगी कि विसंक्रमण तथा अच्छी सफाई के लिए उनके पुर्जे आदि आसानी से खोले जा सकें, और स्थिर उपस्कर इस ढंग से लगाए जाएंगे कि उन तक आसानी से पहुंचा जा सके और उनकी अच्छी सफाई की जा सके तथा उन्हें विसंक्रमण किया जा सके। प्रत्येक केनरी में निम्नलिखित उपस्कर तथा मशीनें पर्याप्त मात्रा में लगाई जाएंगी :—

(1) कारगर दशा में रखी गई अर्धस्वचलित तथा स्वचलित सिलाई की मशीनें,

(2) (क) थर्मामीटर (ख) दबाव जाली (ग) सीम स्प्रेडर (घ) संवातन वाल्व तथा (ङ) सुरक्षा वाल्व के युक्त रिटार्ट,

(3) कन्वेयर पद्धति सहित वहन चेम्बर,

(4) मानक तुलन मशीनें तथा बाट

(5) धवलन टैंक तथा स्टेनलैस स्टील से बने सबंधित बर्तन,

(6) एक लाइन में कम से कम 7 अंक उत्कीर्ण करने की क्षमता वाली कोड उत्कीर्णन मशीनें,

(7) स्वचालित क्लोरीनीकरण यंत्र के साथ फिट किया गया शीतल टैंक,

(8) उचित प्रकार के बायलर तथा उप-साधन तथा एक ही समय में सभी सामान्य क्रियाओं के लिए भाप वितरण क्षमता, तथा प्रवाष्प ले जाने वाली सभी नालियां उचित रूप से उष्मारोधी होंगी।

(9) सीवन दोष, पी एच, खारापन, निर्जीवाणुहीनता, वैक्यूम प्राप्त क्लोरीन आदि जैसी बातों का नैमिक पता लगाने के लिए परीक्षण सुविधाएं, तथा

(10) तैयार डिब्बों वाली क्रेटों को उठाने के लिए यांत्रिक उत्थापक उपस्कर ।

(8) भण्डारकरण तथा भाण्डागारण :

डिब्बा बन्द करने वाली यूनिटों के पास, डिब्बा बन्द उत्पादों के अलग भाण्डागारण के लिए सुविधाएं होंगी। भाण्डागार पर्याप्त क्षमता वाले होंगे तथा ऐसे होंगे कि भण्डारित उत्पाद को, चरम तापमान पर शुष्क तथा अनुच्छन रखा जा सकता हो। इसे नमी से पर्याप्ततः बचाया जाएगा तथा भली प्रकार साफ और स्वास्थ्यकर रूप में रखा जाएगा ।

सभी प्रक्षालक तथा रोगाणुनाशक अलग-अलग भण्डारित किए जाएंगे। पैकिंग सामग्री को भण्डार करने की व्यवस्था अलग से होगी। अग्निशामक यंत्रों के अतिरिक्त विषैले पदार्थ जैसे, कृन्तकनाशी, धूमक, कीटनाशी या अन्य पदार्थ, अग्निशामक उपस्कर को छोड़कर, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पृथक बन्द कमरे में रखे जाने चाहिए। ये सभी पदार्थ तथा उपस्कर केवल प्रशिक्षित व्यक्तियों के भारसाधन में होने चाहिए।

(9) जल तथा बर्फ

पेय जल (जिसकी विशेषताएं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पेय जल के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक में दी गयी है अपेक्षाओं के अनुसार होंगी) का अच्छी मात्रा में प्रदाय होना चाहिए। प्रदाय की लाइनों में सूक्ष्म जीवों के बढ़ने का कम करने के लिए पानी में अवशिष्ट के भीतर क्लोरीन अंश को परिवर्तित करने के लिए क्लोरीनीकरण पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। कच्ची सामग्री को धोने के लिए प्रयुक्त जल पुनः प्रयुक्त करने के लिए तब तक प्रक्रमित नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे पीने योग्य क्वालिटी के स्तर तक पुनः भण्डारित नहीं कर दिया जाता। यदि प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल, पेय जल के प्रदाय स्रोतों से भिन्न स्रोतों से दिया जाता है तो उसके पेय होने के बारे में प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा जो अभिकरण या उसके द्वारा अनुमोदित कोई संस्था देगी। यदि बायलर या अन्य सहायक सेवाओं के लिए पीने के अयोग्य जल का प्रदाय किया जाता है तो सहायक जल वितरण पद्धति तथा पेय जल वाहक पद्धति के बीच कोई आस संबंध नहीं होगा। यदि जल संचयन टंकी से प्राप्त जल प्रयुक्त किया जाता है तो संचयन टंकी पर्याप्त क्षमता वाली होगी और उसे बाहरी संदूषणों से सुरक्षित रखा जाएगा। संचयन टंकी 6 मास में कम से कम एक बार अच्छी तरह साफ की जाएगी। प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त जल में, क्लोरीन का अंश, कम से कम 3 पी०पी०एम० रखा जाएगा।

बर्फ पेय जल से बनाई जाएगी और उसका विनिर्माण, उठाई-धराई तथा संचयन इस प्रकार किया जाएगा कि उसे संदूषणों से बचाया जा सके। यदि बाहर की बनी बर्फ प्रयोग की जाती है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह पेय जल से बनी तथा दूषित नहीं है। बर्फ तोड़ने की मशीनों का यदि प्रयोग किया जाता है तो उन्हें अच्छी साफ हालत में रखा जाएगा। बर्फ को दूषण तथा अधिक पिघलने से बचाने के लिए एक विशेष कक्ष या अन्य उपयुक्त भण्डार गृहों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

10. सफाई संबंधी सुविधाएं तथा नियंत्रण :

(i) डिब्बों की सफाई तथा धुलाई

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक डिब्बे का भली प्रकार निरीक्षण किया जाएगा कि वह टूटा नहीं है और उसमें कोई कमी नहीं है। डिब्बों में मछली से बने उत्पाद पैक करने से पहले उन्हें पेय जल (विशेष रूप से गर्म) जिसमें क्लोरीन अंश 10 पी०पी०एम० है, अच्छी तरह साफ किया जाएगा।

(ii) कार्य मेजों, ट्रे, बर्तनों तथा उपस्करों की धुलाई तथा विसंक्रमण

प्रसंस्करण के दौरान प्रयुक्त कार्य मेजों, ट्रे, बर्तनों, कटिंग बोर्ड, डिब्बों उपस्करों तथा कार्य साधनों के विसंक्रमण तथा सफाई के लिए आवश्यक सुविधाएं दी जानी चाहिए। बर्तन, ट्रे तथा मेज की सतह जो पैक न किए हुए माल के सम्पर्क में आती है, पहले उपयुक्त साफ करने वाले पदार्थ से साफ की जाएगी और अन्त में न्यूनतम 50 पी०पी०एम० क्लोरीन वाले जल से साफ की जाएगी। आवश्यकतानुसार ऐसी सफाई तथा धुलाई की जानी चाहिए। यह अच्छा होगा कि ऐसी सफाई तथा धुलाई की सुविधाएं एक अलग कक्ष में हों जहां गर्म तथा ठंडे पेय जल की सप्लाई उपयुक्त दबाव से हो और वहां से जल निकास की भी उचित सुविधाएं हों।

(iii) फर्श की धुलाई

प्रसंस्करण हाल, दिन का कार्य प्रारम्भ करने से पहले, एक बार साफ किया जाएगा और फिर प्रत्येक पारी के अन्त में साफ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सफाई तथा धुलाई आवश्यकतानुसार बारबार की जाएगी।

(iv) वाहित मल तथा अपशिष्ट का निपटान

संयंत्र से तरल तथा अर्ध तरल अपशिष्ट को हटाने के लिए, उपयुक्त तथा पर्याप्त जल नालियां होंगी। वहां फर्श का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा जहां पानी इकट्ठा तथा बन्द हो जाए। नालियां चिकनी तथा अप्रभावित सामग्री से बनी होंगी तथा डिजाइन इस प्रकार की होगी कि उसमें अधिक से अधिक तरल पदार्थ बह सके और न उसमें बाढ़ आए और न वह नालियों के बाहर जा सके। केवल खुली नालियों के अतिरिक्त अपशिष्ट ले जाने वाली नालियों उचित रूप से संवातित होंगी और यदि अपेक्षित है तो ठोस अपशिष्ट सामग्री को हटाने के लिए केच बेसिन तक ले जाया जाना चाहिए। ऐसा बेसिन प्रसंस्करण क्षेत्र से बाहर स्थित होना चाहिए और जल सह कंकरीट या अन्य सामान सामग्री का बना होना चाहिए कृन्तकों के प्रवेश को रोकने के लिए, खुली नालियों के जो दीवारों में से होकर गुजरती है, मुख पर धातु की जालियां लगाई जाएगी।

अपशिष्ट जल तथा कूड़े करकट के निपटान के लिए यथाशीघ्र ऐसा प्रबन्ध किया जाएगा कि पड़ोसी के लिए कोई सफाई संबंधी समस्या उत्पन्न न हो, शौच स्थल से मल इस ढंग से हटाया जाएगा कि उस तक मक्खियां न पहुंच सकें और यूनिट को दिया जाने वाला पानी उससे प्रदूषित न हो। किसी भी दशा में परिसर में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट या पानी एकत्रित नहीं होगा।

(5) कारखाना परिसर से कुत्ते तथा पशुओं का बहिष्कार :

कुत्ते, बिल्लियों तथा अन्य पशुओं को, जिनसे रोग पैदा हो सकते हैं प्रसंस्करण परिसर में न तो प्रवेश करने दिया जायगा और न उन्हें उसमें या उसके आसपास रहने दिया जायेगा ।

(vi) शौच सुविधाएं :

इस संबंध में लागू विधिक अपेक्षाओं के अनुसार सफाई की दृष्टि से पर्याप्त शौच सुविधाएं दी जाएंगी । शौच स्थल प्रसंस्करण क्षेत्रों से दूर अलग स्थित होंगे । उनमें पर्याप्त प्रकाश होगा । शौच स्थल में अपने आप बंद होने वाले दरवाजे तथा हाथ धोने का बेसिन तथा साबुन की सुविधाएं होंगी । धुलाई के प्रयोजनों के लिए पेय जल प्रयुक्त किया जाएगा ।

(11) कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा सफाई :

संयंत्र के प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित है या कारित कर सकता है, एकक के किसी भी क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । ऐसे रोग का पता आसानी से लगाने के लिए प्रबंधक उन कर्मचारियों की, जो एकक के किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षा कराएगा ।

कैनरी में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी कार्य करते समय अत्यधिक सफाई का ध्यान रखेंगे तथा मछली से बने उत्पादों को अन्य पदार्थ संदूषण से बचाने के लिए समस्त सावधानी बरतेंगे । प्रबन्धक समस्त कर्मचारियों को उनके कार्य के अनुसार ऐप्रेन तथा टोपियां देगा । मछली के उत्पादों की उठाई धराई में प्रयुक्त वस्त्राने साफ तथा स्वास्थ्यकर ढंग से रखे जायेंगे तथा अपारगम्य सामग्री के बने होंगे किन्तु उस दशा में नहीं जब इनका प्रयोग अन्यथा असंगत हो ।

कर्मचारी प्रत्येक दिन का कार्य आरम्भ करने से पहले तथा शौच स्थल में जाने के पश्चात काम आरम्भ करने से पहले तथा अन्य अवसरों पर जहां भी आवश्यक हो, अपने हाथ साबुन या किसी अन्य प्रक्षालक वस्तु से तथा गर्म पानी से धोएंगे । कर्मचारी, जब भी आवश्यक हो और विशेष रूप से प्रसंस्करण कक्ष से प्रत्येक अनुपस्थिति के पश्चात तथा उसमें प्रवेश करने से पूर्व अपने पैर पेय जल तथा साबुन से धोएंगे । वस्त्रानों का पहनना कर्मचारियों को हाथ धोने की आवश्यकता से मुक्त नहीं करेगा ।

उठा-धराई तथा प्रसंस्करण के दौरान कोई भी ऐसा व्यवहार करना जैसे, तम्बाकू या कोई अन्य सामग्री खाना धूम्रपान करना या चबाना थूकना आदि, जो उत्पाद को संभाव्यत: दूषित कर सकता है उठा-धराई तथा प्रसंस्करण क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में करना सख्त मना होगा ।

जहां स्त्री पुरुष दोनों नियोजित हों, वहां अलग-अलग शौचागार, भोजन कक्ष, कपड़े बदलने के लिए कक्ष तथा आराम कक्षों की सुविधाएं दी जाएंगी । सामान्यत: भोजन कक्ष में सभी कर्मचारियों के लिए बैठने की जगह होगी तथा अनावश्यक संकुलन किए बिना कपड़े बदलने के कक्ष में प्रत्येक कर्मचारी को झाँकर सुविधाएं दी जाएंगी ।

कार्यकाल के घंटों के दौरान न पहने जाने वाले कपड़े और जूते प्रसंस्करण क्षेत्र में नहीं रखे जाएंगे ।

(12) परिवहन सुविधाएं :

कच्चा माल, केवल विद्युत्तरोधी प्रणीतित वाहनों में ही ले जाया जाएगा । ऐसे वाहनों को प्रत्येक उपयोग के पश्चात धोया तथा रोगाणुओं से मुक्त किया जाएगा तथा इस तरह से रखा जाएगा कि वे उत्पाद को दूषित न कर सकें ।

कोई भी व्यक्ति जिसके बारे में यह ज्ञात है कि वह संक्रामक रोग से पीड़ित है या जिसके संक्रामक घाव है या खुली चोट है, मछली के उत्पादों के परिवहन में नहीं लगेगा । आवश्यक आधानों तथा उपस्करों तथा वाहनों की सफाई नैमित्तिक रूप से की जाएगी जिसमें उचित अपमार्जक या रोगाणुनाशक तत्व मिले हुए पेय जल या साफ समुद्र के पानी से धोना, रगड़ाई तथा सफाई करना आवश्यक है ।

(13) अभिलेखों का रखा जाना :

डिब्बा बंद मछली तथा मछली से बने उत्पादों के प्रसंस्करण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए प्रसंस्करणकर्ता परिषद द्वारा समय समय पर यथा विहित आवश्यक रजिस्टर तथा रिकार्ड रखेगा । यह अभिलेख तथा रजिस्टर अभिकरण के अधिकारियों को यथापेक्षित रूप में उपलब्ध किया जाएगा ।

प्रसंस्करण एककों का अनुमोदन : निर्यात के लिए डिब्बा बंद मछली तथा मछली से बने उत्पादों को प्रसंस्करण करने का इच्छुक प्रसंस्करणकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में परिषद द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण के अधिकारी प्रसंस्करण एकक में यह देखने के लिए जायेंगे कि एकक में प्रसंस्करण के लिए सुविधाएं हैं या नहीं । यदि यह पाया जाता है कि एकक में वे न्यूनतम सुविधाएं जो इन नियमों में विहित हैं, विद्यमान हैं तो परिषद यह देखने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करेगा कि एकक में पर्याप्त सुविधाएं हैं तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए, वह अपना अनुमोदन अभिकरण को सूचित करेगा । पैनल का अनुमोदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर अभिकरण या तो एकक को अनुमोदित करेगा तथा उसे डिब्बा बंद निर्यात के लिए मछली तथा मछली से बने उत्पादों का प्रसंस्करण करने की अनुमति दे देगा या उसे अनुमोदित करेगा कि और प्रसंस्करणकर्ता को निर्यात के लिए डिब्बा बंद मछली तथा मछली से बने उत्पादों के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं देगा ।

(2) अभिकरण ऐसे किए गए अनुमोदन की सूचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखित रूप में देगा । एकक के अनुमोदित कर दिये जाने की दशा में, पैनल अपने द्वारा अभिलिखित कमियों को दर्शाते हुए, इसकी सूचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखित रूप में देगा ।

(2) 1 ऐसी कमियां दूर करने के पश्चात प्रसंस्करणकर्ता कमियों दूर करने की बाबत विस्तृत रिपोर्ट सहित एक नया आवेदन अभिकरण को प्रस्तुत करेगा । इस आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर अभिकरण पैरा (1) तथा (2) में विस्तृत रूप से दिए गए कदम उठाएगी ।

(3) निम्नलिखित कारणों से, सूचना की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के पश्चात संबंधित प्रसंस्करणकर्ता को सूचना देकर, दिया गया अनुमोदन वापिस ले लिया जाएगा, अर्थात् –

(1) यदि उपस्करण, मशीनरी और भंडार सुविधाएं अच्छी चालू हालत में नहीं हैं,

(2) यदि एकक की स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है,

(3) यदि प्रति-जांच के लिए, लिए गए नमूने अधिकथित मानकों के अनुसार नहीं हैं,

(4) यदि प्रसंस्करणकर्ता ने अधिसूचना के उपबंधों या समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन किया है या जानबूझकर उल्लंघन करने का प्रयत्न किया है ।

(4) अनुमोदन के ऐसे वापिस ले लिए जाने की सूचना प्रसंस्करणकर्ता को लिखित रूप में दी जाएगी ।

(5) (1) यदि प्रसंस्करणकर्ता अनुमोदन वापिस ले लिए जाने के विनिश्चय से व्यथित है तो वह अपील पैनल के समक्ष अपील फाइल कर सकता है ऐसे मामलों में उसे प्रसंस्करण जारी रखने की अनुमति होगी ।

(2) यदि अपील-पैनल विनिश्चय उसके प्रतिकूल करता है तो प्रसंस्करण को मध्यवर्ती अवधि के दौरान प्रसंस्कृत सामग्री निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(6) जिस एकक का अनुमोदन वापिस ले लिया गया है, वह कमियों को दूर करने के पश्चात अभिकरण से नया अनुमोदन लेने के लिए नए सिरे से आवेदन कर सकेगा ।

(7) उपरोक्त 3(i), 3(ii), 3(iii) तथा 3(iv) में दिए गए कारणों से, यदि किसी भी समय उत्पाद की अनुरूपता को विनिर्देशों के अनुरूप बनाए रखने में कठिनाई होती है या किसी कारणवश अभिकरण यह निर्देश देता है कि निर्यात के लिए उत्पादन निलम्बित कर दिया जाए तो अभिकरण को सूचित करते हुए निर्यात के लिए प्रसंस्करण तभी निलम्बित कर दिया जाएगा। निर्यात के लिए प्रसंस्करण तभी पुनः आरम्भ किया जाएगा जब उसके लिए अभिकरण लिखित में अनुमोदन दे दे।

ग. **प्रसंस्करण** : (1) प्रसंस्करणकर्ता सक्षम तकनीकी कर्मचारियों के पर्यवेक्षण में ही अनुमोदित एककों में प्रसंस्करण करेगा।

(2) प्रसंस्करण के लिए केवल ऐसी कच्ची सामग्री, जो ताजी, स्वच्छ, दुरुस्त विशिष्ट आकृति वाली, सुगंध, रंग तथा बनावट वाली होगी, स्वीकृत की जाएगी।

(3) प्रसंस्करण एकक में आने वाली कच्ची सामग्री का निरीक्षण एकक का पर्यवेक्षण। शिल्प वैज्ञानिक उसकी मात्रा, क्वालिटी तथा विजातीय पदार्थ निश्चित करने और ऐसे संप्रेषण को, समय-समय पर परिषद् द्वारा विहित रीति से अभिलिखित करेगा। अभिकरण के अधिकारी परिषद द्वारा विहित रूप में सामग्री की ओर जांच करेंगे। इस प्रक्रम में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे अभिकरण का अन्तर्निधारण पैनल विनिश्चय करेगा। अस्वीकृत सामग्री का निपटान अभिकरण को समाधान प्रद ढंग से किया जाएगा।

(4) विवाद की दशा में संबंधित कच्चा माल या तो ठीक ढंग से बर्फ में रखा जाएगा या अलग पहचान चिन्ह लगाकर प्रसंस्कृत किया जाएगा और अन्तिम निपटान के लिए अलग रखा जाएगा, जिसका विनिश्चय अभिकरण के अधिकारियों पैनल को करेगा।

(5) कच्चे माल को आगे और प्रसंस्करण जैसे धुलाई छिलका उतारना/श्रेणीकरण, विवर्णन, पकाना, भरना सीवन करना तथा रिटार्टिंग एकक के समक्ष कर्मचारियों के पर्यवेक्षण के अधीन विनिर्माण की अगली पद्धति के अनुसार किया जाएगा।

(6) प्रसंस्करण के दौरान एकक का पर्यवेक्षक। शिल्प वैज्ञानिक परिषद द्वारा विहित रूप में उत्पाद की ओर जांच करेगा। अभिकरण के अधिकारी यथा विहित रूप में सामग्री की प्रति जांच करेगा। इस प्रक्रम पर उठे किसी विवाद का विनिश्चय अभिकरण का अन्तर्निधारण पैनल करेगा। अस्वीकृत मात्रा का निपटान अभिकरण को समाधान-प्रद ढंग से किया जाएगा।

(7) योगज, यदि वे प्रयोग किये जाते हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। यदि योगज उपरोक्त अधिनियम के अधीन अनुमोदित नहीं हैं किन्तु किसी आयातकर्ता देश की विशिष्ट अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो वे अभिकरण के अनुमोदन के अधीन होंगे।

(8) लेबल पर, यदि वे प्रयोग किए जाते हैं, निम्नलिखित ब्योरा होगा, अर्थात :—

(क) प्रसंस्करण कर्ता का नाम

(ख) (ग्रामों में) जलोत्सारित भार तथा शुद्ध भार,

(ग) प्रयोग किए गए योगज की मात्रा तथा नाम.

(घ) आकार-श्रेणी, यदि कोई है।

घ. **निरीक्षण की प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरण** : (1) इन नियमों के अधीन निरीक्षणों के प्रयोजन के लिए एक दिन का उत्पादन एक नियंत्रण एकक का गठन करेगा। एक नियंत्रण एकक में, उत्पाद के प्रकारों पर निर्भर करते हुए, कई उप-एकक हो सकते हैं। वे लाट जो अभिकथित मानकों के अनुरूप होंगे, अनुमोदित लाट माने जाएंगे तथा उन्हें इस संबंध में परिषद द्वारा विहित अनुमोदि लाट रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

(2) डिब्बा बंद मछली तथा मछली से बने उत्पादों के परेषण को निर्यात करने को इच्छुक निर्यातकर्ता, परिषद द्वारा विहित प्रोफार्मा में, अभिकरण को लिखित रूप में सूचना देगा और ऐसी सूचना के साथ इस आशय की घोषणा भी करेगा कि डिब्बा बन्द मछली तथा मछली से बने उत्पाद के परेषण का प्रसंस्करण इस संबंध में विहित प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग करके किया गया है और यह अनुमोदित लाट में से लिया गया है।

(3) ऐसी सूचना प्रसंस्करण परिसर से परेषण के पोत-लदान के लिए भेजे जाने की तारीख से कम से कम चार कार्य दिवस 1 पूर्व अभिकरण के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

(4) ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण यह जानने के लिए अभिलेख से सत्यापन करेगी कि कार्टन अनुमोदित लाट में से लिए गए हैं। अभिकरण नमूने भी ले सकता है तथा इनकी जैवतात्विक विशेषताओं के लिए जांच भी कर सकता है। यदि अभिकरण का यह समाधान हो जाता है कि निर्यात किया जाने वाला परेषण अधिसूचित मानकों के अनुरूप है और यदि उपरोक्त पैरा ग(3) और ग(6) के अनुसार अभिलिखित नियमित जांचों के परिणाम समाधानप्रद हैं तो वह ऐसी सूचना प्राप्त होने के चार कार्य दिवस के भीतर परेषण को निर्यात योग्य घोषित करते हुए, निर्यातकर्ता को प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(5) यदि अभिलिखित जांच परिणामों के आधार पर ऐसा करना उचित है या अभिकरण यह समझता है कि और विस्तृत जांच आवश्यक है तो ज्यष्ठ अधिकारी द्वारा विहित रूप में परषण में से जीवाणु विज्ञान संबंधी परीक्षण सहित विस्तृत परीक्षण के लिए, अतिरिक्त नमूने लिए जायेंगे। ऐसे मामलों में, निर्यात-योग्य होने का प्रमाण-पत्र केवल परीक्षणों के समाधानप्रद रूप में पूरा होने के पश्चात् ही दिया जाएगा।

(6) जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने से इन्कार करेगा और ऐसी अस्वीकृति की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा।

(7) जो नियंत्रण एकक/उप-एकक विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें अस्वीकृति तथा उनके निपटान की पद्धति से संबंधित जानकारी देने वाला एक पृथक अभिलेख रखा जाएगा।

(8) निरीक्षण के प्रयोजन के लिए, अभिकरण के अधिकारी को, सुसंगत अभिलेखों और परिसरों तक जहां डिब्बा बंद मछली से बने उत्पाद का प्रसंस्करण पैकिंग तथा भंडारण किया जाता है, पहुंच प्राप्त होगी। प्रसंस्करणकर्ता प्रसंस्करण क्षेत्र के पार्श्व में आवश्यक सुविधाओं सहित एक पृथक कक्ष की व्यवस्था करेगा।

(9) प्रमाण के पश्चात भी, अभिकरण को परेषण की क्वालिटी जो भण्डार में अभिवहन में या पत्तनों पर है, पुनः निर्धारित करने का अधिकार होगा, मूलतः जारी किया गया प्रमाण-पत्र इनमें से किसी भी प्रक्रम पर परेषण के विनिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने की दशा में, वापस ले लिया जाएगा।

(10) विधि मान्यता :

(10) 1. लाट के अनुमोदन की तारीख से, जारी किया गया प्रमाण-पत्र 90 दिन के लिए वैध होगा।

(10)2. यदि परेषण के प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि के भीतर पोत, लदान नहीं होता तो निर्यातकर्ता पुनः विधिमान्य किए जाने के लिए परेषण प्रस्तुत कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए, निरीक्षण फीस अधिसूचित दरों पर वसूल की जाएगी तथा केवल जैवतात्विक निरीक्षण के लिए इस संबंध में विहित नमूना मापमान के अनुसार नमूने लेकर

परेषण की जांच की जाएगी ऐसे मामलो मे विधिमान्यता निरीक्षण समाप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाएगी ।

(10) 3 यदि परेषण का 10 1 मे उल्लिखित विधिमान्यता अवधि के भीतर पोत-लदान नहीं किया जाता है तो यदि अभिकरण आवश्यक समझे तो, विधिमान्यता को 7 दिन से अनधिक की अवधि के लिए तदर्थ आधार पर बढ़ा सकेगा ।

4. निरीक्षण फीस

इन नियमो के अधीन निर्यातकर्ता अभिकरण को प्रति किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए 20 पैसे की दर से निरीक्षण फीस देगा । फीस ऐसे सम्पूर्ण उत्पादन के लिए ली जाएगी जिसका अनुमोदन लाट या अन्यथा के रूप में स्वीकृति के लिए परीक्षण किया जाता है ।

5 अपील

(1) यदि किसी व्यक्ति के किसी एकक की बाबत अभिकरण पैरा (1) ख के अधीन अनुमोदन देने से या उपरोक्त पैरा घ (6) के अधीन निर्यात योग्यता का प्रमाण-पत्र जारी करने से इकार कर देता है तो ऐसे इकार से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इकार सूचना प्राप्त होने से 10 दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञो के पैनल को, जिसमे कम से कम 3 और अधिक से अधिक 7 व्यक्ति होगे, अपील कर सकेगा ।

(2) विशेषज्ञो के पैनल की कुल सदस्य सख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी ।

(4) अपील प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर निपटा दी जाएगी ।

उपाबंध-II

लवण-जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित माध्यम में या शुष्क पैक डिब्बा बंद झींगा मछली (चिगट) के लिए विनिर्देश :

1. कच्चा माल

1 1 डिब्बा बदी के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री विकृति-युक्त तथा पूर्णत. स्वच्छ होगी ।

2 डिब्बे

2 1 सामग्री को स्वच्छ स्थिति मे प्रसस्कृत किया जाएगा तथा गन्धक प्रतिरोधक रोगन से रागन किए हुए डिब्बो मे पैक किया जाएगा ।

2 2 डिब्बो मे न्यूनतम 150 मिलीमीटर स्थान निर्वात होगा ।

2 3 डिब्बे वायुरुद्ध कर दिए जाने के पश्चात्, अन्तर पैनलिंग जग लगे हुए, उभरे हुए या कालापन लिए हुए नही होगे ।

3 लवण-जल :

3 1 लवण-जल, यदि प्रयोग किया जाता है तो, साफ होगा तथा विवर्णित नही होगा ।

3 2 प्रयुक्त लवण-जल का सोडियम क्लोराइड तत्व भार मे 2 प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

4 पैकिंग तथा लेबल लगाना

4.1 एक डिब्बे मे एक ही प्रकार की सामग्री बंद की जाएगी ।

4.2 प्रयुक्त लेबल उसी देश के नियमो के अनुसार होगे जहां सामग्री निर्यात की जानी है ।

5 भार तथा आकार श्रेणी .

5 1 अन्तर्वस्तु का कुल शुद्ध भार घोषित भार से कम नही होगा ।

5 2 प्रत्येक डिब्बे की अन्तर्वस्तु का शुद्ध भार डिब्बे की कुल जलधारिता के 65 प्रतिशत से कम नही होगा ।

5 3 आकार सख्या (प्रति एकक भार मे टुकड़ो की सख्या) लेबल पर घोषित के अनुसार होगी ।

6. जैवतात्त्विक क्वालिटी :

(1) डिब्बे को खोलने पर अन्तर्वस्तु अच्छे रूप मे होगी तथा कोई विशेष विघटन प्रदर्शित नही करेगी । जिन टुकडा के भाग अलग हो चुके हैं उनको विघटित चिगट समझा जाएगा ।

(2) छूने पर झींगा मछली की सतह चिपचिपी नही दिखाई देगी । मांस नरम किन्तु सुदृढ़ होगा तथा उन उंगलियो के बीच दबाई जने पर दानो के रूप मे टुकड़े-टुकड़े नही होगी ।

(3) झींगा मछली के टुकड़े परस्पर बंधे हुए प्रतीत नही होगे तथा टुकड़ों को आसानी से अलग करना सभव होना चाहिए । टुकड़े एक ही आकार के होगे तथा साफ होगे तथा मांस के ढीले लटकते हुए टुकडो से मुक्त होगे ।

(4) सामग्री मे ताजी पकाई हुई झींगा मछली के मांस का स्वाद तथा सुगन्ध होगी तथा तीखे कड़वे या अन्य किसी आपत्तिजनक स्वाद से मुक्त होगी ।

(5) सामग्री प्रसस्करण पूर्व विकृति दर्शाते हुए हरापन लिए हुए पीले पुट वाली पीले विरंजित वर्ण से मुक्त होगी सामग्री काले रंग के धब्बे से भी उक्त होगी ।

(6) सामग्री, रेत, धूल, कीटाणु, बाल तथा अन्य किसी बाहरी पदार्थ से मुक्त होगी । यह शिरा के सीप के कणो तथा उपांग के टुकडो से मुक्त होगी ।

(7) सामग्री किसी विषैली तथा हानिकारक तत्वो से मुक्त होगी ।

(8) डिब्बे खोलने पर कोई जीवाणु दूषण की गंध नहीं आनी चाहिए, अन्तर्वस्तु का द्रवण प्रकट नही होना चाहिए तथा कालापन प्रकट नही होना चाहिए ।

7 जीवाणु क्रिया

7 1 डिब्बे की अन्तर्वस्तु मे 37 सें०ग्रे० के उष्मायन पर थियो ग्लाइकोल्सेट सिटाईन शोरबे मे संचारण तथा 48 घंटे के लिए कोई जीवाणु वृद्धि प्रकट नहीं होनी चाहिए । सचारण के पहले डिब्बे सात दिन के लिए 37 सें०ग्रे० पर उष्मायित किए जायेंगे ।

8 कोड :

8 1 डिब्बो पर आकार श्रेणी, शुद्ध भार, विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का कोड तथा विनिर्माण का वर्ष, मास, बैच तथा दूसरी ओर उत्पादन करने वाले देश को सूचित करने के 'भारतीय' चिन्ह अकित किए जायेंगे । सक्षिप्त रूप मे कोड चिन्हित करने के लिए एक दृष्टांत नीचे दिया गया है,—

टी 5

8 बी 05

उपरोक्त दृष्टान्त मे,—

टी 5 से, शुद्ध भार 5 औंस में पैक किया गया 'टिनी' अभिप्रेत है । X से अभिप्रेत है विनिर्माता का सक्षिप्त रूप मे नाम या कारखाने का कोड '8' से विनिर्माण का वर्ष अभिप्रेत है तथा इस उदाहरण मे, यह वर्ष 1978 सूचित करता है । 'बी' से विनिर्माण का मास अभिप्रेत है (यहां फरवरी मास अभिप्रेत है) तथा '05' से मास मे विनिर्माण की तारीख वर्णित होती है ।

आकार श्रेणी तथा शुद्ध भार प्रकट करने के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित नाम पद्धति का पालन किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) आकार श्रेणी

नाम पद्धति	काउंट 100 ग्राम	संक्षेपाक्षर
कोलोसल सुप्रीम जुम्बो	8 से कम	ग/घ
जुम्बो	9 से 13	ञ
बड़ा	14 से 22	ठ
मध्यम	23 से 36	ड
छोटा	37 से 63	ढ
टिनी	64 से 102	ण
काकटेल/मिनी/सलाद	103 से ऊपर	ग ण/ड झ घ ध
टूटन/समस्त टूटन	कोई सीमा नहीं	ख/ब ख

+ डिब्बे में कुल टुकड़ों की संख्या का ध्यान रखे बिना, भार के हिसाब से ऐसे पैक को जिसमें, टूटे हुए टुकड़े 10 प्रतिशत से अधिक हैं, टूटा हुआ समझा जाएगा।

(ख) शुद्ध भार

4.5 औंस वाले पैक को छोड़कर जो मापक पैक समझा जाता है, डिब्बे पर *वास्तविक शुद्ध भार औंसों में अंकित किया जाएगा।* विनिर्माण का मास निम्न रूप में लिखा जाएगा, अर्थात् :—

मास	संक्षेपाक्षर
जनवरी	क
फरवरी	ख
मार्च	ग
अप्रैल	घ
मई	ङ
जून	च
जुलाई	छ
अगस्त	छः
सितम्बर	झ
अक्तूबर	ट
नवम्बर	ठ
दिसम्बर	ड

2. लवण-जल में या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अनुमोदित माध्यम में डिब्बा बन्द केकड़े के मांस के लिए विनिर्देश

1. कच्ची सामग्री :

1.1. डिब्बे में बंद करने के लिए प्रयोग किया गया मांस खाद्य वर्ग के स्वस्थ, तुरन्त पकड़े हुए जीवित केकड़े जैसे सेयल्ला सिरेटा, प्रोटोनस पालाजिक्स इत्यादि से प्राप्त किया जाएगा।

2. डिब्बे :

2.1. केकड़े का मांस स्वस्थकर व्यवस्था में प्रसंस्कृत किया जाएगा तथा गन्धक रोधक से रोगन किए हुए डिब्बों में भली भांति पैक किया किया जाएगा।

2.2. डिब्बों में न्यूनतम 150 मिलीमीटर निर्वात स्थान होगा।

2.3. डिब्बे वायुरुद्ध बंद कर दिए जाने के पश्चात् क्षरित, पेर्नालिग, अंग लगे हुए या उभरे हुए नहीं होंगे।

3. लवण-जल :

3.1. प्रयुक्त लवण-जल का सोडियम क्लोराइड तत्व भार में 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

4. पैकिंग तथा लेबल लगाना :

4.1. क्रेता तथा विक्रेता के मध्य स्वीकृत संविदा की शर्तों के अनुसार केकड़े के धड़ तथा पंजे का मांस पैक किया जाएगा। संविदात्मक विनिर्देशों के न होने पर, पंजे का मांस स्पष्टतया अलग तहों में ऊपर या नीचे पैक किया जाएगा।

4.2. एक डिब्बे में एक ही जाति के केकड़े का मांस पैक किया जाएगा।

5. शुद्ध भार :

5.1. प्रत्येक डिब्बे की अन्तर्वस्तु का शुद्ध भार डिब्बे की कुल जल धारिता के 65 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

6. जैवतात्विक क्वालिटी :

6.1. डिब्बे को खोलने पर अन्तर्वस्तु से केकड़े के *मांस का विशिष्ट* रंग तथा सुगंध प्रकट होनी चाहिए तथा उससे कोई बाह्य गंध नहीं आनी चाहिए।

6.2. सामग्री में ताजे पकाए हुए केकड़े के मांस की विशिष्ट गंध होनी चाहिए तथा केकड़े के मांस के अतिरिक्त अन्य बाह्य वस्तु उसमें नहीं होनी चाहिए।

6.3. मांस का रंग नीलापन लिए हुए नहीं होगा।

6.4. डिब्बे में रखी गई वस्तु से स्रवण का कोई चिन्ह प्रकट नहीं होना चाहिए।

7. जीवाणु क्रिया :

7.1. डिब्बे की अन्तर्वस्तु में थियोग्लाइकोलेट सिसटाइन शोरबे में संचारण तथा 48 घंटे के लिए 37 सें०ग्रे० के *उष्मायन* पर, कोई जीवाणु वृद्धि प्रकट नहीं होनी चाहिए। संचारण के पहले डिब्बे सात दिन के लिए 37 सें०ग्रे० पर उष्मायित किए जायेंगे।

8. संकेतन :

8.1. डिब्बों पर शुद्ध भार का चिन्ह, विनिर्माता का नाम या उसकी फैक्टरी का चिन्ह तथा विनिर्माण का वर्ष, महीना तथा तारीख अलंकृत किए जायेंगे। संकेत चिन्ह को अलंकृत करने के लिए *दृष्टान्त का संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है।*

सी बी 5 ×

8 बी 0 5

उपरोक्त दृष्टान्त में,—

सी बी लवण—जल में डिब्बा बन्द केकड़े का मांस सूचित करता है।

5 शुद्ध भार सूचित करता है तथा इस दृष्टान्त में यह 5 औंस शुद्ध भार सूचित करता है।

×, संक्षिप्त रूप में विनिर्माता का नाम या उसके कारखाने का कोड सूचित करता है।

8, विनिर्माण का वर्ष सूचित करता है तथा यहां यह वर्ष 1978 सूचित करता है।

बी, विनिर्माण का मास सूचित करता है तथा यहां यह फरवरी मास सूचित करता है।

05. मास के दौरान विनिर्माण की तारीख सूचित करता है।

विनिर्माण के मास निम्न रूप में दिए जायेंगे, अर्थात :—

मास	संकेताक्षर
जनवरी	क
फरवरी	ख
मार्च	ग
अप्रैल	घ
मई	ङ
जून	च
जुलाई	छ
अगस्त	ज
सितम्बर	झ
अक्तूबर	ञ
नवम्बर	ट
दिसम्बर	ठ

[सं० 8(11)/78-नि०नि० तथा नि०ख०]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 29th September, 1979

S.O. 3318.—Whereas, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that canned fish and fishery products should be subjected to quality control and inspection prior to export;

As whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by Sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964,

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule, the Central Government in partial supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 771 dated the 6th March, 1965 in so far as it relates to prawns (shrimps) canned in brine or dry pack, and S.O. No. 455 dated 5th February, 1977 relating to canned crab meat, hereby publishes the said proposals for information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within 45 days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, 'World Trade Centre', 14/1B, Ezra Street (7th Floor), Calcutta-700001.

Proposals

(1) To notify that canned fish and fishery products shall be subject to quality control and inspection prior to export;

(2) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1979 as set out in Annexure-I to this Order as the type of inspection which shall be applied to such canned fish and fishery products prior to their export;

(3) To recognise the specifications as set out in Annexure-II to this order as the standard specifications for canned fish and fishery products;

(4) To prohibit the export of such canned fish and fishery products in the international trade unless the same are accompanied by a certificate of inspection issued by an Agency recognised by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 to the effect that such canned fish and fishery products conform to the standard specifications and are exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of samples of canned fish and fishery products to prospective buyers, the value of which does not exceed Rs. 250.

4. In this order, canned fish and fishery products shall mean the following fishery products packed in hermatically sealed containers, namely:

I. all types of prawns (shrimps) canned in brine or in other internationally approved medium or dry pack.

II. Crab meat canned in brine or any other internationally approved medium the meat having been obtained from edible crabs like scylla serrata, protonus palaqicus.

ANNEXURE I

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) in partial supersession of the Export of Fish and Fishery Products (Inspection) Rules, 1964 in so far as it relates to prawns (Shrimps) canned in brine or drypack and the Export of Canned Crab Meat (Inspection) Rules, 1977.

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Export of Canned Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) 'Act' means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) 'agency' means any one of the Export Inspection Agencies established under section 7 of the Act at Bombay, Calcutta Cochin, Delhi and Madras;

(c) 'council' means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act.

(d) 'canned fish and fishery products' means:—

I. all types of prawns (shrimps) canned in brine or in any other internationally approved medium or dry packed.

II. Crab meat canned in brine or any other internationally approved medium from meat of edible crabs like scylla serrata, protonus palaqicus.

(a) 'standard specifications' means the specifications in respect of prawns/shrimps canned in brine or any other internationally approved medium or dry pack, crab meat canned in brine or any other internationally approved medium.

3. Quality Control:

A. **Requirements of processing units.**—Only processing units approved by the Agency shall be eligible to process canned fish and fishery products for export. Such an approval will be granted only to those units having the minimum facilities as prescribed below which shall be adjudged by a panel of experts constituted by the Export Inspection Council of India.

(1) Surroundings, construction and lay out :

Canneries and surrounding area should be such as can be kept reasonably free of objectionable odours, smoke, dust or other contamination. The surroundings of canning units shall not have any swamps, dumps or animal housing nearby which might pose any sanitary problem. All the immediate approaches

of the processing area which are under the physical control of the processor shall be concreted, tarred or turfed so that the cannery can be kept reasonably free of dust or other contamination. The building should be adequate in size to avoid crowding of equipments or personnel, well constructed and kept in good repair. They should be of such design and construction as to protect against the entry and harbourage of insects, birds or other vermin and to permit easy and adequate cleaning.

The processing unit shall be housed in a building of permanent nature affording sufficient protection from normal climatic hazards like wind-blown dust and rain. The lay-out of different sections shall be such as to facilitate the smooth flow of work and to prevent possible contamination from pre-processing section.

(2) Processing areas :

The area in which the raw material is received and stored shall be separated from the area where the final product is prepared or packed in such a manner as to eliminate bacteriological contamination of the finished product. Areas and compartments used for the storage of edible products shall be separate and distinct from those used for the storage of inedible materials. The food handling area shall be completely separted from the area used for residential purposes.

(3) Ceiling, wall and floor :

Ceiling should be designed and constructed to prevent accumulation of dirt, condensation of steam, harbourage of rodents and should be easy to clean. Ceiling should be at least 3 metres (10 ft.) in height, free of cracks and open joints and should be of a smooth, water-proof and light coloured finish.

Internal walls of the cannery should be smooth, water-proof, free of pits and cracks, light coloured and easily washable upto a minimum height of 1.5 metres (5 feet). Wall to wall and wall to floor junctions may be rounded to facilitate cleaning. Walls should be free from projections and all pipes and cables should be neatly covered.

The floors should be constructed of durable water-proof, non-toxic, non-absorbent and non-corroding material which is easy to clean and disinfect. They should be nonslip and without crevices and should slope evenly and sufficiently to drain of water.

(4) Fly-proofing, vermin and animal control :

The processing area shall be provided with effective fly-proofing arrangements and other suitable step shall also be taken to prevent entry of other insects, rodents, birds, cats, dogs etc. into the processing areas.

(5) Lighting and ventilation :

All the working areas shall be well lighted. Light bulbs and fixtures should not be directly suspended over the processing table or at any stage of the preparation of the product. These shall be so safety type to prevent contamination in the event of breakage. The premises should be well ventilated to prevent excessive heat, condensation and contamination with obnoxious odours, dust, vapour or smoke. Special attention should be given to the venting of areas and equipmen's producing excessive heat, steam, obnoxious fumes, vapours or contaminating aresols by providing natural or mechanical ventilation. Ventilation openings should be screened and if required, equipped with proper air filters. Windows which open for ventilation purposes should also be screened. The screens should be made easily removable for cleaning and should be made from suitable corrosion-resistent material.

(6) Working tables and utensils :

All working tables, work surfaces, containers, trays, tanks or other utensils used during the processing of canned fishery products shall be of smooth, impervious, non-toxic material which shall be corrosion-resistent and shall be so designed and constructed as to prevent hygienic hazards and permit easy and thorough cleaning. All food contact surfaces should be smooth, free from pits, crevices, substances harmful to man, and they should be capable of withstanding repeated cleaning and disinfection. Containers used for holding fishery products shall preferably be made of plastic or corrosion-resistent material. Bamboo baskets, wicker baskets, enamelled utensils shall not be used in the processing area. The table top shall be of stainless steel or aluminium and shall be smooth and free from pits and crevices. Working tables shall be so arranged as to permit smooth flow of work and easy cleaning of the area underneath and around them.

Material washing tanks should be so designed as to provide a constant change of water with good circulation and to have provisions for drainage and easy cleaning. Utensils used for inedible or contaminated materials should be identified as such and should not be used for handling edible products. Adequate waste receptacles shall be provided for the frequent removal of waste material from the working areas during processing operations.

(7) Equipments and machinery :

Machineries and equipments shall be so designed that they could be easily dismantled to facilitate thorough cleaning and disinfection. Stationery equipments shall be installed in such a manner as will permit easy access and thorough cleaning and disinfection. Every cannery shall be equipped with the following equipments and machinery in sufficient numbers :

(i) seaming machines of semi-automatic or automatic type maintained in good working condition ;

(ii) reports equipped with (a) thermometer, (b) pressure gauge, (c) seam spreader, (d) venting valves and (e) safety valves ;

(iii) exhausting chamber with conveyor system ;

(iv) standard weighing machines and weights ;

(v) blanching tanks and related utensils made of stainless steel ;

(vi) code embossing machines capable of embossing minimum of 7 digits in a line ;

(vii) cooling tanks fitted with automatic chlorination device ;

(viii) boiler and accessories of suitable type and capacity to supply steam for all normal operations at a time ; and all steam-carrying-pipes properly insulated ;

(ix) testing facilities to conduct routine tests such as seaming defects, pH, salinity, sterility, vacuum available chlorine etc., and

(x) mechanical lifting equipments to handle crates containing processed cans.

(8) Storage and warehousing :

The canning units shall have facilities for warehousing the canned products separately. The warehouse shall be of adequate capacity and shall be such that the stored products can be kept dry and non-exposed to extremes of temperatures. This shall also be sufficiently protected from dampness and maintained at a high level of sanitation and hygiene.

All detergents and disinfectants shall be stored separately. There shall be separate facility for storing, packaging materials. Toxic substances such as rodenticides, fumigants, insecticides or other substances injurious to health except fire fighting equipments, shall be kept in a seperate locked room. All these substances and equipment shall be handled by trained personnel only.

(9) Water and Ice :

There shall be plentiful of potable water (properties of which shall be in accordance with the requirements contained in the World Health Organisation "International Standard for Drinking Water") supply with in-line chlorination system allowing the residual chlorine content of the water to be varied at will in order to reduce multiplication of micro-organisms. Water used for washing raw materials should not be re-circulated unless it is re-stored to a level

of potable quality. If the water used for processing is from sources other than protected water supplies, a certificate of potability of the same from the Agency or institutions approved by the Agency shall be produced. If non-potable water is supplied for boiler and other auxiliary services, there shall be no cross-connection between the auxiliary water system and the system carrying potable water. If the water used is from a storage tank, the tank shall be of sufficient capacity and shall be protected from extraneous contamination. The storage tank shall be cleaned at least once in six months. The minimum available chlorine content in water used for processing shall be maintained at 3 ppm level.

Ice shall be made from potable water and shall be manufactured, handled and stored so as to protect it from contamination. If ice used is from external sources, it shall be ensured that the same is made from potable water and is not contaminated. Ice crushing machines, if used, shall be kept in good sanitary conditions. A special room or other suitable storage facilities should be provided to protect the ice from contamination and excessive meltage.

(10) Sanitary facilities and control :

(i) Cleaning and washing of containers.—Each and every container must be inspected carefully to ensure that it is undamaged and without feasible flaws. These containers shall also be cleaned thoroughly using potable water (preferably hot) containing 10 ppm available chlorine before they are used for packing fishery products.

(ii) Washing and disinfection of working tables, trays, utensils and equipments.—Necessary facilities shall be provided for cleaning and disinfection of working tables, trays, utensils, cutting boards, containers equipments and working implements which are used during processing. Utensils, trays and table tops which come in contact with unpacked material shall be washed initially with a suitable cleaning agent and finally with water containing 50 ppm available chlorine. Such cleaning and washing should be done as often as necessary. It will be ideal to have all such cleaning and washing facilities in a separate room where there should be an adequate supply of hot and cold potable water preferably under good pressure and where there should be proper drainage facilities.

(iii) Washing of the floor.—The processing hall shall be cleaned before the day's work starts and then in the end of each working shift. In addition, the cleaning and washing shall be done as frequently as necessary.

(iv) Sewage and waste disposal.—There shall be suitable and adequate drainage facilities for the removal of liquid or semi-liquid wastes from the plant. There shall not be any floor area where water may collect and stagnate. Drains should be constructed of smooth and impervious material and should be designed to cope with the maximum flow of liquid without any overflowing and flooding. The drainage lines carrying waste affluent except for open drains should be properly vented and if required, run to a catch-basin for removal of the solid waste material. Such a basin should be located outside the processing area and should be constructed of water-poof concrete or other similar material. The openings of open drains, if any, which pass through walls shall be fitted with metal grills to prevent the entry of rodents.

The arrangements for disposal of sewage waste water and offal shall be done as quick as possible and shall be such that it shall not cause any sanitary problem to the neighbourhood. The sewage from the toilet shall be disposed of in such a manner that the same shall not be accessible to flies and shall not contaminate the unit's water supply. On no account shall there be accumulation of waste or water of any kind in the premises.

(v) Exclusion of dogs, and animals from factory premises.—As dogs, cats and other animals are potential carriers of disease, they shall not be allowed to enter or to live in or nearby the processing premises.

(vi) Toilet facility.—Adequate toilet facilities of sanitary type shall be provided as per the legal requirements applicable in this regard. The toilets shall be well lit and shall be well isolated from the processing area. The toilets shall be provided with self-closing doors, and with wash basins and soap. Potable water shall be used for washing purposes.

(11) Personal health and hygiene :

Plant management shall take care to ensure that no person who is either carrier of, or known to be affected with, a communicable disease, is permitted to work in any area of the unit. In order to facilitate the detection of such disease, the management shall conduct at least yearly medical examination of the personnel permitted to work in any area of the unit.

All persons working in a cannery shall maintain a high degree of personal cleanliness while on duty and shall take all precautions to prevent contamination of fishery products with any foreign substance. The management shall provide clean aprons and headgears to all employees according to the nature of their work. Gloves used in handling of fishery products shall be maintained in clean and sanitised condition and shall be made of impermiable material, except where their use would be incompatible with the work involved. Workers shall wash their hands thoroughly with soap or other cleaning agent, and warm water before commencing each day's work, and on every occasion after visiting a toilet before resuming work, and also on other occations wherever necessary. Workers shall also wash their feet with potable water and soap wherever necessary especially before entering into, and after each absence from the processing hall. By no means, the wearing of gloves shall exempt the workers from the necessity to thoroughly washing their hands.

Any behaviour which can potentially contaminate the product during handling and processing, such as eating, smoking, chewing tobacco or other materials, spitting etc., shall be strictly prohibited in any part of the handling and processing areas. Where workers of both sex are employed, separate toilet facilities, lunch rooms, changing rooms, and rest rooms shall be provided. As a general guide, lunch rooms should provide sitting accommodation for all employees and the changing rooms should provide enough space for lockers for each employee without causing undue congestion.

Clothing and footwear not worn during working hours must not be kept in any processing area.

(12) Transportation facilities :

The raw material shall be transported only in insulated/refrigerated conveyances. Such conveyances should be cleaned and disinfected immediately after each use and should be so maintained as not to constitute a source of contamination of the product.

No person known to be suffering from any communicable diseases or who has an infected wound or open lesion, shall be engaged in the transportation of fishery products.

Cleaning of the conveyances together with the necessary receptacles and equipments, shall be done on a routine basis. Hosing, scrubbing and cleaning with potable water or clean sea water to which a suitable detergent or disinfectant has been added, are necessary

(13) Maintenance of records :

Necessary registers and records as prescribed by the Council from time to time shall be maintained by the processor in order to ensure effective control on the processing of canned fish and fishery products, and these shall be made available to the Agency officers as and when required.

B. **Approval of Processing Units.**—(1) A processor intending to process canned fish and fishery products for export shall inform his intention to do so in writing, in the proforma prescribed by the Council, to the nearest office of the Agency. On receipt of such intimation, the Agency officers shall visit the processing unit in order to adjudge the facilities for processing available in the unit. If the unit is found to have the minimum facilities as prescribed in these rules, a Panel of Experts constituted for this purpose by the Council, shall adjudge the adequacy of the facilities in the unit and recommend its approval/disapproval to the Agency for further necessary action. Within fifteen days of receiving the recommendation of the Panel, the Agency shall either approve the unit and

permit it to carry out processing of canned fish and fishery products for export, or disapprove the same and shall not allow the processor to process canned fish and fishery products for export.

(2) The approval so accorded shall be communicated to the processor in writing by the Agency. In case the unit is disapproved, it shall be communicated to the processor in writing pointing out the deficiencies recorded by the Panel.

2.1 A processor, after rectifying such deficiencies, shall submit a fresh application to the Agency along with a detailed report on rectification of the deficiencies carried out by him. On receipt of this application, the Agency shall take the steps detailed in paras (1) and (2) above.

3. For the following reasons, the approval accorded shall be withdrawn by giving a notice to the concerned processor after 7 days from the date of receipt of the notice.

(i) If the equipments, machinery and storage facilities are not in good working condition;

(ii) If the sanitary and hygienic condition of the unit is not satisfactory;

(iii) If samples drawn for counter-checks fail to meet the laiddown standards;

(iv) If the processor has violated/deliberately attempted to violate the provisions of the notification or instructions issued from time to time.

(4) Such withdrawal of approval shall be intimated in writing to the processor.

(5) (i) If the processor is aggrived by the decision to withdraw approval, he may file an appeal before the Appellate Panel. In such cases, he shall be allowed to continue processing.

(ii) In the event of an adverse decision by the Appellate Panel, the processor shall not be allowed to export the material processed during the intervening period.

(6) A unit whose approval has been withdrawn, may, after rectifying the defects, make a fresh application to the Agency for getting fresh approval.

(7) For reasons given at 3(i), 3(ii), 3(iii) and 3(v) above, if, at any time, there is any difficulty in maintaining conformity of the products to the specifications, or if directed by the Agency to suspend production for export, the processor shall suspend production for export under intimation to the Agency The processing for export shall be resumed only after the same is approved by the Agency in writing

C. **Processing.**—(1) The processor shall carry out processing only in approved units under the supervision of competent technical personnel.

(2) Only such raw material, which are fresh, clean, wholesome, having the characteristic appearance, odour, colour and texture of species, shall be accepted for processing.

(3) The raw material arriving in the processing unit shall be inspected by the supervisor/technologist of the unit for its quantity, quality and foreign matter, and the observations recorded in the manner as prescribed by the Council, for this purpose from time to time.

The material shall be subjected to further checks by the Agency officers as may be prescribed by the Council. In the event of any dispute arising at this stage the matter shall be decided by an internal assessment panel of the Agency. The rejected material shall be disposed of in a way satisfactory to the Agency.

(4) In case of dispute, the concerned raw material shall be either kept adequately iced/or processed with a separate identity mark and kept separately for final disposal which shall be decided by a panel of officers of the Agency.

(5) Further processing of the raw material like washing, peeling, grading, blanching, cooking, filling, seaming and retorting, shall be carried out observing good manufacturing practices under the supervision of a competent personnel of the unit.

(6) During the processing, the supervisor/technologist of the unit shall check the product as may be prescribed by the Council in this behalf. The material will be counter-checked by the Agency officer as may be prescribed. In the event of any dispute arising at this stage, the matter shall be decided by an internal assessment panel of the Agency. The rejected material shall be disposed of in a way satisfactory to the Agency.

(7) Additives, if any used, shall conform to the requirements of 'Prevention of Food Adulteration Act, 1955'. If additives not approved under the above Act are used to meet the specific requirement of any importing country the same shall be subject to approval by the Agency.

(8) Label, if used, shall bear the following details;

(a) Name of processor;

(b) Net weight and drained weight in grams;

(c) Quantity and name of additives used;

(d) Size-grade, if any.

D. **Procedure of Inspection and Certification.**—(1) For the purpose of inspection under these rules, a day's production shall constitute a control unit. A control unit may have more sub-units depending upon the species of the product. Those of the lots which meet with the laid down standard will be treated as approved lots and shall be entered in the register for approved lots, as may be prescribed by the council in this behalf.

(2) An exporter intending to export a consignment of canned fish and fishery products shall give intimation to the Agency in writing in the proforma prescribed by the Council, and submit along with such intimation a declaration to the effect that the consignment of canned fish and fishery products has been processed exercising the inprocess quality control measures as prescribed in this regard, and is from approved lot

(3) Such intimation shall reach the Agency office not less than four working days prior to the date of despatch of the consignment from the processing premises for shipment.

(4) On receipt of such intimation, the Agency shall verify with the records to ascertain that the cartons are from the approved lots. The Agency may also draw samples and examine these for organoleptic characteristics. If the Agency is satisfied that the consignment to be exported complies with the notified standards, and if the results of recorded regular checks conducted as per para C(3) and C(6) above are satisfactory, it shall, within 4 working days of receipt of such intimation, issued a certificate to the exporter declaring the consignment exportworthy.

(5) In case the results of the recorded checks so warrant, or if the Agency feels that further detailed checks are necessary, additional samples as decided by a senior officer, shall be drawn from the consignment for detailed testing including bacteriology. In such cases, the certificate of exportworthiness shall be issued only after satisfactory completion of these tests

(6) Where the Agency is not so satisfied, it shall refuse to issue such certificate and communicate such refusal in writing to the exporter along with the reasons therefor.

(7) A separate record shall be maintained giving information relating to the rejection and mode of disposal of the control units/sub-units which do not conform to the specifications.

(8) For the purposes of inspection, the Agency officer shall have access to the relevant records and premises where processing, packing and storage of canned fish and fishery products are carried out. The processor shall provide a separate inspection room with necessary facilities adjacent to the processing area.

(9) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment in the storage, in transit or at the ports. In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate originally issued shall be withdrawn.

(10) Validity :

10.1. The certificate issued shall be valid for 90 days from the date of approval of the lot. If more than one lot approved on different days are presented in one application, the validity of the certificate shall be reckoned from the earliest date of approval.

10.2. If the consignments are not shipped within the period of validity of the certificate, the exporter shall be permitted to present the consignment for re-validation. For this purpose, the inspection fee at the notified rates shall be charged and the consignment shall be examined by drawing samples as per the sampling scale prescribed by the Council in this behalf, for organoleptic inspection only. In such cases, the validity shall be extended for a further period of 30 days from the date of completion of inspection.

10.3. For a consignment not shipped within the validity period mentioned in 10.1, an ad hoc extension of validity for a period not more than 7 days may be granted by the Agency, if found necessary.

4. INSPECTION FEE

A fee at the rate of 20 paise per kg. or part thereof, shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules. The fee shall be charged for the entire production tested to judge for its acceptance as approved lot or otherwise.

5. APPEAL

(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to accord approval for his unit under para B(1) above, or to issue a certificate of exportworthiness under para d(6) above, may, within 10 days of receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a Panel of Experts consisting of not less than 3, but not more than 7 persons, appointed for the purpose by the Central Government.

(2) At least two-thirds of the total membership of the Panel of Experts shall consist of non-officials.

(3) The quorum of the Panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE II

SPECIFICATIONS FOR PRAWNS (SHRIMPS) CANNED IN BRINE OR IN ANY OTHER INTERNATIONALLY APPROVED MEDIUM OR DRY PACK

1. Raw material :

1.1 The material used for canning shall be free from spoilage and shall be well cleaned.

2. Cans :

2.1 The material shall be processed under hygienic conditions and shall be packed in well lacquered cans with sulphur resistant lacquer.

2.2 The cans shall have a minimum vacuum of 150 mm.

2.3 The cans after sealing hermatically shall not show flipper, panalling, rusting, swellign or blackening.

3. Brine :

3.1 The brine, if used, shall be clear and shall not be discoloured.

3.2 The sodium chloride content of the brine, if used, shall not exceed 2 per cent by weight.

4. Packing and labelling :

4.1 Only material of the same species shall be packed in a can.

4.2 The labels, if used, shall be according to the rules of the country where the material is to be exported.

5. Drained weight and size grade :

5.1 The net drained weight of contents shall not be less than the declared weight.

5.2 The drained weight of the contents of each can shall not be less than 65 per cent of the nett water capacity of the can.

5.3 The size count (number of pieces per unit weight) shall conform to that declared on the label.

6. Organoleptic quality.

(1) The contents of the can on opening shall present a good appearance and shall not display any appreciable disintegration. Pieces from which portions have separated out would be treated as disintegrated shrimp.

(2) The surface of the prawns shall not appear slimy to the touch. The meat shall be soft but firm and shall not crumble to granular from when pressed between fore-fingers.

(3) The prawn pieces shall not appear to be pressed together and it should be possible to separate the pieces easily The pieces shall be of uniform size and shall be clean and free from loose hanging pieces of meat.

(4) The material shall have the odour and flavour of fresh cooked prawn meat and shall be free from scorched, bitter or any other objectionable flavour.

(5) The material shall be free from pale bleached colour with a greenish yellow tint indicative of pre-processed spoilage. The material shall also be free from any black discolouration.

(6) The material shall be free from sand, dirt, insect, hair or any other extraneous matter It shall be free from bits of veins, shell particles and pieces of appandages.

(7) The material shall be free from any poisonous and deleterious substances.

(8) The cans on opening shall not give any odour indicative of bacterial spoilage, shall not show liquafaction of contents, and shall not show blackening.

7. Bacteriological activity :

7.1 The contents of the can on inoculation into thioglycollate cystine broth and incubation at 37°C for 48 hours shall not show bacterial growth. Before inoculation, the cans shall be incubated at 37°C for 7 days.

8 Coding :

8.1 The cans shall be embossed with the markings of size-grade, drained weight, name of the manufacturer or his factory code, year, month and batch of manufacturer, and the word INDIA on the other side to indicate the country of produce. An illustration for embossing the code in the abbreviated form is given below :—

T5X

8B05

Where, in the above illustration : T5 stands for 'Tiny' packed with 5 oz. drained weight, 'X' stands for the name of the manufacturer in the abbreviated form or the factory code, '8' stands for the year of manufacture, and in this illustration it signifies the year 1978, 'B' stands for the month of manufacture (here it signifies the month of February), and '05' stands for the date of manufacture during the month.

For the purpose of denoting the size, grade and the drained weight, the following nomenclature shall be followed :—

(a) Size-grade*

Nomenclature	Count/100 gms.	Abbreviation
Coloseal/Supreme Jumbo	Below 8	C/SJ
Jumbo	9 to 13	J
Large	14 to 22	L
Medium	23 to 36	M
Small	37 to 63	S
Tiny	64 to 102	T
Cocktail/Mini/Salad	103 and above	CT/MI/SD
Broken/Whole & Broken	No limit	B/WB

*Any pack having more than 10 per cent broken pieces by weight irrespective of the total number of pieces in the can shall be treated as 'Broken'.

(b) Drained weight

Except in the case of 4 5 oz pack, which being the standard pack the actual drained weight shall be embossed in oz on the cans The month of manufacture shall be designated as—

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	I
October	K
November	L
December	M

2 SPECIFICATIONS FOR CRAB MEAT, CANNED IN BRINE OR ANY OTHER INTERNATIONALLY APPROVED MEDIUM

1 Raw material

1 1 The meat used for canning shall be obtained from healthy, freshly caught, live crabs of the edible species only such as Seylla Serrata, Protonus palaqicus, etc

2 Cans :

2 1 The crab meat shall be processed under hygienic conditions and shall be packed in well lacquered cans with sulphur-resistant lacquer

2 2 The cans shall have a minimum vacuum of 150 mm

2 3 The cans after sealing hermatically shall not show flipper, panalling, rusting or swelling

3 Brine

3 1 The sodium chlorine content of the brine, if used, shall not exceed 2 per cent by weight

4 Packing and labelling

4 1 The body meat and claw meat of the crab shall be packed according to the terms of contract agreed upon between the buyer and the seller

In the absence of contractual specifications, the claw meat shall be packed on the top or at the bottom in distinctly separate layers

4 2 Only the meat of one species of crab shall be packed in a can

5 Drained weight

5 1 The drained weight of the contents of each can shall not be less than 65 per cent of the nett water capacity of the can

5 2 The drained weight of the meat shall not be less than the declared weight

6 Organoleptic quality

6 1 The contents of can on opening shall present a characteristic colour and odour of crab meat and shall not display any foreign odur

6 2 The material shall be free from any flavour other than the characteristic flavour of freshly cooked crab meat and any foreign material other than crab meat

6 3 The colour of the meat shall not be bluish

6 4 The contents of the can shall not show any signs of liquefaction

7 Bacteriological activity :

7 1 The contents of the cans on inoculation into thioglycollate cystine broth and incubation at 37 degree C for 48 hours shall not show any sign of bacterial growth Before incubation, the cans shall be incubated at 37 degree C for 7 days

8 Coding

8 1 The cans shall be embossed with the markings of the drained weight, name of the manufacturer or his factory code, and year, month and date of manufacture An illustration for embossing the code in the abbreviated form is given below

CB5X

8B05

Where in the above illustration —

CB stands for crab meat canned in brine,

5 stands for drained weight and in this illustration it signifies 5 oz drained weight

X stands for the name of the manufacturer in the abbreviated form or his factory code,

8 stands for the year of the manufacture and in this illustration it signifies the year, 1978

B stands for the month of manufacture and in this illustration it signifies the month of February,

05 stands for the date of manufacture during the month

The months of manufacture shall be designated as—

Month	Abbreviation
January	A
February	B
March	C
April	D
May	E
June	F
July	G
August	H
September	J
October	K
November	L
December	M

[No 6(11)/78-EI&EP]

आदेश

का०आ० 3319.—भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये खाने तथा औषधीय प्रयोग के लिये बनाये गये गम कराया (कतीरा) का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण किये जाने के लिये, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2453 तारीख 12 अगस्त, 1966 को अधिक्रान्त करते हुए कतिपय प्रस्तावों की अधिसूचना निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम 2 की अपेक्षानुसार भारत सरकार में वाणिज्य मंत्रालय के आदेश तारीख 30 सितम्बर, 1978 के अधीन भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी ।

2 और उन सभी लोगों से, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना थी, उस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्ति तथा सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 9 अक्तूबर, 1978 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अब अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2453 तारीख 12 अगस्त, 1966 का अधिक्रमण करते हुए, तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ।

(1) अधिसूचित करती है कि औषधीय तथा खाने के प्रयोग के लिये बनाये गये गम कराया (कतीरा) का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण किया जायेगा,

(2) गम कराया निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1978 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण का वह प्रकार विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे गम कराया को निर्यात से पूर्व लागू होगा;

(3) इस आदेश के उपाबन्ध में दिये गये विनिर्देशों को गम कराया के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देती है;

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसे किसी भी गम कराया (कतीरा) के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करती है जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि ऐसा गम कराया (कतीरा) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है ।

3. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को भूमि, जल या वायु मार्ग द्वारा गम कराया (कतीरा) के नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होंगी, परन्तु यह तब जब ऐसा नमूना भार में दो किलोग्राम से अधिक नहीं है ।

4. इस आदेश में गम कराया (कतीरा) से स्टीरकूलिया यूरेनस पौधे से प्राप्त गम अभिप्रेत है।

[सं० 6(9)/77-नि०नि०तथा नि०उ०]

ORDER

S.O. 3319.—Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Gum Karaya meant for food and pharmaceutical uses to quality control and inspection prior to export, in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2453 dated 12th August, 1966 and the notification were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, in the Gazette of India dated the 30th September, 1978 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce dated the 30th September, 1978.

2. And whereas objections and suggestions were invited within forty-five days of the publication of the said order from all persons likely to be affected thereby ;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th October, 1978 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 2453 dated the 12th August, 1966, the Central Government after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India, hereby,—

(1) notifies that gum karaya meant for food and pharmaceutical uses shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) specifies the type of quality control and inspection in accordance with the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1979 as the type of inspection which would be applied to such gum karaya prior to export.

(3) recognises the specifications set out in the Annexure to this order as the standard specifications for gum karaya.

(4) prohibits the export in the course of international trade of any such gum karaya unless the same is accompanied by a certificate issued by any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that such gum karaya satisfies the condition relating to quality, control and inspection and is exportworthy.

3. Nothing in this order shall apply to export be sea, land or air of samples of gum karaya to prospective buyers provided that no such sample is in excess of two kilogram in weight.

4. In this order "gum karaya" shall mean the gum obtained from the plant sterculia urens.

[No. 6(9)/77-EI&EP]

का०आ० 3220.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम गम कराया (कतीरा) (निरीक्षण) नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा :—इन नियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'गम कराया' (कतीरा) से स्टीरकूलिया यूरेनस पौध से प्राप्त गोंद अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार :—गम कराया (कतीरा) का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जायेगा कि क्या वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य निर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—गम कराया (कतीरा) का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता, अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में अभिकरण को देगा और ऐसी सूचना के साथ यह घोषणा करेगा कि गम कराया (कतीरा) का परेषण नियम 3 के अनुसार तैयार किया गया है तथा परेषण इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है।

(2) जहां निर्यातकर्ता की यह इच्छा है कि निर्यात किये जाने वाले गम कराया (कतीरा) के परेषण का निरीक्षण,—

(क) बम्बई में अभिकरण द्वारा किया जाये वहां वह उपनियम (1) के अधीन सूचना, पोत लदान से कम से कम तीन दिन पहले देगा।

(ख) कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली या मद्रास में अभिकरण द्वारा किया जाये वहां वह उपनियम (1) के अधीन सूचना पोत भरण से कम से कम सात दिन पहले देगा।

(3) (1) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, अभिकरण गम कराया (कतीरा) के परेषण का निरीक्षण निर्यात निरीक्षण परिषद्, द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार अपना यह समाधान करने के विचार से करेगा कि परेषण नियम 3 के अनुसार श्रेणीकृत तथा पैक किया गया है या नहीं।

(2) निर्यातकर्ता अभिकरण को ऐसा निरीक्षण करने के लिये उसे सभी आवश्यक सुविधायें देगा।

(4) निरीक्षण के पश्चात् यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि निर्यात किये जाने वाले गम कराया (कतीरा) का परेषण, नियम 3 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तो अभिकरण,

(i) बम्बई में अभिकरण द्वारा निरीक्षण किये जाने की दशा में, सूचना प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, तथा

(ii) कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली या मद्रास में अभिकरण द्वारा निरीक्षण किये जाने की दशा में सूचना प्राप्ति से सात दिन के भीतर,

यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि परेषण निर्यात योग्य, है, परन्तु जहां अभिकरण का ऐसा समाधान नहीं होता है वहां वह उक्त तीन या सात दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार कर देगा तथा ऐसे इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को उसके कारणों सहित देगा।

5. पैकिंग तथा चिह्नांक :— 5 1 पैकिंग-गम कराया (कतीरा) दोहरे बोरों में पैक किया जाएगा जिनमें से अन्दर वाला बोरा साफ तथा मजबूत होगा और बाहरी बोरा पूर्णतः नया होगा।

5 2. चिह्नांक—बाहरी बोरे पर निम्नलिखित लिखा जायेगा, अर्थात् :—

(i) खाद्य तथा औषधीय प्रयोग के लिये बना गम कराया (कतीरा);

(ii) गम कराया (कतीरा) की श्रेणी; तथा

(iii) पोत परिवहन चिह्न।

6 निरीक्षण का स्थान :—(1) इन नियमो के प्रयोजन के लिये निरीक्षण, निर्यातकर्ता के परिसर पर, जहां निरीक्षण के लिये माल प्रस्तुत किया जाता है किया जायेगा परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधायें विद्यमान हों।

(2) अभिकरण, निर्यातकर्ता के परिसर पर उक्त निरीक्षण करने के अतिरिक्त परेषण का निरीक्षण पोत भरन के समय गोदाम में या घाट पर भी कर सकता है।

7. निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक परेषण के 50 कि० ग्रा० या उसके किसी भाग के लिये 1.50 पैसे की दर से निरीक्षण फीस दी जायेगी किन्तु यह फीस प्रति परेषण 50 रुपये से कम नहीं होगी।

8. अपील :—(1) नियम 4 के उपनियम (4) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के इंकार से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से, दस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्ति होंगे, अपील कर सकता है।

(2) विशेषज्ञों के पैनल में उसकी कुल सदस्यता के दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर निपटा दी जायेगी।

उपाबन्ध

गम कराया (कतीरा) के लिये विनिर्देश

1. गम स्टीरकूलिया यूरेनस पौधे से प्राप्त किया जायेगा।

2. गम निम्नलिखित श्रेणी मानकों के अनुरूप होगा :—

श्रेणी	छाल और बाह्य कार्बनिक पदार्थ (ब प्रकार)
सं० 1	अधिकतम 1.5%
सं० 2	अधिकतम 3.0%
सं० 3	अधिकतम 5.0%

3. गम का आकार निर्यात संविदा में यथा अधिकथित क्रेता तथा विक्रेता के मध्य तय हुए आकार के अनुसार होगा।

4. गम कृन्तक उत्सर्ग, कृन्तक मल और कृन्तक बालों से मुक्त होगा।

[सं० 6(9)/77-नि०नि०तथा नि०उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 3320.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Gum Karaya (Inspection) Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "agency" means any one of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "gum karaya" means the gum obtained from the plant Sterculia urens.

3. Basis of inspection.—The quality control and inspection of gum karaya shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export gum karaya shall give intimation in writing of his intention to do so to the agency and submit along with such intimation a declaration that the consignment of gum karaya has been prepared in accordance with rule 3 and that the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised for the purpose.

(2) Where the exporter desires that the inspection of the consignment of gum karaya to be exported may be conducted—

(a) by the agency at Bombay, he shall submit the intimation under sub-rule (1) not less than three days prior to shipment;

(b) by the agency at Calcutta, Cochin, Delhi or Madras, he shall submit the intimation under sub-rule (1) not less than seven days prior to shipment.

(3) (i) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (2), the agency shall inspect the consignment of gum karaya as per instructions issued by the Export Inspection Council in this behalf from time to time with a view to satisfying itself that the consignment has been graded and packed in accordance with rule 3.

(ii) The exporter shall provide all necessary facilities to the agency to enable it to carry out such inspection.

(4) If after inspection, the agency is satisfied that the consignment of gum karaya to be exported complies with the requirements of the specifications referred to in rule 3, the agency shall issue a certificate declaring the consignment as exportworthy,—

(i) within three days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the agency at Bombay, and

(ii) within seven days of the receipt of intimation in case of inspection conducted by the agency at Calcutta, Cochin, Delhi or Madras,

Provided that where the agency is not satisfied, it shall within the said period of three days or seven days as the case may be, refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons thereof.

5. Packing and marking

5.1 Packing.—The gum karaya shall be packed in double gunny bags. Whilst the inner bag shall be clean and sound the outer bag shall be completely new.

5.2 Marking—The outer bags shall be marked with the following informations :—

(i) gum karaya meant for Food and Pharmaceutical use;

(ii) grade of the gum karaya; and

(iii) shipping marks.

6 Place of inspection.—(i) Inspection for the purposes of these rules shall be carried out at the premises of the exporter where the goods are offered for inspection provided adequate facilities exist therein for inspection.

(ii) In addition to the inspection at the exporter's premises, the agency may also inspect the consignment at the time of shipment in godown or at the wharf.

7. Inspection fee.—Subject to a minimum of Rs. 50 for each consignment, a fee at the rate of Rs. 1.50 per 50 kg. or part thereof shall be paid as inspection fees under these rules.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the agency to issue a certificate under sub-rule (4) of rule 4, may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-third of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE

SPECIFICATIONS FOR GUM KARAYA

1. The gum shall be obtained from the plant sterculia urens.

2. The gum shall conform to the following grade standards :

GRADE	BARK AND FOREIGN ORGANIC MATTER (B FORM)
No. 1	1.5% Max.
No. 2	3.0% Max.
No. 3	5.0% Max.

3. The size of the gum shall be as agreed to between the buyer and the seller as laid down in the export contract.

4. The gum shall be free from rodent excreta, rodent filth and rodent hair.

[No. 6 (9)/77-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Joint Director.

(नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता विभाग)

भारतीय मानक संस्था

नई दिल्ली, 1979-09-07

का० आ० 3321—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि फर्म के द्वारा लाइसेंस समर्पित कर दिए जाने के कारण लाइसेंस संख्या सी एम/एल-7759 जिसके ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, 8 जुलाई 1979 से रद्द कर दिया गया है।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी एम/एल-7759 1979-05-17	मैसर्स केमिकल्स एण्ड इन्सेक्टीसाइड्स राम नगर करंजहा डाकघर भैसहा बरास्ता सरदार नगर, गोरखपुर (उ०प्र०) इनका कार्यालय सर्राफ चैम्बर्स हिन्दी बाजार, गोरखपुर (उ० प्र०) में है।	मालाथियोन पायसनीय सान्द्र	IS : 2567—1978 मालाथियोन पायसनीय सान्द्र की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)

[सी० एम० डी०/55 : 7759]

(Department of Civil Supplies and Co-operation)

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 1979-09-07

S.O. 3321.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-7759 particulars of which are given below has been cancelled with effect from Eight July, One Thousand Nine Hundred and Seventy nine as the firm has surrendered the licence.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/process covered by the licensees cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-7759 1979-05-17	M/s. Chemicals & Insecticides, Ram Nagar Karanjah, P.O. Bhanisah, Via Sardar Nagar, Gorakhpur (UP) having their office at Saraf Chambers, Hindi Bazar, Gorakhpur (UP).	Malathion EC	IS : 2567—1978 Specification for Malathion Emulsifiable Concentrates (Second Revision).

[CMD/55:7759]

का०आ० 3322.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 14 के उपविनियम (4) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि लाइसेंसधारी के द्वारा लाइसेंस समर्पित कर दिए जाने के कारण लाइसेंस संख्या सीएम/एल-5450, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, एक जुलाई 1979 से रद्द कर दिया गया है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या और तिथि	लाइसेंसधारी का नाम और पता	रद्द किए गए लाइसेंस के अधीन वस्तु/प्रक्रिया	सम्बद्ध भारतीय मानक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सी० एम० /एल०-5450 1976-08-25	मैसर्स केमो मिनरल इंडस्ट्रीज, मोहन मिल कम्पाउंड कोलशेट रोड, ठाणे-400601	2, 4-डी, सोडियम, तकनीकी की (पुन: भराई) मार्का :फर्नेक्सॉन	IS : 1488—1969 2, 4-डी सोडियम, तकनीकी की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)

[सी० एम० डी०/55 : 5450]

S.O. 3322.—In pursuance of sub-regulation (4) of regulation 14 of the Indian Standards Institution (Certification Marks), Regulations 1955 as amended from time to time, the Indian Standards Institution hereby notifies that Licence No. CM/L-5450 particulars of which are given below has been cancelled with effect from first July, One Thousand Nine Hundred and Seventy nine as the licensee has surrendered the licence.

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. and Date	Name and Address of the licensee	Article/Process covered by the Licensees cancelled	Relevant Indian Standards
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	CM/L-5450 1976-08-25	M/s. Chemo Mineral Industries, Mohan Mill Compound, Kolshet Road, Thana-400601.	2, 4-D Sodium, Technical (Repacking) Brand : 'FERNEXONE'	IS : 1488 –1969 Specification for 2, 4-D Sodium, technical (First Revision).

[CMD/55 : 5450]

नई दिल्ली, 1979-09-12

का०आ० 3323—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) के विनियम 1955 के विनियम 5 के उपविनियम (1) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि भारतीय मानक जिसके ब्यौरे इसके बाद नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, अब 1979-02-01 से रद्द कर दिया गया है और अब वापस माना जाए ।

अनुसूची

क्रम संख्या	रद्द किए गए भारतीय मानक की संख्या एवं शीर्षक	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक की स्थापना की अधिसूचना छपी थी उसकी एस० ओ० संख्या और तिथि	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1	घरेलू साधनों के लिए घरेलू विद्युत् नियंत्रणों की विशिष्टि IS : 7153—1973	भारत के राजपत्र भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1976-04-03 में एस ओ संख्या 1232 दिनांक 1976-03-12 के अधीन प्रकाशित ।	क्योंकि इस मानक में निर्धारित अपेक्षाएं अपूर्ण है और वर्तमान रूप में इस को संशोधन करके प्रमाणन कार्य योग्य नहीं बनाया जा सकता ।

[सी० एम० डी०/13 : 7]

New Delhi, the 1979-09-12

S.O. 3323.—In pursuance of sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 as amended from time to time, it is, hereby, notified that the Indian Standard, particulars of which is mentioned in the Schedule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn with effect from 1979-02-01.

SCHEDULE

Sl. No.	No. & Title of the Indian Standard Cancelled	S.O. No. & Date of the Gazette Notification in which Establishment of the Indian Standard was notified	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS : 7153-1973 Specification for domestic electric controls for household appliances.	S.O. 1232 dated 1976-03-12 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1976-04-03.	Since the requirements stipulated in this standard are incomplete and the standard is not amenable for certification in its present form.

[No. CMD/13 : 7]

का०आ० 3324.—भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1978-05-13 में प्रकाशित तत्कालीन नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय (भारतीय मानक संस्था) अधिसूचना संख्या एम ओ 1360 दिनांक 1978-04-24 के आंशिक संशोधन के रूप में भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि काच की दूध की बोतलों के लिए मानक चिह्न की डिजाइन में फिर परिवर्तन किया गया है । मानक चिह्न की यह परिवर्तित डिजाइन तत्सम्बन्धी भारतीय मानक के शीर्ष और डिजाइन के शाब्दिक विवरण सहित नीचे अनुसूची में दी गई है ।

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बने नियमों और विनियमों के कार्यों के लिए यह मानक चिह्न 1978-12-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	मानक चिह्न की डिजाइन	उत्पाद/उत्पाद की श्रेणी	सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या और शीर्षक	मानक चिह्न की डिजाइन का शाब्दिक विवरण
	IS:1392 ISI BOTTLE ONLY	काँच की दूध की बोतलें	IS : 1392—1971 काँच की दूध की बोतलों की विशिष्टि	भारतीय मानक संस्था का मोनोग्राम जिसमें "ISI" शब्द होते हैं स्तम्भ (2) में दिखाई गई शैली और अनुपात में तैयार किया गया है और जैसा डिजाइन में दिखाया गया है इस मोनोग्राम के ऊपर की ओर भारतीयमानक की पदसंख्या तथा नीचे की ओर शब्द "बोतल ओनली" अंकित किए गए हैं।

[सी० एम० डी०/13 : 9]

S.O. 3324.—In partial modification of the then Ministry of Civil Supplies and Co-operation (Indian Standards Institution) notification number S.O. 1360 dated 1978-04-24 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1978-05-13, the Indian Standards Institution, hereby notifies that the design of the Standard Mark for glass milk bottles has again been revised. The revised design of the Standard Mark together with the title of the relevant Indian Standard and verbal description of the design is given in the following Schedule.

This Standard Mark for the purposes of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952 and the Rules and Regulations framed thereunder, shall come into force with effect from 1978-12-01.

SCHEDULE

Sl. No.	Design of the Standard Mark	Product/Class of Product	No. & Title of the Relevant Indian Standard	Verbal Description of the Design of the Standard Mark
1.	IS:1392 ISI BOTTLE ONLY	Glass milk bottles	IS : 1392-1971 Specification for glass milk bottles (second revision)	The monogram of the Indian Standards Institution, consisting of letter 'ISI' drawn in the exact style and relative proportions as indicated in Col (2); the number of the Indian Standard being superscribed on the top side and the words 'BOTTLE ONLY' being subscribed under the bottom side of the monogram as indicated in the design.

[No. CMD/13 : 9]

अधिसूचना

का०आ० 3325.—समय-समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) विनियम 1955 के नियम 4 के उपनियम (2) के अनुसार अधिसूचित किया जाता है कि IS : 7153—1973 घरेलू साधनों के घरेलू विद्युत् नियंत्रणों की विशिष्ट सम्बन्धी घरेलू साधनों के विद्युत् नियंत्रणों के मानक चिह्न की डिजाइन जिसके ब्यौरे भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) दिनांक 1978-07-08 में एस ओ संख्या 2011 दिनांक 1978-06-23 के अधीन प्रकाशित हुए थे 1979-02-01 से वापस ली गई है।

[सी एम० डी०/13 : 9]

ए० पी० बनर्जी, उपमहानिदेशक

S.O. 3325.—In pursuance of sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Rules, 1955 as amended from time to time, it is, hereby notified that the design of the Standard Mark for domestic electric controls for household appliances, relating to IS : 7153-1973 Specification for domestic electric controls for household appliances, details of which were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 1978-07-08 under number S.O. 2011 dated 1978-06-23, has been rescinded with effect from 1979-02-01.

[No. CMD/13 : 9]

A. P. BANERJI, Dy. Director Gen.

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

का०आ० 3326.—वस्त्र मशीनों के निर्माण अथवा उत्पादनरत अनुसूचित उद्योगों की विकास परिषद् की स्थापना करने के बारे में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग के आदेश दिनांक 28-2-1979 जिसे भारत के राजपत्र के भाग 2 खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में दिनांक 28-2-1979 को प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा —

8 श्री० के० के० बजोरिया, अध्यक्ष,
इण्डियन जूट मिल्स एसोसिएशन,
रायल एक्सचेंज बिल्डिंग,
6, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-1

[सं० 957 टी एम/डी सी/एच आई/79/सं० 2-70/78-एच०एम०(1)]
एस० कनन, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th September, 1979

S.O. 3326.—In the Order of the Government of India, Ministry of Industry, Department of Heavy Industry dated 28-2-79, establishing a Development Council for the Scheduled industries engaged in the manufacture of production of Textile Machinery, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 28th February, 1979, the following amendment shall be made

8 Shri K. K. Bajoria, Chairman,
Indian Jute Mills Association,
Royal Exchange Building,
6, Netaji Subhas Road,
Calcutta.

[No. 957/TM/DC/HI/79/No. 2-70/78 HM(I)]
S. KANAN, Dy. Secy

(औद्योगिक विकास विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1979

का०आ० 3327—भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में 8 जून, 1978 को प्रकाशित इस मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 377(अ)/आई०डी०आर०ए०/21/1/78-पटसन में क्रमांक 21 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी —

"अध्यक्ष
हावली विपणन समवाय समिती लिमिटेड,
हावली (कामरूप),
आसाम"

[फा०सं० 21/1/78-पटसन]
एस० के० सरकार, संयुक्त सचिव

(Department of Industrial Development)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 14th September, 1979

S.O. 3327.—In this Ministry's Order No. S.O. 377(E)/IDRA/21/1/78-Jute published in the Gazette of India Extraordinary of the 8th June, 1978, in part II, Section 3, Sub-Section (ii), the entry appearing at Serial Number No. 21 shall be deleted and substituted by the following

"21. Chairman,
Howly Marketing Samabay Somity Ltd.,
Howly (Kamrup), Assam."

[F. No. 21/1/78/Jute]
S. K. SARKAR, Jt. Secy.

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1979

का० आ० 3328—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसाकि यहा सलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० 205 (Ank-P) से जी० जी० एस० 6 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) का धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-5-79 से समाप्त कर दिया गया है,

अत अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

205 (Ank-P) से जी० जी० एस-6 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन, और उर्वरक	हजात	438	18-2-78	28-5-79

[सं० 12016/23/79-प्रोड० 1]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZER

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 31st August, 1979

S.O .3328—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport petroleum from d.s. 205 (Ank-P) to GGS VI in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 28-5-79.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. 205 (Ank-P) to GGS-VI

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Hajat	438	18-2-78	28-5-79

[No. 12016/23/79—Prod.-I]

का० आ० 3329—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यक्त स्थल सं० 212 से 135 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 23-5-59 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

212 से 135 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	भडकादरा अमरवाड़ा	3543	9-12-78	23-5-79

[सं० 12016/23/68-प्रोड० 2]

S.O. 3329.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. Well No. 212 to 135 in Ankleshwar oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 23-5-79.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation of above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Well No. 212 to 135

Name of Ministry	Villages	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemical & Fertilizer	Bhadkodra Umarwada	3543	9-12-78	23-5-79

[No. 12016/23/79—Prod. II]

का० आ० 3330—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता) के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के सानन्द तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यक्त स्थल सं० सानन्द 48 से डब्ल्यू एच० आई० सानन्द 15 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 14-2-76 से समाप्त कर दिया गया है ।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता) के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद् द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

सानन्द -48 से डब्ल्यू एच० आई० सानन्द-15 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	सनाथड जेटलज नासमेद	1279	21-4-79	14-2-76

[सं० 12016/43/79-प्रोड०-I]

S.O. 3331. Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. SANAND-48 to W.H.I. SANAND-15 in Sanand oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 14-2-76.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. Sanand-48 to W.H.I. Sanand-15

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Sanawad Jethalaj Nasmed	1279	21-4-79	14-2-76

[No. 12016/43/79-Prod. I]

का० आ० 3331.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के सानन्द तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में उपधन स्थल स० डी० एच० बी० से सानन्द-12 तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपभोग के अधिकार है ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड (7) के उपखंड 1 की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 24-8-78 से समाप्त कर दिया गया है ।

अत अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

डी० एच० बी० से सानन्द-12 तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०स०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय	बोरीसना आद्रज मेरडा	960	17-3-79	24-8-78

[स० 12016/15/79-प्रोड०-II]

S.O. 3331.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. JHB to Sanand-12 in Sanand oil field in Gujarat State.

And Whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 24-8-78.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from D.S. JHB to Sanand-12

Name of Ministry	Villages	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Borisan Adraj Merda	960	17-3-79	24-8-78

[No. 12016/15/79—Prod.-II]

का० आ० 3332—यत इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन ओयल कोरपोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है ।

और यत: इण्डियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची मे निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है ।

अब अत पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन के नियमावली 1963) नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथी को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करते है ।

अनुसूची

उपधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाईन संक्रिया पर्यवसान

मन्त्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
1	2	3	4	5
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	हामलपुर मुरेश्वर	2748	3-9-77	30-11-78

1	2	3	4	5
	विरमगाम	2748	3-9-77	30-11-78
	वलाणा	,,	,,	,,
	कोकता	,,	,,	23-11-78
	नदीयाणा	,,	,,	,,
	चणोठीया	,,	,,	8-10-78
	करीयाला	,,	,,	,,
	अघार	,,	,,	,,
	बासका	,,	,,	,,

[सं० 12020/16/79-प्रोड०-II]

S.O. 3332.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State of Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And Whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum,	Hansalpur	2748	3-9-77	30-11-78
Chemicals &	Sureshwar	,,	,,	,,
Fertilisers	Viramgam	,,	,,	,,
(Petroleum	Valana	,,	,,	,,
Department)	Kokta	,,	,,	,,
	Nadiyana	,,	,,	23-11-78
	Chanothiya	,,	,,	,,
	Kariyala	,,	,,	8-10-78
	Aghar	,,	,,	,,
	Boska	,,	,,	,,

[No. 12020/16/79—Prod.-II]

का०आ० 3333.—यत: इससलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन ग्रोयल कोर्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियां के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यत: इण्डियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची मे निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब अत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करते है।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाईन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम रसायन	भंकोडा	2749	3-9-77	8-10-78
और उर्वरक	रामपुरा	,,	,,	,,
मंत्रालय	कांज		,,	,,
(पेट्रोलियम विभाग)	सदातपुरा	,,	,,	29-10-78
	देकावाडा	,,	,,	,,
	गमानपुरा	,,	,,	1-11-78
	नदीशाला	,,	,,	,,
	रुदातल	,,	,,	29-11-78
	डभासर	,,	,,	,,

[सं० 12020/16/79 प्रोड०-I]

S.O. 3333.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (ii) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And Whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of Termination
Petroleum	Bhankoda	2749	3-9-77	8-10-78
Chemicals &	Rampura	,,	,,	,,
Fertilisers	Kanz	,,	,,	,,
(Petroleum	Sadatpura	,,	,,	29-10-78
Department)	Dekavada	,,	,,	,,
	Gamanpura	,,	,,	1-11-78
	Nadishala	,,	,,	,,
	Rudatal	,,	,,	29-11-78
	Debhasar	,,	,,	,,

[No. 12020/16/69-Prod.-I]

का० आ० 3334.—यतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लिये गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात रिफाइनरी कोयली तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है।

और यतः इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित कर दिया है।

अब अतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट संक्रिया पर्यवसान के रूप में एतद् द्वारा अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाईपलाइन संक्रिया पर्यवसान

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	संक्रिया पर्यवसान की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग)	तेनीवाडा	2919	17-9-77	16-4-79
	राजोसणा	,,	,,	16-5-79
	छापी	,,	,,	,,
	माही	,,	,,	,,
	भरकावाडा	,,	,,	,,
	शेरपुरा	,,	,,	,,

[सं० 12020/17/79-प्रोड०]

S.O. 3334.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962, the Right of User has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State.

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has terminated the operation referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on the date shown against the name of village in the schedule.

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of the said operation.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from Salaya to Mathura

Name of Ministry	Name of Village	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Petroleum Department)	Tenivada	2919	17-9-77	16-4-79
	Rajosana	,,	,,	16-5-79
	Chhapi	,,	,,	,,
	Mahi	,,	,,	,,
	Bharkawada	,,	,,	,,
	Sherpura	,,	,,	,,

[No. 12020/17/79-Prod.]

का० आ० 3335.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशन किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० जे एल बी से जी जी एस जलोरा तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 26-4-78 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम पाइप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी एतद्-द्वारा उक्त तिथि को कार्य समाप्त की तिथि अधिसूचित करते हैं।

अनुसूची

जे एल बी से जी जी एस जलोरा तक पाइप लाइन कार्य समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	मेरडा	260	20-1-79	26-4-78

[सं० 12016/15/79-प्रोड० II]

S.O. 3335.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. JLB to GGS Zalora in Kadi oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred f in clause (i) of sub section (1) of section section 7 of the said Act on 26-4-78.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. JLB to GGS Zalora

Name of Ministry	Villages	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Merda	260	20-1-79	26-4-78

[No. 12016/15/79-Prod.-II]

का० आ० 3336.—भारत सरकार के अधिसूचना के द्वारा जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में प्रदर्शित किया गया है और पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकारी) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है, गुजरात राज्य के कड़ी तेल क्षेत्र में उक्त परिशिष्ट भूमि में व्यधन स्थल सं० जे एल० एम (झालोरा 20) से जी जी एस झालोरा तक पेट्रोलियम के लिए भूमि उपयोग के अधिकार प्राप्त किये गए है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (1) की धारा (1) में निर्दिष्ट कार्य दिनांक 14-6-78 से समाप्त कर दिया गया है ।

अत. अब पेट्रोलियम पाईप लाइन के नियम (प्रयोगकर्ता के भूमि अधिग्रहण अधिकार) नियम, 1963 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी एतद् द्वारा उक्त तिथि का कार्य समाप्ति कि तिथि अधिसूचित करते है।

अनुसूची

जे० एल० एम (झालोरा 20) से जी० जी० एस झालोरा तक पाइप लाइन कार्य की समाप्ति

मंत्रालय का नाम	गांव	का०आ०सं०	भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक	आद्रज	961	17-3-69	14-6-78

[सं० 12016/15/79-प्रोड०-I]

श्रीकान्त वेडेरा, गुजरात राज्य के लिए अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

S.O. 3336.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962, the right of use has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from d.s. JLM (JALORA-20) to GGS Zalora in Kadi oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub-section (1) of section 7 of the said Act on 14-6-78.

Now, therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules, 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

Termination of operation of pipeline from D.S. JLM (Jalora-20) to GGS Zalora.

Name of Ministry	Village	S. O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
1	2	3	4	5
Petroleum, Chemical & Fertilizer	Adraj	961	17-3-79	14-6-78

[No. 12016/15/79 Prod. I]

S. D. VADEERA,

Competent Authority under the Act for Gujarat

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1979

का० आ० 3337.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारी क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची-834001 (बिहार) में या कलक्टर, सीधी, मध्य प्रदेश के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक के कार्यालय, 1, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को परिदत्त कर दें।

अनुसूची

(मेधौली और पिन्डरमली ब्लाक)

सिंगरौली कोयला क्षेत्र

जिला—सीधी (म०प्र०)

रेखांक सं० राज/40/179

तारीख 3-5-1979

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र दर्शित करते हुए)

मेधौली ब्लाक —

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गोरबी . . .	देवसर	—	—	सीधी	—	भाग
2	कठास . . .	,,	—	—	,,	—	पूर्ण
3.	मौरहिया . . .	,,	—	—	,,	—	भाग
4	फुलझर . .	,,	—	—	,,	—	पूर्ण
5.	हगुरा . . .	,,	—	—	,,	—	पूर्ण
6	महदेइया . .	,,	—	—	,,	—	,,
7	मेधौली . . .	सिंगरौली	—	—	,,	—	भाग
8.	निगाही .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
9	मुहेर . .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
10	सोलाग . .	यथोक्त	—	—	,,	—	पूर्ण
11.	राजाखड . .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
12.	प्यरखा . . .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
13.	घाकवार . .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
14.	पड़री . .	यथोक्त	—	—	,,	—	भाग
15.	चितगीटोला .	यथोक्त	—	—	,,	—	,,
16.	हर्रैया	यथोक्त	—	—	,,	—	,,

कुल क्षेत्र : 21,700.00 एकड़ (लगभग)
या 8,781.56 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण

क-ख रेखा रायपुर और पड़री ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा के एक भाग से (जो देवसर और सिंगरौली तहसीलों की भी सम्मिलित सीमा रेखा का एक भाग है) होकर गुजरती है।

ख-ग रेखा चितगीटोला ग्राम, गेडरिया और चितगीटोला ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा के एक भाग से होती हुई नाले के साथ-साथ गुजरती है।

ग-घ भागत नाले की मध्य रेखा के साथ-साथ गुजरती है।

घ-ङ-च-छ रेखाएं हेरया, चितगीटोला, पड़री, मोहर और निगाही ग्रामों से (जो कि कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अर्जित मोहर, अमलोरी और निगाही ब्लाकों की भी सम्मिलित सीमा रेखा है) होकर गुजरती हैं।

छ-ज-झ रेखाएं निगाही और मेधौली ग्रामों से होती हुई कठास और मेधौली ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा के एक भाग से (जो खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 17 के अधीन अधिसूचित ब्लाक की भी सम्मिलित सीमा रेखा है होकर गुजरती है।

झ-क रेखा कठास, गरबी, हगुरा और महदेइया ग्रामों की उत्तरी सीमा के एक भाग से होती हुई और महदेइया ग्राम की पश्चिमी सीमा रेखा के कुछ भाग से गुजरती है और आरंभिक बिन्दु "क" पर मिल जाती है।

ध्यान दें— मेधौली ब्लाक के अन्तर्गत 1, 2, 3 और 4 से घिरा हुआ गोरबी ब्लाक और 5, 6, 7 और 8 से घिरा हुआ गोरबी ब्लाक एक्टेंशन सम्मिलित नहीं हैं (गोरबी ब्लाक और गोरबी ब्लाक को कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन पहले ही अर्जित किया जा चुका है)।

पिण्डर टोला ब्लाक

क्रम सं०	ग्राम	तहसील परगना	परगना नं०	जिला क्षेत्र	टिप्पण
1	पिण्डर टोला	सिंगरौली	सिंगरौली	सीधी	भाग
2.	पजरेह	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
3	चटका	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
4.	चूड़ीदाह	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
5	झींगुरदाह	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
6	चुर्की	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
7.	मेधौली	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त

कुल क्षेत्र 4,300.00 एकड़ (लगभग)
या 1,740.12 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

ट-ठ-ड-ढ रेखाएं भागतः कुसुमी और पिण्डर टोला, पिण्डर टोला और मेधौली, पिण्डर टोला और पजरेह ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है और फिर पजरेह और मेधौली ग्रामों (जो खान और खनिज अधिनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचित ब्लाक की सम्मिलित सीमा रेखा का एक भाग है, से होकर गुजरती है।

ढ-ण रेखा भागतः पजरेह और मेधौली और चटका, चटका और करवारी, करवारी और झींगुरदाह ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है और फिर चूड़ीदाह ग्राम जो कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन भागतः झींगुरदाह ब्लाक की सम्मिलित सीमा रेखा भी है, से होकर गुजरती है।

ण-त रेखा भागतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है।

त-थ-द-ध-न-प-फ-ब- रेखाएं झींगुरदाह, चटका, पजरेह और पिण्डर टोला ग्रामों से (जो कोयला अधिनियम की धारा 9 के अधीन झींगुरदाह ब्लाक की सम्मिलित सीमा रेखा है) होकर गुजरती है।

ब-भ रेखा सिंगरौली तहसील के झींगुरदाह ग्राम और तहसील देवसर के चुर्की ग्राम से होती हुई फिर भागतः झींगुरदाह और बरकी ग्रामों की सम्मिलित सीमा रेखा (जो कोयला अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन भागतः झींगुरदाह ब्लाक की सम्मिलित सीमा रेखा है) के साथ-साथ गुजरती है।

भ-म रेखा भागतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है।

म रेखा देवसर तहसील के चुर्की ग्राम से होते हुए और सिंगरौली तहसील के चुर्की और पिण्डर टोला ग्रामों की उत्तरी सीमा रेखा से होते हुए आरंभिक बिन्दुओं पर मिल जाती है।

[संख्या 19(24)/79-(1) सी० एल०]

MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

(Department of Coal)

New Delhi, the 14 September 1979

S.O. 3337.—Whereas it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land mentioned in the Schedule hereto annexed,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein.

The Plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar), or in the Office of the Collector, Sidhi, Madhya Pradesh or in the Office of the Coal Controller 1, Council House, Street, Clacutta-700001.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001, (Bihar) within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

Medhauli and Pindertali Blocks

Singrauli Coalfield
(Distt. Sidhi (MP;

Drg. No. Rev/40/79 dt. 3-5-1979
(Showing land notified for prospecting)

Medhauli Blocks

Sr. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Dist Area	Remarks
1 2	3	4	5	6	7	8
1.	Gorbi	Deosar	—	—	Sidhi	Part
2.	Kathas	,,	—	—	,,	Full
3.	Naurhiya	,,	—	—	,,	Part
4.	Phuljhai	,,	—	—	,,	Full
5.	Ingura	,,	—	—	,,	Full
6.	Mahadaiya	,,	—	—	,,	Full

1	2	3	4	5	6	7
7.	Medhauli	Singrauli	—	—	Sidhi	Part
8.	Nigahi	-do-	—	—	,,	,,
9.	Muher	-do-	—	—	,,	,,
10.	Solang	-do-	—	—	,,	Full
11.	Rajakhad	-do-	—	—	,,	,,
12.	Thurwa	-do-	—	—	,,	,,
13.	Chakawar	-do-	—	—	,,	,,
14.	Padari	-do-	—	—	,,	Part
15.	Chinagi tota	-do-	—	—	,,	,,
16.	Harraiya	-do-	—	—	,,	,,

Total Area : 21,700.00 acres (approx.)
or 8,781.56 hec. (approx.)

Boundary description :

A—B line passes along the part common boundary of village Rampurwa and Padari (which is also the part common boundary of Tahsil Deosar and Singrauli).

B—C line passes through village Chinagi tola, along the part common boundary of villages Gedaria and Chinagi tola then through nala.

C—D line passes along the part central line of Nalla.

D—F—F—F 1—F 2—G lines pass through villages Harraiya, Chinagi tola, Padari, Muher and Nigahi (which is also the part common boundary of Muher, 'Amlori' and 'Nigahi' block acquired u/s 4(1) of Coal Act).

G—H—I lines pass through villages Nigahi and Medhauli along the part common boundary of villages Kathas and Medhauli, Kathas and Kusbai (which is also the part common boundary of block notified u/s 17 of M & H (R & D) Act, 1957).

I—A line passes along the part northern boundary of villages Kathas Gorbi, Ingura and Mahadaiya and along the part western boundary of village Mahadaiya and meets and starting point 'A'.

N.B. Medhauli Block excludes the area of Gorbi Block bounded by 1, 2, 3 and 4 and Gorbi Block Extn. bounded by 5, 6, 7 and 8 (Gorbi Block and Gorbi Block Extn. already acquired u/s 9(1) of Coal Act).

Pender Tali block

Sr. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana number	Distt. Area	Remarks
1.	Pinder toli	Singrauli	Singrauli		Sidhi	Part
2.	Panjreh	-do-	-do-		-do-	-do-
3.	Chatka	-do-	-do-		-do-	-do-
4.	Churidah	-do-	-do-		-do-	-do-
5.	Jhingurdah	-do-	-do-		-do-	-do-
6.	Churki	-do-	-do-		-do-	-do-
7.	Medhauli	-do-	-do-		-do-	-do-

Total Area : 4,300.00 acres (approx.)
or 1,740.12 hec. (approx.)

Boundary Description :

J—K—L—M—N lines pass along the part common boundary of villages Kusbai and Pinder tali, Pindertali and Medhauli, Pindertali and Panjreh, then through villages Panjreh and Medhauli (which forms part common boundary of block notified u/s 17 M & M (R & D) Act, 1957.

N—O line passes along the part common boundary of villages Panjreh and Medhauli, Medhauli and Chatka, Chatka and Karwari, Karwari and Jhingurdah then through village Churidah which forms part common boundary of Dudhichuwa block u/s 4(1) of Coal Act.

O—P line passes along the part Inter State boundary of U.P. and M.P.

P—Q—R.S—T—U—V—W lines pass through villages Jhingurdah, Chatka Panjreh and Pindertali (which forms common boundary of Jhingurdah block acquired u/s 9 of the Coal Act).

N—X line passes through village Jhingurdah of Tahsil Singrauli and Churki of Tahsil Deosar then along the part common boundary of villages Jhingurdah and Churki (which forms part common boundary of Jhingurdah block Extn. u/s 4(1) of Coal Act).

X—Y line passes along the part Inter-State Boundary of U.P. & M.P.

Y—J line passes through village Churki of Tahsil Deosar and along northern boundary of villages Churki and Pindertali of Tahsil Singrauli and meets at starting point 'J'.

[No. 19 (24)/79-CL (i)]

का० आ० 3338.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के आशय की सूचना देती है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) के कार्यालय दरभंगा हाउस, रांची-. 834001 (बिहार) में या कलक्टर, सीधी, मध्य प्रदेश के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक के कार्यालय, कौंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700001 में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची-834001 को भेजेंगे ।

अनुसूची

ककरी ब्लाक इक्टेंशन और पथसागर ब्लाक

सिंगरौली कोयला क्षेत्र जिला—मिर्जापुर (उ० प्र०)

रेखांक सं० राज०/41/79

तारीख 31-5-79

(पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित क्षेत्र वर्णित करते हुए)

ककरी ब्लाक इक्टेंशन

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	औंदी	दूधी	सिंगरौली	—	मिसरा (बीरवा)	मिर्जापुर		भाग
2.	ककरी	यथोक्त	यथोक्त	77	यथोक्त	यथोक्त		यथोक्त
3.	नकली	यथोक्त	यथोक्त	108	यथोक्त	यथोक्त		पूर्ण
4.	परासी	यथोक्त	यथोक्त	36	यथोक्त	यथोक्त		भाग

कुल क्षेत्र : 3400.00 एकड़ (लगभग)
1375.91 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

क-ख	रेखा भागतः मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा रेखा (जो औंदी और ककरी ग्रामों की भागतः पश्चिमी सीमा रेखा भी है) के साथ-साथ गुजरती है ।
ख-ग	रेखा ककरी, परासी और पन्त सागर ग्रामों से (जो कोयला अधिनियम की धारा 4 के अधीन भागतः ककरी ब्लाक की सम्मिलित सीमा रेखा भी है) होकर गुजरती है ।
ग-घ	रेखा परसी ग्राम की पूर्वी सीमा रेखा के साथ-साथ पन्त सागर से और भागतः औंदी ग्राम की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गुजरती है ।
घ-क	रेखा औंदी ग्राम से होती हुई आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिल जाती है ।

पन्त सागर ब्लाक :

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	परगना	परगना सं०	थाना	जिला	क्षेत्र	टिप्पण
1.	पन्तसागर	दूधी				मिर्जापुर	—	भाग

कुल क्षेत्र : 6,600.00 एकड़ (लगभग)
या 2,670.88 हेक्टेयर (लगभग)

सीमा विवरण :

ङ-च	रेखा भागतः रोहता ग्राम की दक्षिणी सीमा रेखा के साथ-साथ और पंतसागर से होती हुई गुजरती है ।
च-छ	रेखा पंतसागर और परासी, जामसिला, बरवानी, चौधवार, धरमारी, कोहरौलिया ग्रामों की पूर्वी सीमा रेखा से होती हुई कोहरौली, मिसरा, भेरवा, जोगी चौरा, मरकि, परसवार राजा, परसवार बाबू परसवार चौबे, बरवा भटवारी और कोटा ग्रामों की दक्षिणी सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है ।
छ-ज	रेखा भागतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सीमा रेखा के साथ-साथ गुजरती है ।
ज-झ-ङ	पंतसागर से होती हुई गुजरती है ।
-ङ-	रेखा पन्तसागर से होती हुई आरंभिक बिन्दु "क" पर मिल जाती है ।

[संख्या 19(24)/79-(2) सी० एल०]

एस० आर० ए० रिजवी, निदेशक

S.O. 3338.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957 (20 of 1957) the Central Government hereby gives notices of its intention to prospect for coal therein ;

The plan of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Central Coalfields Limited, Revenue Section, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar), or in the office of the Collector, Mirzapur, Uttar Pradesh, or in the office of the Coal Controller, 1-Council House Street, Calcutta-1.

All persons interested in the land covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to the sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi-834001 (Bihar) within ninety days from the date of the publication of this notification.

SCHEDULE

Kakari Block, Extn. & Panth Sargar Blocks Singrauli Coalfield Distt. Mirzapur (U.P.) (Drg. No. Rev. 47/79 dt. 31-1-79 showing land notified for prospecting).

Kakari Block Extenstion :

Sr. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana Number	Thana	Distt.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Aundi	Dudhi	Singrauli	—	Misra (Khairwa)	— Mirzapur	—	part.
2.	Kakari	Dudhi	Singrauli	77	Misra (Khairwa)	Mirzapur		part
3.	Nakli	-do-	-do-	108	-do-	-do-		Full
4.	Parasi	-do-	-do-	36	-do-	-do-		part

Total area : 3400.00 acres (approx.) or 1375.91 hec. (approx.)

Boundary description :

A—B line passes along the part State boundary of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh (which is also part western boundary of villages Aundi and Kakari).

B—C line passes through villages Kakari, Parasi and Panth Sagar (which also form part common boundary with Kakari block notified u/s 4 of the Coal Act).

C—D line passes through Panth Sagar along eastern boundary of villages Parasi and part eastern boundary of village Aundi.

D—A line passes through in village Aundi and meets at starting point 'A'.

Panth Sagar Block :

Sl. No.	Village	Tahsil	Pargana	Pargana No.	Thana	District	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Panth Sagar	Dudhi				Mirzapur		part

Total area : 6,600.00 acres (approx.) or 2,670.88 hec. (approx.)

Boundary Despcription :

E—F line passed along the part southern boundary of village Rehta and through Panth Sagar.

F—G line passes through Panth Sagar and along the eastern boundary of villages Parasi, Jamsila, Barwani, Choudwar, Dharsari, Koharaulia, along southern boundary in villages Koharoul, Mishra, Bhairwa, Jogichowra, Marrak, Parsawar Raja, Parswar Babu, Parsawar Choube, Barwa Bhatwari & Kota.

G—H line passes along the part State Boundary of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.

H—I—J lines pass through Panth Sagar.

J—E line passes through Panth Sagar & meet at starting point 'E'.

[No. 19(24)/79—CL(ii)]

S.R.A. RIZWI, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

का० आ० 3339.—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री पी० सबानायगम, सचिव, शिक्षा मंत्रालय की श्री एच० एस० साहनी के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली का सदस्य मनोनीत करती है और भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 24 दिसम्बर, 1977 की अधिसूचना संख्या बी० 16011/176 एम० ई० (पी० जी०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"श्री पी० सबानायगम, सचिव, शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि।"

[स० बी०-16011/2/78-एम० ई० (पी०जी०)]

प्रकाश चन्द्र जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 12th September, 1979

S.O. 3339.—In pursuance of clause (d) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, (25 of 1956), the Central Government hereby nominates Shri P. Sabanayagam, Secretary, Ministry of Education, to be a member of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi vice Shri H. S. Shahani, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 16011/1/76-ME(PG), dated the 24th December, 1977, namely :—

In the said notification, for entry 2, the following entry shall be substituted, namely :—

"2. Shri P. Sabanayagam, Secretary Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi.	Representative of the Ministry of Education."

[No. V. 16011/2/78-ME(PG)]

P. C. JAIN, Desk Officer

नई दिल्ली, 16 मई, 1979

का० आ० 3340.—केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (बंगलौर, नियम, 1976 नियम 1 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त नियमों को निम्नलिखित क्षेत्रों में 16 मई, 1979 से लागू करती है, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 7, सदाशिव नगर (56-ए-34-लोअर प्लेस आर्चर्ड बंगलौर-560006) इस औषधालय की सीमा इस प्रकार है :

उत्तर में गड्डलाहल्ली और मन्नारायणपल्या को जोड़ने वाली मेन पावर लाइन से घिरा हुआ क्षेत्र।

पूर्व में मन्नारायणपल्या से सुलतान पल्या तक और सुलतान पल्या से मुनीरेड्डी पल्या सर्कल तक, जयमहल रोड मिलर्स रोड के कुछ भाग से बसंतनगर, 1 मेन रोड तक।

दक्षिण में मिलर्स रोड जोड़ने वाली सड़कों से घिरा हुआ क्षेत्र और 1 मेन रोड बसंतनगर के जंक्शन से 1 मेन रोड बसंत नगर तक प्लेस रोड के चालुक्य होटल तक रेसकोर्स रोड से माधवनगर 1 मेन रोड तक नगप्पा स्ट्रीट से शेषाद्रीपुरम सर्कल तक का क्षेत्र।

पश्चिम में 1 मेन रोड शेषाद्रीपुरम के साथ-साथ शेषाद्रिपुरम सर्कल से लिंक रोड तक लिंक रोड से बी० क्रास ईस्ट लिंक रोड तक बी० क्रास ईस्ट लिंक रोड से सीवरीज ड्रेन के साथ साथ जो गुट्टाहल्ली मेन रोड तक जाती है। गुट्टाहल्ली मेन रोड और सीवरीज ड्रेन बी० क्रास स्विमींग पूल एक्सटेन्सन के जंक्शन से 12 वें क्रास मालेश्वरम तक।

12 वें क्रास के साथ साथ 12 वें क्रास मालेश्वरम और बी० क्रास स्विमींग पूल एक्सटेंशन के जंक्शन से कोड्डारामापुरम III क्रास तक। इसके बाद कोड्डारामापुरम III क्रास, III टैंपल स्ट्रीट रंगनाथपुरम मेन रोड से शंके रोड तक। शंके रोड और रंगनाथपुरम मेन रोड के जंक्शन से शंके रोड से होते हुए इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साईंस सर्कल (मैसूर पोरसीलेन फैक्टरी) तक। इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साईंस सर्कल से ट्रमकुर रोड होते हुए मेखरी सर्कल तक। मेखरी सर्कल से गेड्डाहल्ली को जाने वाली कच्ची रोड और बेलरी रोड के जंक्शन तक कच्ची रोड और अशोक नगर होते हुए कच्ची रोड और बेलरी रोड के जंक्शन से गेड्डालहाल्ली तक।

उपर्युक्त सीमांकन के फलस्वरूप निम्नलिखित क्षेत्र जो कि पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 2 मलेश्वरम के अन्तर्गत आते थे अब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं० 7 सदाशिवनगर के अन्तर्गत आएंगे।

1. हाई ग्राउंड्स
2. शेषाद्रीपुरम के पूर्वी ओर पड़ने वाले कुछ भाग
   (1) शेषाद्रीपुरम 1 मेन रोड से लिंक रोड तक।
   (2) लिंक रोड और खुला नाला जो कि बी० क्रास लिंक रोड से आरम्भ होता है तथा गट्टाहल्ली मेन रोड तक जाता है।
3. कुमार पार्क (पूर्वी और पश्चिमी)
4. प्लेस गट्टाहल्ली
5. ईस्ट आफ बी० क्रास की ओर पड़ने वाले स्वीमिंग पूल
6. वेंकटरंगपुरम
7. ब्यालीकवल
8. रंगनाथपुरम
9. गायत्री पार्क एक्सटेंशन
10. उपर्युक्त 1 और 2 को छोड़कर सभी टेंपल स्ट्रीट्स
11. उपर्युक्त 1 और 2 को छोड़कर कोड्डारामापुरम के सभी क्रास रोड्स
12. पेलेस अभिलेख (लोअर तथा अपर)
13. राजमहल विलास एक्सटेंशन

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सदाशिवनगर औषधालय के द्वारा जिन प्रमुख क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का विस्तार किया गया है उनके नाम अनुसूची में दिए गए हैं।

अनुसूची

1. गेड्डाहल्ली
2. मन्नारायणपल्या
3. सुलतान पल्या
4. गंगेनाहल्ली
5. दिन्नूर
6. माताडाहल्ली
7. मुनीरेड्डी पल्या
8. अशोक नगर

[सं० 16011/2/78-के०स० स्वा० यो० डेस्क]

सत्यपाल गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 16th May, 1979

S.O. 3340.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (3) of rule 1 of the Central Government Health Scheme (Bangalore) rules 1976, the Central Government hereby extends the said rules with effect on and from 16th May, 79 to the following areas, namely :—

Central Government Health Scheme Dispensary No. 7. Sadashivanagar

(56-A-34, Lower Place Orchard, Bangalore-560006) Area bounded :

In the North by the Main Power line connecting Geddalahalli and Mannarayana Palya

In the East by Roads connecting Mannarayanapalya to Sultan Palya and from Sultan Palya to Munireddy Palya Circle, Jayamahal Road, Part of Miller's Road upto Vasanthnagar, I Main Road.

In the South from the junction of Miller's Road and I Main Road Vasanthanagar, by I Main Road Vasanthnagar, Place Road upto Chalukya Hotel, Race Course Road, Madhavanagar 1 Main Road, Nagappa Street, upto Seshdhripuram Circle

In the West from Seshadripuram Circle by I Main Road Seshadripuram upt Link Road. Link Road to B Cross East Link Road, from B Cross East Link Road along the Sewerage drain, which runs upto Guttahalli Main Road From the junction of Guttahalli Main Road and Sewerage Drain, V Cross Swimming pool Extension upto 12th Cross Malleswaram. From the junction of 12th Cross Malleswaram and V Cross Swimming Pool Extension along the 12th Cross upto Kodandramapuram III Cross. Then Kodandramapuram III Cross, III Temple Street, Ranganathapuram Main Road upto Sankey Road. From the junction of Sankey Road and Ranganathapuram Main Road through Sankey Road upto Indian Institute of Science Circle (Mysore Porcelain Factory). From Indian Institute of Science Circle to Mekhri Circle via Tumkur Road From Mekhri Circle, Bellary Road upto the junction of mud Road leading to Geddalahalli From the junction of mud Road and Bellary Road via the mud Road and Ashoknagar upto Geddalahalli

With the demarcation as mentioned above, the following areas which were previously covered by CGHS. Dispensary No 2 Malleswaram will now be covered by CGHS Dispensary No. 7, Sadashivanagar.

1 High Ground

2 Part of Seshadripuram falling on the eastern side of—

(1) Seshadripuram I Main Road upto link Road.

(2) Link Road and open drain which starts from B Cross East Link Road and runs upto the Guttahalli Main Road.

3 Kumara Park (East and West)

4 Place Guttahalli

5 Part of Swimming Pool Extension falling on the East of V Cross.

6 Venkatarangapuram

7 Vyalikaval

8. Ranganathapuram

9. Gayathri Park Extension

10 All the temple streets except 1 and 2 above

11 All the Cross Roads of Kodandaramapuram except 1 and 2 above

12 Palace Orchards (Lower and Upper)

13 Pajamahal Vilas Extension

In addition to the above, the names of the prominent areas to which CGHS is extended through the Sadashivanagar Dispensary are given in the Schedule.

THE SCHEDULE

1 Geddalahalli.
2 Mannarayana Palya.
3. Sultan Palya.
4 Gangenahalli
5 Dinnur.
6 Matadahalli.
7 Munireddy Palya
8 Ashoknagar.

[No. V. 16011/2/78 ME (PG)]
S P GOSWAMI, Under Secy.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1979

का० आ० 3341—अत केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयो, उपाप्ति निदेशालयो और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयो द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, सचलन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यो का पालन करना बंद कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य है।

और यत खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयो, उपाप्ति निदेशालयो और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयो मे कार्य कर रहे और उपरिवर्णित कृत्यो के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियो और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर मे उसमे विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को उक्त अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1)के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नही दी है ।

अत अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम मे स्थानान्तरित करती है :—

क्रम सं	अधिकारी कर्मचारियो का नाम	केन्द्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरण की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री एस० एस० आहलुवालिया	सहायक निदेशक	सहायक निदेशक	1-3-69
2	श्री डी० एच० चेटी	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	-वही-

1	2	3	4	5
3	श्री आर० एम० सुन्दरम	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-69
4	श्री के० प्रताप चन्दरन	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	गुण निरीक्षक-1	—वही—
5	श्री बाबू लाल	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
6	श्री पी० एस० हितेशी	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
7	श्री एम० हुसैन	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	—वही—
8	श्री कमल कान्त दास	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	गुण निरीक्षक	—वही—
9	श्री वी० के० श्री वास्तव	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—
10.	श्री लाल बहादुर सुपुत्र श्री नर बहादुर	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
11	श्री एम० आई० खां	कनिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	—वही—
12	श्री चन्द्र पाल शर्मा	—	गुण निरीक्षक-1	—वही—
13	श्री आर०एन० तिवारी	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	गुण निरीक्षक- 1	—वही—
14.	श्री राम कुमार यादव	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
15.	श्री विन्देया चल मौर्य	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
16	श्री एस० राजी हुसैन	वरिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	—वही—
17	श्री पी० एन० लाल	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	—वही—
18	श्री हरि नाथ	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
19	श्री डी० एन० शुक्ला	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
20	श्री घसिटा खा	—वही—	—वही—	—वही—
21.	श्री सुख लाल	स्वीपर	स्वीपर	—वही—
22	श्री हबीब मोहम्मद	—	तकनीकी सहायक	—वही—
23	श्री आर० एन० सिंह	—	कनिष्ठ लिपिक	—वही—
24.	श्री एन० बी० मथुनी	—	कनिष्ठ लिपिक	—वही—
25	श्री नरीन्द्र प्रकाश ज्योति	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
26.	श्री बी० डी० भारद्वाज	—	—वही—	—वही—
27.	श्री टी० एन० शर्मा	—	—वही—	—वही—
28	श्री महेश चन्द एम० शाह	—	—वही—	—वही—
29	श्री जे० पी० पोखरियाल	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—
30	श्री बच्चू सिंह	कनिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	—वही—
31.	श्री भानु प्रकाश	—	वाचमैन	—वही—
32	श्री जिले सिंह सिरोही	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
33.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	—वही—	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	15-9-71
34.	श्री एच० ए० आर० सिद्दीकी	तकनीकी सहायक	तकनीकी सहायक-1	1-3-69
35.	श्री के० एन० दुबे	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	12-5-70
36.	श्री एस० के० सूद	चार्जमैन	चार्जमैन	1-3-69
37.	श्री राम दीन	तौलने वाला	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—
38.	श्री ए० एल० सीद्दीकी	—	गोदी निरीक्षक	—वही—
39	श्री बी० पी० मिश्र	—	प्रयोगशाला सहायक	—वही—
40.	श्री भगवान राम	—	वाचमैन	—वही—
41.	श्री एस० बी० यादव	—	—वही—	—वही—
42.	श्री भारत प्रसाद	—	—वही—	—वही—
43.	श्री एम० एन० पाठक	—	स्टीचर	—वही—
44.	श्री सत राज	—	डस्टिंग आपरेटर	—वही—
45.	श्री धर्म राज दूबे	—	वाचमैन	—वही—
46.	श्री जरबधन उपाध्याय	—	वाचमैन	—वही—
47.	श्री एस० गोपालन	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	गुण निरीक्षक-1	—वही—
48.	श्री एम० के० ए० बेग	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—	—वही—
49.	श्री एम० के० तिवारी	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
50	श्री एम० आर० शर्मा	विपणन निरीक्षक	विपणन निरीक्षक	—वही—
51.	श्री रमेश चन्द्र	डस्टिंग आपरेटर	डस्टिंग आपरेटर	1-3-69
52.	श्री पी० बी० सुभईया	—	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—
53.	श्री काली चरण (लाल)	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
54.	श्री सोन पाल	—वही—	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
55.	श्री एम० पी० जैन	वाचमैन	वाचमैन	1-3-69
56.	श्री बी० के० मिश्रा	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	—वही—
57.	श्री हजारी लाल	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
58.	श्री करण	स्वीपर	स्वीपर	—वही—
59.	श्री जय बहादुर	—	वाचमैन	—वही—
60	श्री आर० एम० आर० मूर्थी	वरिष्ठ लिपिक	वरिष्ठ लिपिक	—वही—
61.	श्री आर० के० मिश्रा	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
62.	श्री शिव शंकर सिंह	तौल लिपिक	कनिष्ठ गोदाम लिपिक	—वही—
63.	श्री अशर्फ अली	—	कनिष्ठ लिपिक	—वही—
64.	श्री उमा सिंह भदोरिया	—	—वही—	—वही—
65.	श्री कामता प्रसाद गोयल	गुण निरीक्षक	गुण निरीक्षक	—वही—
66.	श्री डी० आर० सिंह	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	जुलाई, 1971
67	श्री के० सी० त्रिपाठी	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	1-3-79
68.	श्री बाबू सैयद	तकनीकी सहायक	तकनीकी सहायक	—वही—
69.	श्री लक्ष्मण दास	डस्टिंग आपरेटर	डस्टिंग आपरेटर	—वही—
70.	श्री चन्द्र बहादुर	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
71	श्री नारायण सिंह सुपुत्र रामौतार	वाचमैन	वाचमैन	—वही—
72.	श्री देवी सिंह शर्मा	कनिष्ठ लिपिक	कनिष्ठ लिपिक	—वही
73.	श्री ओम प्रकाश	तौलने वाला	—वही—	—वही—
74.	श्री कालीचरण सुपुत्र बिन्दया प्रसाद	स्वीपर	स्वीपर	—वही—
75.	श्री मणी चरण सुपुत्र श्री कल्याण	स्वीपर	स्वीपर	—वही—
76	श्री केदार नाथ सुपुत्र श्री रघुनाथ	स्टीचर	डस्टिंग आपरेटर	—वही—
77.	श्री सतिश चन्द मेहता	—	गोदाम क्लर्क	—वही—
78.	श्री बी० के० दास गुप्ता	--	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—
79.	श्री डी० पी० श्रीवास्तव	कनिष्ठ गोदाम रक्षक	—वही—	—वही—
80.	श्री ए० कपुर	तौल लिपिक	गोदाम क्लर्क	—वही—
81.	श्री बी० एन० बैनर्जी	—	गोदाम क्लर्क	—वही—
82.	श्री रतन लाल	तकनीकी सहायक-1	तकनीकी सहायक-1	—वही—
83.	श्री मंगल दास	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
84.	श्री पी० एल० आहुजा	--	गुण निरीक्षक	—वही—
85.	श्री राजीउद्दीन	—	गोदाम क्लर्क	—वही—
86	श्री बी० एम० गुप्ता	—	तौल क्लर्क	—वही—
87.	श्री बी०एन० शर्मा	गोदाम क्लर्क	गोदाम क्लर्क	—वही—
88	श्री जगदीश प्रसाद वर्मा	वरिष्ठ गोदाम रक्षक	गोदाम अधीक्षक	—वही
89.	श्री सी० एन० सिंह	तौल क्लर्क	गोदी निरीक्षक	—वही—

[संख्या 52/1/79—एफ. सी० III (खंड-III)]

बख्शी राम, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1979

S.O. 3341.—Whereas the Central Government has ceased to perform the functions of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directors and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964(37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India;

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorate of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in reponse to the Circular of the Central Government dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified the rein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India as required by the proviso to sub-section (I) of Section 12A of the said Act,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date the Central Government hereby transfer the following officers and employees to the Food Corporation of India with effect from the Date mentioned against each of them.

S. No.	Name of the Officer/employees	Permanent posts held under the the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to the F.C.I.
1	2	3	4	5
1.	Sh. S. S. Ahluwalia	Asstt. Director	Asstt. Director	1-3-69
2.	Sh. T. H. Chetty	Quality Inspector	Quality Inspector	-do-
3.	Sh. R. M Sundram	Sr. Godown Keeper	Sr. Godown Keeper	-do-
4.	Sh. K. Pratap Chandran	Jr. Godown Keeper	Quality Inspector-I	-do-
5.	Sh. Babu Lal	Watchman	Watchman	-do-
6.	Sh. P. L. Hiteshi	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
7.	Sh. S. Hussain	Quality Inspector	Quality Inspector	-do-
8.	Sh. Kamla Kant Dass	Sr. Godown Keeper	Quality Inspector	-do-
9.	Sh. V. K. Srivastava	Jr. Godown Keeper	Jr. Godown Keeper	-do-
10.	Sh. Lal Bahadur S/o Nar Bahadur	Watchman	Watchman	-do-
11.	Sh. M. I. Khan	Jr. Clerk	Jr. Clerk	-do-
12.	Sh. Chandra Pal Sharma	—	Quality Inspector-I	-do-
13.	Sh. R. N. Tiwari	Sr. Godwn Keeper	Quality Inspector-I	-do-
14.	Sh. Ram Kumar Yadav	Watchman	Watchman	-do-
15.	Sh. Bindya Chal Maurya	Watchman	Watchman	1-3-69
16.	Sh. S. Razi Hussain	Sr. Clerk	Sr. Clerk	-do-
17.	Sh. P. N. Lal	Quality Inspector	Quality Inspector	-do-
18.	Sh. Hari Nath	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
19.	Sh. D. N. Shukla	Watchman	Watchman	-do-
20.	Sh. Ghasita Khan	-do-	-do-	-do-
21.	Sh. Sukh Lal	Sweeper	Sweeper	-do-
22.	Sh. Habib Mohd.	—	Technical Assistant	-do-
23.	Sh. R. N. Singh	—	Jr. Clerk	-do-
24.	Sh. N. V. Mathunni	—	Jr. Clerk	-do-
25.	Sh. Narinder Prakash Jyoti	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
26.	Sh. B. D. Bhardwaj	—	-do-	-do-
27.	Sh. T. N. Sharma	—	-do-	-do-
28.	Sh. Mahesh Ch. M. Shah	—	-do-	-do-
29.	Sh. J. P. Pokhariyal	Sr. Godown Keeper	Sr. Godown Keeper	-do-
30.	Sh. Brahm Singh	Jr. Clerk	Jr. Clerk	-do-
31.	Sh. Bhanu Prakash	—	Watchman	-do-
32.	Sh. Zile Singh Sirohi	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
33.	Sh. Om Prakash Sharma	-do-	Sr. Godown Keeper	15-9-71
34.	Sh. H A. R Siddiqui	Technical Asstt.	Tech. Assistant-I	1-3-69
35.	Sh. K. N. Dubey	Godown Clerk	Godown Clerk	12-5-70
36.	Sh. S. K. Sood	Chargeman	Chargeman	1-3-69
37.	Sh. Ram Din	Weighman	Jr. Godown Keeper	-do-
38.	Sh. A. L. Siddiqui	—	Dock Inspector	do-
39.	Sh. B. P. Misir	—	Lab. Assistant	-do-
40.	Sh. Bhagwan Ram	—	Watchman	-do-
41.	Sh. S. B. Yadav	—	-do-	-do-
42.	Sh. Bharat Prasad	—	-do-	-do-
43.	Sh. S. N. Pathak	—	Stitcher	-do-
44.	Sh. Sant Raj	—	Dusting Operator	-do-
45.	Sh. Dharam Raj Dubey	—	Watchman	-do-
46.	Sh. Jarbandhan Upadhya	—	Watchman	-do-
47.	Sh. S. G. Gopalan	Jr. Godown Keeper	Quality Inspector-I	-do-
48.	Sh. M. K. A. Beg	Sr.Godown Keeper	-do-	-do-
49.	Sh. S. K. Tiwari	Watchman	Watchman	-do-
50.	Sh. M. R. Sharma	Marketing Inspector	Marketing Inspector	-do-
51.	Sh. Ramesh Chandra	Dusting Operator	Dusting Operator	-do-
52.	Sh. P.V. Subbalyya	—	Jr. Godown Keeper	-do-
53.	Sh. Kali Charan (Lal)	Watchman	Watchman	-do-
54.	Sh. Son Pal	-do-	-do-	-do-
55.	Sh. M. P. Jain	-do-	-do-	-do-

1	2	3	4	5
56.	Sh. B. K. Sinha	Quality Inspector	Quality Inspector	1-3-69
57.	Sh. Hazari Lal	Watchman	Watchman	-do-
58.	Sh. Karan	Sweeper	Sweeper	-do-
59.	Sh. Jai Bahadur		Watchman	-do-
60.	Sh. Bh. S. R. Murthy	Sr. Clerk	Sr. Clerk	-do-
61.	Sh. R. K. Mishra	Watchman	Watchman	-do-
62.	Sh. Shiv Shanker Singh	Weightment Clerk	Jr. Godown Clerk	-do-
63.	Sh. Asraf Ali	–	Jr. Clerk	-do-
64.	Sh. Uma Singh Bhadoria	—	-do-	-do-
65.	Sh. Kamta Prasad Goel	Quality Inspector	Quality Inspector	-do-
66.	Sh. D. R. Singh	Godown Clerk	Godown Clerk	July, 1971
67.	Sh. K. C. Tripathi	Sr. Godown Keeper	Sr. Godown Keeper	1-3-69
68.	Sh. Abu Sayeed	Technical Asstt.	Technical Asstt.	-do-
69.	Sh. Luxman Dass	Dusting Operator	Dusing Operator	-do-
70.	Sh. Chandra Bahadur	Watchman	Watchman	-do-
71.	Sh. Narain Singh S/o Ram Avtar	Watchman	Watchman	-do
72.	Sh. Devi Singh Sharma	Jr. Clerk	Jr. Clerk	-do-
73.	Sh. Om Prakash	Weighman	-do-	-do-
74.	Sh. Kali Charan S/o Bidya Prasad	Sweeper	Sweeper	-do-
75.	Sh. Mashi Charan S/o Sh. Kalyan	Sweeper	Sweeper	-do-
76.	Sh. Kedar Nath S/o Sh. Raghu Nath	Stitcher	Dusting Operator	-do-
77.	Sh. Satish Chand Mehta	—	Godown Clerk	-do-
78.	Sh. B. K. Dass Gupta	—	Sr. Godown Keeper	-do-
79.	Sh. D. P. Srivastava	Jr. Godown Keeper	-do-	-do-
80.	Sh. A. Kujur	Weighment Clerk	Godown Clerk	-do-
81.	Sh. B. N. Banerjee	—	Godown Clerk	-do-
82.	Sh. Rattan Lal	Tech. Assistant-I	Tech. Assistant -I	-do-
83.	Sh. Mangal Dass	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
84.	Sh. P. L. Ahuja	—	Quality Inspector	-do-
85.	Sh. Raziuddin	—	Godown Clerk	-do-
86.	Sh. B. M. Gupta	—	Weighment Clerk	-do-
87.	Sh. B. N. Sharma	Godown Clerk	Godown Clerk	-do-
88.	Sh. Jagdish Prasad Verma	Sr. Godown Keeper	Godown Supdt.	-do-
89.	Sh. C. N. Singh	Weignment Clerk	Dock Inspector	-do-

[No. 52/1/79-FC.III(Vol. III]

BAKSHI RAM, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1979

का०आ० 3342.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 635, तारीख 12 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

(i) "भाग 1—साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3" में, "उपतकनीकी सलाहकार के कार्यालय और उनके अधीन एककं" शीर्ष के अन्तर्गत, स्तम्भ 2, 3 और 5 में, "उप सचिव काडर प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "निदेशक काडर प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) "भाग 2—साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4" में, "उपतकनीकी सलाहकार के कार्यालय और उनके अधीन एककं" शीर्ष के अन्तर्गत, स्तम्भ 5 में, "उप सचिव काडर प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "निदेशक काडर प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० सी०-11012/3/74-ए वी यू]

एस० एस० कम्बोह, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 1979

S.O. 3342.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the Notifications of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food) No. G.S.R. 635, dated the 12th January, 1971, namely :—

In the Schedule to the said Notification :

(i) In "Part I—GENERAL CENTRAL SERVICES, CLASS III" under the heading "Offices of the Deputy Technical Adviser and Units thereunder" in columns 2, 3 and 5 for the words "Deputy Secretary Cadre Authority", the words "Director Cadre Authority" shall be substituted.

(ii) In "PART II—GENERAL CENTRAL SERVICES CLASS IV" under the heading "Offices of the Deputy Technical Adviser and units thereunder" in Column 5 for the words "Deputy Secretary Cadre Authority" the words "Director Cadre Authority" shall be substituted.

[No. C-11012/3/74-AVU]

S. L. KAMBOH, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1979

का०आ० 3343.—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा 57 के अन्तर्गत बनाये गये दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं के प्रबन्ध एवं निपटान) विनियम, 1968 से सलग्न शाश्वत् पट्टा विलेख की धारा (22) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आदेश स० एफ० 1(1)/68-एच बी०—भाग 2 दि० 13-5-71 के आंशिक संशोधन मे, मैं एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष, दि० वि० प्रा० एतद्द्वारा सभी कार्यकारी अधिकारियों (आवास) एव उप-निदेशकों (आवास) को पदेन आवास अधिकारी के रूप मे पद नामित करता हूं तथा उक्त शाश्वत् पट्टा-विलेख के सम्बन्ध मे समस्त सूचनाओ, आदेशों, निदेशो, सहमतियो अथवा अनुमोदनो पर हस्ताक्षर करने को निष्पादित करने का अधिकार प्रदान करता हू ।

उक्त कार्यकारी अधिकारी (आवास) एव उपनिदेशक (आवास) द्वारा दि० 13-9-1977 से अधिसूचना जारी करने की तिथि की अवधि तक उक्त विनियमो से सलग्न शाश्वत् पट्टा-विलेख के अनुच्छेद (22) मे वर्णित सभी विषयो से सम्बन्धित सभी निष्पादित कार्यों का भी मै अनुसमर्थन करता हू ।

[सं० एफ० 1(1)/79—समन्वय]

एम० एन० बुच, उपाध्यक्ष

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 4th September, 1979

S.O. 3343.—In exercise of powers conferred by clause (22) of Perpetual Lease Deed appended to the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, framed under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957) and in partial modification of Order No. F. 1(1)/68-HB Pt. II dated 13-5-71, I, M. N. Buch, Vice Chairman, D.D.A. hereby designate all Executive Officer (H) and Dy. Director (H) as Ex-officio Housing Officers and authorised them to sign all notices, orders, directions, consents or approvals in respect of the matters provided in the said Perpetual Lease Deed.

I also ratify all actions taken by such Executive Officers (H) and Dy. Directors (H) during the period from 13-9-1977 to the date of issue of this notification in all cases in respect of the matters enumerated in clause 22 of the Perpetual Lease Deed appended to the said Regulations.

[No. F. 1(1)/79-Coordn.]

M. N. BUCH, Vice-Chairman

संचार मंत्रालय

(महानिदेशक का कार्यालय, विदेश संचार सेवा)

बम्बई, 3 सितम्बर, 1979

का०आ० 3344—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनो के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अनुसरण मे विदेश संचार सेवा के निम्नलिखित कार्यालयो को, जिनके 80% कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है:—

1. उप महानिदेशालय, विदेश संचार सेवा (नई दिल्ली शाखा), नई दिल्ली ।
2. निदेशालय, विदेश सचार सेवा, देहरादून, उ०प्र० ।

[का०आ० सं० 13/1/79—प्रशा०]

पा० कि० गोविन्द नायर, निदेशक

कृते महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Office of the Director General, Overseas Communications Service)

Bombay, the 3rd September, 1979

S.O. 3344.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the following offices of the Overseas Comunications Service, Government of India, 80 per cent of the Staff where of, have acquired the working knowledge of Hindi, are hereby notified :—

1. Office of the Deputy Director General, Overseas Comunications Service, (Now Delhi Branch), New Delhi.
2. Office of the Director, Overseas Communications Service, Dehradun, U.P.

[S.O. No. 13/1/79-Admn.]

P. K. G. NAYAR, Director (Admn.)
For Director General

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली 10 सितम्बर 1979

का०आ० 3345—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वेलमुरुगन मेच इण्डस्ट्रीज, 18, मैच फैक्टरी टोपे स्ट्रीट, सान्तापेट, गुड्डियात्तम उत्तर आर्काट जिला, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अत, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1975 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[स० एम० 35019/179/79-पी० एफ०-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 10th September, 1979

S.O. 3345.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Velmurugan Match Industries, 18, Match Factory Thope Street, Santhapet, Guddiyattam North Arcot District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment,

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1975.

[No. S-35019/179/79-PF-II]

का०आ० 3346.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डा० अम्बेदकर हरिजन कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई सोसाइटी लिमिटेड, टी०बी०ओ० 65, 55, परसुराम मैकर स्ट्रीट, एर्नी, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए.

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[स० एस० 35019/174/79—पी० एफ०-2]

S.O. 3346.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dr. Ambedkar Harijan Co-operative Milk Supply Society Limited, T.P.O. 65, 55, Parasurama Naicker Street, Arni, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35019/174/79-PF-II]

का० आ० 3347.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० वी० कंडासामी मुदलियार, थोक वस्त्र व्यापारी, 22, कांग्रेस हाउस रोड, गुडियाटम, उत्तरी आर्कोट, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/176/79—पी० एफ०—2]

S.O. 3347.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. V. Kandasamy Mudaliar, Wholesale Cloth Merchant, 22, Congress House Road, Gudiyattam, North Arcot, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1976.

[No. S. 35019/176/79-PF. II]

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1979

का० आ० 3348.—त्रिपुरा राज्य ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अनुसरण में श्री के० बी० गुरुंग के स्थान पर श्री एस० के० घोषाल, सचिव, त्रिपुरा सरकार, श्रम विभाग, अगरतला को चिकित्सा प्रसुविधा परिषद् में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2980, दिनांक 26 जुलाई, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "(सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)", शीर्षक के नीचे मद 21 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री एस० के० घोषाल,

सचिव, त्रिपुरा सरकार,

श्रम विभाग,

अगरतला"

[सं० यू०-16012/6/78—एच० आई०]

New Delhi, the 13th September, 1979

S.O. 3348.—Whereas the State Government of Tripura has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri S. K. Ghosal, Secretary to the Government of Tripura, Labour Department, Agartala to represent that State on the Medical Benefit Council in place of Shri K. B. Gurung ;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 10 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2980, dated the 26th July, 1976, namely :—

In the said notification under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of sub-section (1) of section 10)" for the entry against item 21, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri S. K. Ghosal,

Secretary to the Government of Tripura,

Labour Department, Agartala".

[No. U-16012/6/78-HI]

का०आ० 3349.—त्रिपुरा राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री के० बी० गुरुंग के स्थान पर श्री एस० के० घोषाल, सचिव, त्रिपुरा सरकार श्रम विभाग, अगरतला को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 1517 दिनांक 14 अप्रैल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "(राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट)" शीर्षक के नीचे मद 25 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"श्री एस० के० घोषाल,

सचिव, त्रिपुरा सरकार,

श्रम विभाग, अगरतला ।"

[संख्या यू० 16012/6/78—एच० आई०]

S.O. 3349.—Whereas the State Government of Tripura has in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri S.K. Ghosal, Secretary, to the Government of Tripura, Labour Department, Agartala to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri K. B. Gurung;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1517, dated the 14th April, 1976, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4)", for the entry against item 25, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri S. K. Ghosal,

Secretary to the Government of Tripura,

Labour Department, Agartala".

[No. U-16012/6/78-HI]

का०आ० 3350.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स विक्टर टेलर्स, 12-बी, इलियट रोड, कलकत्ता-16, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 39) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017/37/79-पी० एफ०-2]

S.O. 3350.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Victor Tailors 12B, Elliot Road, Calcutta-700016 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of May, 1978.

[No. S-35017/37/79-PF.II]

का०आ० 3351—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स रजनी इन्टरप्राइजेज, 1, लिंडसे स्ट्रीट (दूसरा फ्लोर), कलकत्ता-16ह नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017/38/79 पी०एफ० 2]

S.O. 3351.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Rajni Enterprises, 1, Lindsay Street (2nd Floor), Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35017/38/79-PF.II]

का०आ० 3352.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्द ओवरसीज कारपोरेशन, 1, लिंडसे स्ट्रीट, कलकत्ता-16, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017/39/79-पी० एफ०-2]

S.O. 3352.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hind Overseas Corporation, 1, Lindsay Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1978.

[No. S. 35017/39/79-PF.II]

का०आ० 3353—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स चक्र मोटर लंच सर्विसेज, डाक घर केनिंग टाउन, जिला 24-परगना, पश्चिमी बंगाल, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 28 फरवरी, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017/40/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3353.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Chakra Motor Launch Services, Post Office Canning Town, District 24-Parganas, West Bengal, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the twenty-eighth day of February, 1978.

[No. S. 35017/40/79-PF.II]

का०आ० 3354.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्दुस्तान टी एक्सपोर्टर्स, 16, मंगोई लेन, कलकत्ता-1, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35017/42/79 पी०एफ० 2(i)]

S.O. 3354.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hindustan Tea Exporters, 16, Mangoe Lane, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1978.

[No. S. 35017/42/79-PF. II(i)]

का०आ० 3355.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 मई, 1978 से मैसर्स हिन्दुस्तान टी एक्सपोर्टर्स 16, मंगोई लेन कलकत्ता-1,

नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा० सं० एम०-35017/42/79-पी०एफ० 2(2)]

S.O. 3355.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of May, 1978 the establishment known as Messrs. Hindustan Tea Exporters, 16, Mangee Lane, Calcutta-1, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017/42/79-PF. II(ii)]

का०आ० 3356.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मुरूगेसन एंड ब्रदर्स, जी 6 और 7, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पुडुक्कोट्टाई-4, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/139/79—पी०एफ० 2]

S.O. 3356.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Murugesan and Brothers, G, 6 and 7, Industrial Estate, Pudukkottai-4, have agreed that the proviions of the Employees' Providnt Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1977.

[No. S. 35019/139/79-PF-II]

का०आ० 3357.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स शनमुगन ट्रेडिंग कारपोरेशन, 4/20, नारायणा विधि कोट्टर, नागरकोइल-2, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/161/79—पी०एफ० 2]

S.O. 3357.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shunmugam Trading Corporation, 4/20, Narayana Veedhi, Kottar, Nagercoil-2 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of December, 1978.

[No. S. 35019/161/79-PF.II]

का०आ० 3358.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स साउदर्न टेनिंग कम्पनी, गुडियाट्टम रोड, वलाथूर, उत्तरी आर्काट, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/163/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3358.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relatioun to the establishment known as Messrs Southern Tanning Company, Gudiyattam Road, Valathoor, North Arcot, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1976.

[No. S. 35019/163/79-PF.II]

का०आ० 3359.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स अमेरजोथी फैब्रिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जवाहर नगर, करूर, त्रिची नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/165/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3359.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Amerjothi Fabrics (Private) Limited, Jawahar Nagar, Karur, Trichy, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1976.

[No. S. 35019/165/79-PF.II]

का०आ० 3360.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स थीरू हीरूदया गिन्निंग फैक्टरी एंड राइस मिल, कल्लाकुडि, डालमिया पुरम, त्रिची जिला, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जुलाई, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/168/79-पी० एफ० 2]

S.O. 3360.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Thiru Hirudaya Ginning Factory and Rice Mill, Kallakud, Dalmiapuram, Trichy District, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of July, 1976.

[No. S. 35019/168/79-PF. II]

का०आ० 3361.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए०एस०आर०एम० सुब्बैया पिल्लई, 6, दक्षिणी फाटक, मैलम, त्रिची-8, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अगस्त, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/169/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3361.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.S.R.M. Subbiah Pillai, 6, South Gate, Mailam, Trichy-8, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1976.

[No. S. 35019/169/79-PF. II]

का०आ० 3362.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स श्री कन्निका परमेश्वरी फिनान्सिंग कारपोरेशन, 630, बाजार स्ट्रीट, करूर, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एम० 35019/170/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3362.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Shri Kannika Parameswari Financing Corporation, 630, Bazar Street, Karur have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of November, 1976.

[No. S. 35019/170/79-PF. II]

का०आ० 3363.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स फाइन निटिंग मिल्स, 10, देवंगापुरम स्ट्रीट, तीरूपुर-638602, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35019/171/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3363.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Fine Knitting Mills, 10, Devangapuram Street, Tiruppur-638602, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1977.

[No. S. 35019/171/79-PF. II]

का० आ० 3364.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कुम्बा का सिल्क व्यापारी, सं० 90, सन्नाटी स्ट्रीट, तीरूबुवनम, कुम्बाकोणम तालुक, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1976 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/172/79-पी०एफ० 2]

S.O. 3364.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in reation to the establishment known as Messrs Kumba's Silk Merchant, No. 90, Sannadhi Street, Thirubuvanam, Kumbakonam Taluk, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March, 1976.

[No. S. 35019/172/79-PF. II]

का०आ० 3365.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दि कुलासेखरम विलेज कोआपरेटिव एग्रिकलचरल क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, नं० वाई, 256, कुलासेखरम, कुलासेखरम डाक घर, नाम स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 सितम्बर, 1977 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35019/173/79-पी०एफ० 2(1)]

S.O. 3365.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs The Kulasekharam Village Co-operative Agricultural Credit Society Limited, No. Y-256, Kulasekharam, Kulasekharam Post Office, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of September, 1977.

[No. S. 35019/173/79-PF. II(i)]

का०आ० 3366.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघद्ध विषय में आवश्यक जाच करने के पश्चात् 1 सितम्बर, 77 से मैसर्स दि कुलासेखरम विलेज कोआपरेटिव एग्रिकलचरल क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, नं० वाई 5256, कुला!खरम, कुलासेखरम डाक घर, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है ।

[फा० सं० एस-35019/173/79 पी० एफ-2(2)]

S.O. 3366.—In exercise of the pwers conferred by the first proviso to section 6 of the Empoyees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of September, 1977 the establishment known as Messrs. The Kulasekharam Village Co-operative Agricultural Credit Soceity Limited, No. Z-256, Kulasekharam, Kulasekharam Post Office, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019/173/79-PF.II(ii)]

का० आ० 3367.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स गोल्डेन एसबेस्टॉस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, अवनाशी, कोयम्बटूर-14, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 फरवरी, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[स० एस० 35019/177/79-पी० एफ-2]

हंसराज छाबड़ा, उपसचिव

S.O. 3367.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Golden Asbestos Manufecturing Company, Avanashi, Coimbatore, have agreed that the provision of the employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of February, 1979.

[No. S. 35019/177/79-PF.II]
HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1979

का० आ० 3368.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण मे, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1006 तारीख 7 मार्च, 1979 द्वारा सीसा खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 25 मार्च, 1979 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनो के लिए 25 सितम्बर, 1979 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या ए०-11017/2/79/जी/1(ए) (ii)]

New Delhi, the 12th September, 1979

S.O. 3368.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required, had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1006 dated the 7th March, 1979 the Lead mining industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th March, 1979;

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the

Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 25th September, 1979.

[No S. 11017/2/79/DI(A)(ii)]

का० आ० 3369.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2, के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1005 तारीख 7 मार्च, 1979 द्वारा जिंक खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 मार्च, 1979 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है।

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 17 सितम्बर, 1979 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017/2/79/डी 1 ए(i)]

S.O. 3369.—Whereas the Central Government being satisfied that the public interest so required had declared by a notification made in pursuance of the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), being the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1005 dated the 7th March, 1979 the Zinc mining Industry to be a public utility service for the purpose of the said Act, for a period of six months from the 17th March, 1979;

And whereas the Central Government is of the opinion that the public interest requires the extension of the said period by a further period for six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a further period of six months from the 17th September, 1979.

[No. S. 11017/2/79/DIA(i)]

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 1979

का० आ० 3370.—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1120 तारीख 21 मार्च, 1979 द्वारा ताँबा खनन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1979 से छः मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उपखण्ड (6) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 अक्टूबर, 1974 से छः मास की और कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[सं० एस० 11017/4/79/डी 1(ए)]
एल० के० नारायणन्, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 14th September, 1979

S.O. 3370.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest so required had in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1120 dated the 21st March, 1979, the Copper Mining Industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 1st April, 1979,

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 1st October, 1979.

[No. S. 11017/4/79/DI(A)]
L. K. NARAYANAN, Desk Officer.

New Delhi, the 5th September, 1979

S.O. 3371.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby, publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employer in relation to the management of Chinakuri Pits 3 Colliery of Chinakuri, Sub-Area of Eastern Coalfields Limited, Sanctoria, Post Office Sunderchak, Burdwan and their workmen which was received by the Central Government on 4th September, 1979.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 65 of 1978

PARTIES :

Eployers in relation to the management of Chinakuri Pits 3 Colliery of Chinakuri Sub-Area, E.C.L., Sanctoria, P.O. Sunderchak, Burdwan,

AND

Their Workmen

PRESENT :

Sri Justice S. K. Mukherjee—Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Sri S. M. Ashraf, Asstt. Chief Personnel Officer.

On behalf of Workmen—Absent.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal Mine.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by their Order No. L-19012/7/77-D-III(B)/D-IV(B), dated 19th July, 1978 referred an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Chinakuri Pits 3 Colliery of Chinakuri Sub-Area, E.C.L., Sanctoria and their workmen, to this tribunal, for adjudication. The reference reads :

"Whether the action of the management of Chinakuri 3 Pits Colliery of Chinakuri Sub-Area, Eastern Coalfields Ltd, in suspending S/Shri Golap Chand and Niranjan Majhee with effect from 17-1-76 to 24-1-76 and 8-4-76 to 12-4-76 respectively is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. The parties duly filed their pleadings. Thereafter the case was fixed for hearing today. At the hearing a Memorandum of settlement by which the parties sought to dispose of the reference was filed. I have gone through the terms of Settlement and am of opinion that the terms are fair and reasonable. A copy of the said Memorandum of Settlement is annexed hereto as a part of this Award.

3. In the result, I make my award in terms of the Memorandum of Settlement referred to above.

Dated, Calcutta,
The 29th August, 1979.

Sd/-
S. K. MUKHERJEE, Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

Reference 65 of 1978

Employer's relationship of Chinakuri III Pit Colliery and their workmen.

PETITION OF COMPROMISE

The parties submit by a settlement dated 6-8-1979 the dispute between the parties have been settled amicably between them, a copy of which is being filed herewith.

That settlement will show that the terms are fair and reasonable and completely resolves the dispute.

The parties, therefore, pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to give its award in terms of the settlement. For & on behalf of the workmen.

(N. N. Sinha)
Vice-President
COLLIERY MAZDOOR CONGRESS
(H.M.S.)

For & on behalf of the Management.

Ranadhir Prisma.

Memorandum of Settlement between the Management of Chinakuri III Pit Colliery of Chinakuri, Sub Area of M/s. Eastern Coalfields Limited, P.O. Sundarchak, Dist Burdwan and their workmen represented by Colliery Mazdoor Congress (HMS), Asansol, Dt. 27th March, 1979.

Present on behalf of the workmen,

1. Shri N. N. Sinha Vice-President : CMC (HMS), Bengal Hotel, Asansol.

Present on behalf of the Management.

1. Sri S. M. Ashraf, Asst. Chief Personnel Officer (IR), D.A.

SHORT RECITAL OF THE CASE.

Sri Golap Chand, who is working as Tyndal and Sri Niranjan Majhee, Asst. Foreman (Elec.) in the Chinakuri III Pit were suspended following issue of Chargesheets to them for misconduct.

So far as Sri Golap Chand is concerned the allegations against him were that he was directed by the supervisor to go to OX-cut and X-Cut for shifting of electrical machinery but he behaved indecently with the Supervisor and did not obey the order. So far as Sri Niranjan Majhee is concerned, on 24-11-75 while he was on duty in the second relay at about 6.00 P.M. a break-down occured at 8X-Cut section of the Mine in the mono pump starter which was attended by Sri Majhee. He, however, failed to rectify the defect upto 10.50 P.M. He was advised to run the pump by making direct connection but he had failed to run the Pump and had intentionally disconnected and damaged the contractor leading to other risk of the section itself.

As stated above chargesheets were isued and after enquiry while Sri Golap Chand was suspended for 8 days by way of punishment, Sri Majhee was ordered to be suspended for a period of 5 days. The Union took up their cases and after failure in the conciliation, a reference (being Ref. No. 65 of 1978) was made before the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, where it is pending.

The parties have since decided to settle the dispute and with that end in view a number of meetings were held in cordial atmosphere. Both parties agree that the dispute be settled on the following terms :

1. Sri Golap Chand will be entitled to get his wages for 8 days in respect of which the suspension is being revoked.

2 Similarly Sri Niranjan Majhee will be paid his wages for five days in respect of which the suspension is being revoked.

3. That they will not claim anything else by way of compensation, cost or otherwise.

4. A copy of the settlement shall be filed before the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta with the prayer that the settlement be accepted and award be kept in terms of the settlement.

5. A copy of his settlement shall also be forwarded to conciliation Officer (ALC(C), Asansol for his records.

For & on behalf of the workmen

1. Sri N. N. Sinha,

Vice-President

Colliery Mazdoor Congress

(H. M. S.)

For and behalf of the management.

1. Sri S. M. Ashraf.

Witnesses :

1. R. N. P. Singh
2. B. B Roy

[No. L. 19012(7)/77-D.III(B)/D.IV(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

का० आ० 3372.—मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की ईस्ट निमचा कोलियरी, डाकघर जेकेनगर, जिला बर्दवान के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) आसनसोल करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और उक्त नियोजको और कर्मकारो ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबंधो के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 30 अगस्त, 1979 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन**)

पक्षकारो के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले — 1. श्री एस० एस० बनर्जी, उप कार्मिक प्रबन्धक, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सतग्राम क्षेत्र, डाकघर देव चान्दनगर जिला बर्दवान

कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करने वाले — 1 श्री एस० के० पाडे, मंत्री कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०), गोराई मेंशन्स जी० टी० रोड, डाकघर आसनसोल बर्दवान).

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एस० एन० पाडे, कार्मिक निदेशक, टिस्को, जमशेदपुर के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

(i) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

"क्या मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की ईस्ट निमचा कोलियरी, डाकघर जेकेनगर, जिला बर्दवान के प्रबन्धतंत्र की सर्वश्री आर० एन० तिवारी खनन सरदार (2) अम्बिका सिंह, खनन सरदार (3) जमशेर खान, सुरक्षा गार्ड (4) माजिद खान, खनन सरदार और (5) तायेब खान, लाइन मिस्त्री को 31-10-78 से बर्खास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

(ii) विवाद के पक्षकारो का विवरण, जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है :

(1) उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड की निमचा उपक्षेत्र, डाकघर जेकेनगर (बर्दवान)

(2) महामंत्री, कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) गोराई मेंशन्स, जी० टी० रोड़, डाकघर आसनसोल (बर्दवान).

(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह विवाद में स्वयं शामिल है या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम : कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले } मंत्री, कोयला मजदूर कांग्रेस (एच० एम० एस०) गोराई मेंशन्स, डाकघर आसनसोल (बर्दवान).

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या : लगभग 3900

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :

5

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा ।

मध्यस्थ अपना पंचाट समुचित सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

ह०/ (एस० के० पांडेय) ह०/- (एस० एस० बनर्जी)
तारीख 16-6-79 तारीख 16-6-79

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

मैं उपयुक्त मामले में मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हूं ।

ह०/- (एस० एन० पांडेय)

साक्षी : 1. ह०/-(अपाठ्य)
ता० 16-6-79

2. ह०/- (अपाठ्य)
ता० 16-6-79

[संख्या एल-19013(9)/79-डी० 4(बी)]

शशि भूषण, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 10th September, 1979

S.O. 3372.—Whereas an industrial dispute exists between the management of East Nimcha Colliery, Post Office Jaykaynagar, District Burdwan of Messers Eastern Coalfields Limited and their workmen represented by the Koyala Mazdoor Congress (HMS) Asansol;

And whereas the said maegnament and their workmen have by a written agreement in pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration of the person mentioned therein and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (3) of Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the said Arbitration agreement which was received by the Central Government on 30th August, 1979.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties :

Representing the employer.—(1) Shri S. S. Banerjee, Dy. P. M. Satgram Area of Eastern Coalfields Limited, P.O. Devchandnagar, Distt. Burdwan.

Reprsenting the workmen.—(1) Shri S. K. Pandey, Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansions, G. T. Road, P.O. Asansol (Burdwan).

It is hereby agreed between the parties to refer the following disputes to the arbitration of Shri S. N Pandey, Director Personnel, TISCO, Jamshedpur.

(i) Specific matters in disputes :

"Whether the action of the management of East Nimcha Colliery, P.O. Jaykaynagar, Dist. Burdwan of M/s. Eastern Coalfields Ltd. was justified in dismissing from service S/Shri R. N. Tewari, Mining Sirdar, (2) Ambika Singh, Mining Sirdar (3) Jamsher Khan, Security Guard, (4) Majid Khan, Mining Sirdar and (5) Tayeb Khan, Line Mistry with effect from 31-10-1978 ? If not, to what relief the workmen are entitled?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved :

(1) The Sub-Area Manager, Nimcha Sub-Area of Eastern Coalfields Limited,, P.O. Jaykaynagar (Burdwan).

(2) The General Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansions, G.T. Road, P.O. Asansol (Burdwan).

(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen in question.

Represnting the workmen.—The Secretary, Koyala Mazdoor Congress (HMS) Gorai Mansions, P.O. Asansol (Burdwan)

(iv) Total No. of workmen employed in the undertaking affected : about 3900.

(v) Estimate No. of workmen affected or likely to be affected by the dispute : 5

We further agree that decisions of the Arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of 30 (thirty) days from the date of publication of this agreement in the official Gazette by the appropriate Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall

stand automatically cancelled, and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Sd/-

Sd/-

(S. K. PANDEY)/dt. 16-6-79 (S. S. BANERJEE dt. 16-6-79)
Representing the workmen Representing the employer

I, hereby give my consent to be Arbitrator in the above case.

Sd/-

(S. N. PANDEY)

Witnesses :

1. Sd/- (Illegible) Dt. 16-6-79.

2. Sd/- (Illegible) dt. 16-6-79.

[No. L. 19013(9)/79-D. IV(B)]

SHASHI BHUSHAN, Desk Officer

New Delhi, the 11th September, 1979

S.O. 3373.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (114 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi in the industrial dispute between the management of Oriental Fire & General Insurance Company Limited, New Delhi and their workmen which was received by the Central Government on 10th September, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 1 of 1979

BETWEEN

The General Secretary,
Oriental Fire & General Insurance Employees' Association,
412, Mandawali, Fazalpur,
Delhi.

AND

The General Manager,
Oriental Fire & General Insurance Co. Ltd.,
Jeevan Udyog, A-25/27, Asaf Ali Road,
New Delhi-110002.

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. made a reference u/S 10 of the I.D. Act, 1947 vide its order No. L-17013(2)/78-D.IV(A), dated the 30th December, 1978 to this Tribunal in the following terms :

(i) Whether the management of Oriental Fire and General Insurance Company Limited are required to implement clauses 3(ii)(d), (e) and 3(iii) of the settlement dated the 27th November, 1970 for the period 1-7-1973 to 26-5-1974 even after the coming into force of the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974 with effect from the 27th May, 1974, which does not include any clause barring the promotion ?

(ii) Whether the said management are required to implement the above-mentioned clauses of the above-mentioned settlement dated the 27th November, 1970 after the 27th May, 1974 ? If so, to what relief are the employees concerned entitled ?

2. On receipt of this reference usual notices were sent to the parties whereupon Shri J. P. Jain put in appearance on behalf of the Employees' Association and Mrs. V. Rao for the Insurance Company and it was ordered that a statement of claim be filed. But thereafter none appeared for the workman in consequence ex-parte proceedings were ordered against the workmen—Association and the Management was directed to file its statement of claim. Thereafter once again Shri J. P. Jain, General Secretary of the Association appeared and requested for permission to file statement of claim which permission was granted and the case was adjourned to 22nd August for this purpose but once again on 22nd August none appeared for the Association while Mrs. V. Rao appeared for the Management and consequently ex-parte proceedings were again ordered against the Association and the case was adjourned for filing of statement of claim of the Insurance Company on 3rd September, 1979. Strangely enough on 3rd September, 1979 neither the representative of the employers' association nor that of insurance company put in their appearance. No statement of claim was received from both of the parties and in these circumstances I had no option but to proceed to determine this matter in the absence of both the parties.

3. In so far as no statement of claim has been filed by the Association which had raised the dispute and in so far as the burden of establishing and in so far as the burden of establishing both the claims in the schedule to the order of reference was upon the Association both these questions referred to are answered in the negative and an award is hereby made that the employees are not entitled to any relief whatso-ever in this reference. Parties are left to bear their own costs.

Dated : the 5th September, 1979.

FURTHER AWARDED :

Requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Govt. for necessary action at their end.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

Dated : the 5th September, 1979.

[No. L. 117013(2)/78-D.IV(A)]

New Delhi, the 13th September, 1979

S.O. 3374.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal (Central), Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their workmen which was received by the Central Government on 11th September, 1979.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD

Dated : 6th August, 1979

Industrial Dispute No. 2 of 1979

BETWEEN

Workmen of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam.—Workmen

AND

The Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam—Management.

This industrial dispute coming for final hearing before me today upon perusing the reference, claim statement, counter and other material papers on record and upon hearing both the parties and having stood over for consideration till this day, the Tribunal passed the following :—

AWARD

On an industrial dispute that arose between the Management of Visakhapatnam Port Trust, Visakhapatnam and their Workmen in respect of the matters specified in the Schedule,

the Government of India by its Order dated 8-2-1979 referred the same to this Tribunal for adjudication under Section 10(1) (d) of the Industria Disputes Act, 1947.

SCHEDULE

"Whether the management of Visakhapatnam Port Trust are justified in amalgamating the posts of Loco Drivers and Senior Loco Drivers into one Cadre having the scale of pay of Rs. 465—725 in place of two existing cadres of Loco Drivers Diesel in the scale of Rs. 465—725 and Senior Driver Diesel B.G. Loco in the scale of Rs. 575—840 ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The facts that gave rise to this reference are briefly the following :—Amongst the various workmen employed in Visakhapatnam Port, Loco Drivers from one class who were originally divided into four categories, in different scales of pay, viz, (i) Driver (Diesel NG Loco) in the scale of Rs. 150—253; (2) Sr. Driver (Diesel NG Loco) in the scale of Rs. 170—290; (3) Driver (Diesel BG Loco in the scale of Rs. 190—280; and (4) Sr. Driver (Diesel B.G. Loco) in the scale of Rs. 246—354. The Government of India appointed a Wage Revision Committee to go into the question of revision of pay scales etc., of the Port and Dock Workers in all the major ports. That Committee recommended 24 scales grouping the then existing scales into 24 groups. The pay scales of the four categorie of Drivers, referred to above were revised and fixed at Rs. 425—655; 450—700; 450—700 and 575—840 respectively. In during so, the Wage Revision Committee also made a special recommendation to the effect that Loco drivers of all ports shall be given the scale of Rs. 465—725. The Government and the representatives of the Federation of Port and Dock Workers, by an agreement dated 14-7-1977 accepted the recommendations of the Wage Revision Committee with slight modifications, in pursuance of which, the loco drivers referred to against S. Nos. 1 to 3 where given the scales of Rs. 465—725 while the senior loco drivers mentioned against S. No. 4 were given the scale of Rs. 578—840.

3. Alleging taht the Management of the Port Trust, Visakhapatnam, merged the two categories, into one scale of Rs. 465—725 in July, 1978 without any reasonable cause and without even consulting the Union and that the Management is not justified in doing so, which affects the right of the Senior Loco Drivers, a dispute was raised by the affected workmen through their Union Effort at Conciliation having failed, the **Government of India, after satisfying itself about the existance of an industrial dispute between the workmen and the management, referred the same to this Tribunal for adjudication.**

4. The workmen, in their claim statement have pleaded that the action of the management in merging the two categories of loco drivers into one category in the scale of Rs. 465—725, contrary to the agreement dated 14-7-1977 and thereby denying the higher scale of Rs. 575—840 to Senior Loco Drivers, is not justified, that the Management did so because of its hostility toward the Union of which the senior loco drivers are members and that since the above action of the management is nothing short of unfair labour practice, an award may be passed restoring the higher scale of pay to senior loco drivers (Diesel B.G. Loco.).

5. The Management in its counter while denying all the adverse allegations made by the workmen in their claim statement, has pleaded that the Wage Revision Committee's recommendations have been strictly complied with, that the senior diesel B.G. loco drivers are not deprived of the higher scale as the difference between the uniform scale of Rs. 465-10-515-EB-12-635-EB-15-725 recommended by Wage Revision Committee, and the scale of Rs. 575-15-680-EB-20-840 was treated as personal scale to the senior drivers already working, that at no time the management accepted two categories of Loco drivers with two distinct scales of pay, that even the workmen never disputed the same, that the workmen cannot go behind the agreement reached between the Government and the Federation of Port and Dock Workers Union regarding the implementation of the recommendations of the Wage Revision Committee, and that the claim made by the workmen which is devoid of merits is liable to be rejected.

6. Before the enquiry could be commenced in this matter, the Ministry of Shipping & Transport, Government of India, appears to have issued necessary orders to the satisfaction of the workmen and so a joint Memo was filed before this Tribunal, with a request to drop the proceedings treating the dispute to have been settled between the parties.

7. In the light of the Joint Memo filed, the reference made **is terminated holding that the dispute no longer exists.**

Given under my hand and the seal of this Tribunal this the 6th day of August, 1979.

G. SADASIVA REDDY, Presiding Officer

[No. L. 34011(11)/78-D. IV (A)]

NAND LAL, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1979.

का० आ० 3375—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एच० शनमुखप्पा होंगे, जिनका मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारतीय खाद्य निगम, बंगलौर के प्रबंधतंत्र की श्री बी० बी० नागाराजाराव, तकनीकी सहायक, श्रेणी-1 को, बंगलौर से बेलगांव स्थानांतरित करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-42012/9/79-डी० 2(बी)]

हरबंस बहादुर, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 30th August, 1979

S.O. 3375.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Food Corporation of India and their workmen respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri H. Shanmukhappa shall be the Presiding Officer with headquarters at Bangalore and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the Food Corporation of India, Bangalore, in transferring Shri B. V. Nagaraja Rao, Technical Assistant, Grade I from Bangalore to Belgaum, is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

[No. L-42012(9)/79-D.II(B)]

HARBANS BAHADUR, Desk Officer

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1979

का० आ० 3376—लोहा अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 2 के खंड (छ) के उपखंड (ii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित कारखानों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु धातुकर्मीय कारखाने घोषित करती है, अर्थात् :—

1. मैसर्स मानडोवी पेलेट्स लि०,
मारमागोवा बन्दरगाह-403803
प्लांट; बोरिम ब्रिज के नजदीक, शिरोडा-
गोवा-403103.
2. मैसर्स करटी कैमीकल्स लि०,
साल्गांवकर भवन,
वास्को-डी-गामा,
गोवा-403802.
कारखाना : करटी पोंडा—गोवा

[सं० एल-23013/1/79-एम० 4]

आर० के० ए० सुब्रह्मण्या, अपर सचिव

New Delhi, the 10th September, 1979

S.O. 3376.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (g) of section 2 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), the Central Government hereby declares the following factories to be mettalurgical factories for the purposes of the said Act, namely :

1. M/s. Mandevi Pellets Ltd., Marmagoa Harbour-403803.

   Plant at : Near Borin Bridge, Shiroda-Goa-403103.

2. M/s. Curti Chemicals Ltd., Salgaonkar Building, Vasco-da-Gama, Goa-403802.

   Factory : Curti Ponda—Goa.

[File No. S-23013/1/79-M.IV]

R. K. A. SUBRAMANYA, Addl. Secy.

New Delhi, the 13th September, 1979

S.O. 3377.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of East Bhuggatdih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Security Headquarters, At and Post Office Jealgora, District Dhanbad, and their workman, which was received by the Central Government on the 31st August, 1979.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3 DHANBAD

Reference No 22 of 1978

PRESENT :

Shri P. Ramkrishna,

Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of East Bhuggatdih Colliery of M/s. Bharat Cooking Coal Ltd., P.O. Jharia, Distt. Dhanbad.

AND

Their workman

APPEARANCES :

For Employers—Shri T. P. Chowdhury, Advocate.

For Workman—Shri S. P. Singh, General Secy. Khan Mazdoor Congress

INDUSTRY : STATE : Bihar

AWARD

Dated, the 21st August, 1979

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/S 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), have referred the following dispute to the Tribunal for adjudication as per their order dispute to the Tribunal for adjudication as per their order No. L-20012/212/77-D III(A) dated 28th February, 78.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of East Buggatdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jharia, Dist. Dhanbad, in superannuating Shri Joet Singh, Night Guard with effect from 1st July, 1977, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled and from what date ?"

On behalf of the workman herein the General Secretary of the Khan Mazdoor Congress has filed a statement of claim stating that the workman herein was working as a Night Guard in the East Bhuggatdih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. ever since 12-5-47. The management of the colliery served a notice dated 11-4-77 on the workman stating that he would be superannuated with effect from 2-7-77 on the completion of his sixtieth year. The workman contended that he had not attained the age of superannuation by 2-7-77. To this effect the submitted a representation to the General Manager, Area No. 8. No action was taken on that representation. By his letter dated 7-5-77 he requested the management to send him for examination before a Medical Board for determination of his correct age. But the management refused to comply with his request by their letter dated 11-5-75. The subsequent representations made by the workman to the management in this regard were also not considered. Finally he placed the matter before the union. The union approached the A.L.C.(C) Dhanbad on 27-5-77 to take up the matter in conciliation. The conciliation proceedings having failed the A.L.C.(C) submitted his failure report, on receipt of which the Govt. has made the reference in question to this Tribunal. On behalf of the workman it is prayed that he may be reinstated with full back wages.

The management in their written statement submit that the service of the workman herein were taken over by them subsquent to the date of nationalisation. They say, that in the record of the Coal Mines Provident Fund organisation the age of the workman on the date he signed the declaration form viz 5-8-49 was recorded as approximately 32 years. This entry relating to age was corrected as 1-7-17 so as to correspond to the approximate age given If the age of the workman is calculated on the basis of date of birth noted in the Provident Fund records, he would be completing the age of 60 by 2-7-77. They say that the date of birth given in the Provident Fund record as 1-7-17 by way of correction does not affect the case of the workman. It only confirms the approximate age given by him. They also say that the failure on the part of Coal Mines Provident Fund authorities (hereinafter called as C.M.P.F.) in not initialing the correction might have been on account

of oversight. The further submit that when the workman himself declared his age to be 32 years before the C.M.P.F. authorities, there was no point in ignoring that declaration and having his age determind afresh by submitting him to an examination by a Medical Board. They say that the school leaving certificate produced by the workman in support of his case is a forgery. The management prays that this reference may be answered against the workman.

The union filed a rejoinder to the management's written statement on behalf of the workman stating that the C.M.P.F. record relied upon by the management is fabricated. They say that the school leaving certificate produced by the workman is a genuine document and that the said certificate was submitted to the management in the year 1950. They pray that the workman may be reinstated.

On the above pleadings the points that arise for consideration are—

(1) whether the workman has been correctly superannuated with effect from 2-7-77 ?

(2) If not what relief is he entitled ?

Point (1)—The workman herein is a Night Guard working the Bhuggatdih Colliery from 1947 or so. On 11-4-77 the workman was informed in writing (copy of which is placed on the record) that he would be superannuated with effect from 2-7-77 on completion of 60 years of age. The workman protested against this order saying that he had not reached the age of 60. He wrote a letter dated 7-5-77 requesting the management to send him to a Medical Board for proper determination of his age. The management by their reply Ext. W-4 dated 11-5-77 declined to accede to that request. The workman placed his case in the hands of the union to raise an industrial dispute regarding the correctness of the order of superannuation.

Great reliance is placed on the school leaving certificate Ext. W-2 in support of the workman's case apart from some oral evidence. The management relies on the declaration form signed by the workman herein on 5-8-49 before the competent authority in the C.M.P.F. Office wherein his date of birth was given as 1-7-17. WW-1 is the workman. He files the school leaving certificate Ext. W-2. According to him he was 21 or 22 years of age at the time he was appointed in the colliery and that he was 53 or 54 years old by the date of his deposition. WW-2 is Radhunan Tiwary. He deposes that he worked as Chaprasi in the colliery in question. He files his identity card and his horoscope. According to him his date of birth is 1-7-25 and that the order of the management directing him to retire on the ground he had already completed 60 years of age is incorrect. He submits that when he was opposed to appear before a Medical Board the management compelled him to do so in order to determine his correct age. The point made on behalf of the workman is that the management was making discrimination between one workman and another. When WW-1 wanted that he should be sent before a Medical Board for proper determination of his age the management declined to do so whereas against the wishes of WW-2 he was subjected to a medical examination for ascertainment of his age.

WW-3 San Singh is examined to speak to the age of WW-1 the workman herein He belongs to the same village as WW-1 and also claims to be a relation of WW-1. According to his estimate WW-1 would not be more than 55 or 56 years of age on the date of his deposition. He goes on to say that WW-1 and he were contemporaries at the same lower Primary School of their village. On seeing the school leaving certificate he says that it was the certificate issued by the School Head Master.

MW-1 is Shri J. R. Burman, Deputy Personnel Manager of the colliery in question. The workman puts some questions to him taking advantage of his presence before the Court though the management did not choose to examine on their behalf.

On the above evidence it has to be seen if the contention of the workman that he is only 53 or 54 years of age by the date of his deposition before the Court is correct. Not much reliance can be placed on the school leaving certificate Ext. W-2 produced by him. In the course of the rejoinder it is stated on behalf of WW-1 that the school leaving certificate Ext. W-2 was submitted to the management in the year 1950 and that from the management's record that document was taken. The certificate purports to have been issued on 10-4-50. The printed form on which the certificate is issued gives the date of printing as 12-12-73. This shows that Ext. W-2 is a bogus certificate. Further the entries contained therein unless they are checked with the original school admission register cannot be taken as correct. This leaves us with the evidence of the village elder WW-3. His evidence also is vogue and devoid of particulars. His mere assertion that WW-1 is aged about 55 or 56 years without being supported by cogent reasons cannot be accepted. Then there is the declaration of age given by the workman before C.M.P.F. office on 5-8-49. In that form (a true copy of which is placed on the record after comparing the same with the original) the date of birth is given as 1-7-17. At first it is written 'approximate age 32 years' and thereafter those words are scored out and the date of birth 1-7-17 is given. This correction is not attested by any one though the thumb impression of the workman at the foot of the document is taken before some officer of the C.M.P.F. office. Sri S. P. Singh the Secretary of the union contends that since the correction in the date of birth is not attested by any one the entire document should be rejected as being unreliable. I do not agree. This declaration was taken on 5-8-49 that is more than 30 years back. This document is coming from proper custody. The same date of birth as found in this declaration form is entered in the Form B register in which the date on which he joined service (12-5-47) is correctly noted. Against these entries in the Form B register WW-1's thumb impression has been obtained. The correctness of the entries made in this register were never questioned. I accept the correctness of the entries made in the declaration form and the Form B register.

Since the correct date of birth is given in the declaration form before the C.M.P.F. office, the request of the workman that he should be sent to the Medical Board for determination of his age was, in my opinion, rightly rejected by the management.

Lastly Sri S. P. Singh for the workman contended that since the Standing Orders are silent on the question of age of superannuation the workman cannot be superannuated on the completion of his 60 years of age. Since this plea is not taken in the statement of claim or rejoinder, Sri Singh filed a petition on 7-8-79 to add this plea in the statemnt of claim by way of amendment. Since this plea is allowed to be raised and argued and also referred to in the course of the award it is not considered necessary to allow this petition for amendment. According to Mr. Singh the workman is entitled to be in service till he becomes physically unfit to perform his duties. Sri T. P. Chowdhury for the management produces a copy of the letter dated 4-8-72 issued by the Chief Industrial Relations and Personnel Officer fixing the age of superannuation at 60. This order was issued in compliance with the provisions of Section 2(r) of Payment of Gratuity Act, 1972. That the age of superannuation was fixed at 60 years in pursuance of an agreement as per the provisions of the Gratuity Act is reiterated in the order of superannuation dated 11-4-77 and to this part of the order no exception has been taken till the date of arguments. It is not disputed that all the employees are being retired on the completion of age of 60 in terms of this letter. So there is no substance in the contention that in the Bharat Coking Coal Limited's service there is no age of superannuation fixed.

Sri S. P. Singh relies upon column 7 of the profoma Form II of the Employees Provident Fund Scheme 1952 under which the declaration and nomination of a workman have to be taken. Column 7 reads as follows :

"7. Date of birth : Day.....month..... year.....
(where exact particulars are not available, approximate age may be indicated in consultation with the Medical Officer of the Factory/Establishment)."

In this case, Sri Singh argues, since the workman is unable to give the exact particulars of his age, it was incumbent on the employer to consult a Medical Officer to indicate his age. This not having been done he submits that the age entered in the declaration form is of no avail to the management and that the workman's age should be determined now in consultation with the Medical Board. Sri T. P. Chowdhury for the management argues that since the workman himself had given

his approximate age as 32 there was no need for the officer concerned to refer the case to the Medical Officer to determine his approximate age. I agree with this contention.

For the aforesaid reasons Point (1) answered against the workman.

Point (2)—In the result this reference is answered against the workman.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer

[No. L-20012/212/77-D. II(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 15th September, 1979

S.O. 3378.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Daltonganj and their workman over termination of services of Shri Kameshwar Prasad, Clerk-cum-Typist with effect from 19-2-70, which was received by the Central Government on 6-9-79.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3 DHANBAD

Reference No. 19 of 1978 (Ref. 4 of 1976

On the file of CGIT No.1)

PRESENT :

Shri P. Ramakrishna.

Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Daltonganj Dist. Palamau.

AND

Their workman

APPEARANCES :

For Employers—Shri Goel, Regional Personnel Officer.
For Workmen—Shri C. L. Bhardwaj, Vice President National Organisation of Bank Workers.

Industry : Bank State Bihar

AWARD

Dated, the 21st August, 1979

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their order No. F. L-12012/1/76-DHA, dated 30th September, 1976.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the State Bank of India, Daltonganj in terminating the services of Shri Kameshwar Prasad, Clerk-cum-Typist with effect from 19-2-70 is justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The facts as disclosed in the statement of claim filed by the Vice-President of National Organisation of Bank Workers on behalf of the workman are that the workman herein was temporarily appointed as a Clerk-cum-Typist-cum-Cashier by the Agent of State Bank of India, Leteher Branch for a period of 25 days (from 8-1-68 to 2-2-68). He was again appointed as a Clerk-cum-Typist by the Agent of the State Bank of India (S.B.I. for brevity) in Daltonganj Branch from 10-10-68 to 18-2-70. It is contended that during this period he worked in a permanent sanctioned vacancy. It is complained that with effect from 19-2-70 the workman's services were terminated without notice and without giving any reason whatsoever. Notice pay and other dues as per the provisions of Bank award and the provisions of Industrial Disputes Act, Section 2(00) read with S. 25-F are not paid. The workman appeared for a test conducted on 2-3-69 under the Regional Recruitment Scheme. He passed in the written test and on that basis he was called for viva-voce test on 13-7-69. It is submitted that the work and conduct of the workman during this period being satisfactory he was allowed to continue in the post till 18-2-79. They say that if the workman had not passed the test he would not have been allowed to continue till 18-2-70. The workman made several representations to the S.B.I. authorities to reconsider their order of temination of service but to no purpose. So he approached this union to espouse his cause. The union also made repeated requests to the S.B.I. authorities for reinstatement. The S.B.I. not having acceded to their request, the union placed the matter before the A.L.C.(C), Ranchi for his intervention. The case was referred to the A.L.C.(C), Hazaribagh for necessary action The A.L.C. submitted the failure report dated 22-12-75 to the Govt. After the receipt of the failure report by the Government the management of the S.B.I. Patna offered a temporary appointment for a period of one month subject to the condition that he should pass the requisite test held by the Bank for recruitment to the post of Clerk-cum-Typist. The workman declined the offer. Thereafter the present refrence is made. It is submitted that since the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act and paras 522(4) to 524 of the Sastry Award are not complied with, the workman is entitled to reinstatement in his original post from 1976 with full back wages and continuity of service and other compensations to which a perment employee is entitled under the Bank Award.

The S.B.I. filed a written statement stating that the workman was appointed on a purely temporary basis as Clerk-cum-Typist in their Daltongunj Branch on 10-10-68 for a period of 15 days. The letter of appointment clearly provided that his appointment would come to an end on the expiry of the said period of 15 days unless extended for a further period. It was also stated in the said letter of appointment that no claim whatsoever for absorption in permanent cadre or for giving an appointment in the Bank would be entertained on that account. In this manner several letters of appointment were issued to the workman extending his period of service from time to time till 18-2-70. They submit that the temporary service of the workman came to an end on the expiry of 18 days commencing from the last order of appointment dated 31-1-70. The Bank asserts that the services of the workman were not terminated on account of his being rendered surplus and therefore his contention that he must be deemed to have been retrenched from service with effct from 19-2-70 is not tenable. It is further averred that the workman herein appeared for a written test held on 2-3-69 at Ranchi Branch under the Regional Recruitment system. Though he qualified himself in the written test he did not get the minimum pass mark of 35 per cent. He secured 'O' marks in the typing test and 30 at the interview and 33 in the written test against the minimum mark of 70 out of 200. The workman was allowed to appear for the test held on 7-6-70 at Ranchi even after his services were terminated, but he did not get the qualifying marks in the written test. He secured 26-1/2 per cent marks only. Had the workman passed the test he would have been absorbed in the Bank's service in a permanent post. They also say that the appointment of workman from 10-10-68 to 18-2-70 was on a purely temporary basis in connection with a temporary increase in work and not against any permanent sanctioned vacancy. Since the termination of the service of the workman is not retrenchment in the eve of law, he is not entitled to be paid any compensation provided under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. The Bank further submits that on a representation made by the workman and more on compassionate ground he was again offered a temporary appointment as Clerk-cum-Typist in the Bank's service as per their letter dated 26-10-76 subject to the condition that his case for permanent absorption in the Bank's service should depend on his performance in the written test/interview which was to be held shortly thereafter. The workman refused to accept the said offer as per his letter dated 4-11-76. In the circumstances the Bank submits that the workman is not entitled to any relief whatsoever.

On behalf of the workman a rejoinder is filed reiterating their stand that the termination of the workman's services amounted to retrenchment and that the termination of his service without compliance with the provsions of Section 25-F is illegal. They also assert that the workman was not posted on a temporary basis but was allowed to work against a permanent vacancy. They also say that the Bank was not justified in terminating the workman's services on the ground that he did not qualify at the tests held in 1969 and 1970.

The Bank in their rejoinder while taking the same stand as they took in their original written statement stated that the workman was allowed to continue as a Clerk on a temporary basis till 18-2-70 because the result of the test held in 1969 was not known till that date. They deny the averment made in the statement of claim that as the workman's work and conduct were found to be upto the mark he was allowed to continue till 18-2-70 even though he had not passed the test. They also say that the National Organisation of Bank Workers is not a union recognised by the Bank.

On the above pleadings the points that arise for consideration are :—

(1) Whether the termination of services of the workman with effect from 18-2-70 is retrenchment within the meaning of Sections 2(00) & 25-F of the I.D. Act ?

(2) If so, whether his services are terminated in accordance with the provisions of Section 25-F of the I.D. Act ?

(3) To what relief ?

The dispute was originally referred to C.G.I.T.-cum-Labour Court No. 1, Dhanbad as per the order of the Ministry dated 30-9-76. After recording the entire evidence in the case Sri K. B. Srivastava the then Presiding Officer of Court No. 1 had expired somewhere in November '77. Thereafter the Ministry is pleased to transfer this case to the file of this Tribunal as per their order dated 24/25-2-78 with a direction that the case should be proceeded with from the stage at which it was on the file of Court No. 1 and to dispose of the same according to Law.

Thereafter arguments of both the parties were heard. Point (1)—The workman herein Sri Kameshwar Prasad joined the service of the S.B.I. as a Clerk-cum-Cashier in January '68 and was discharged on 2-2-68. Again he was appointed as a Clerk-cum-Typist at the Daltonganj Branch of the S.B.I. as per order dated 10-10-68 (Ext. M-9) which is given below :

"Shri Kameshwar Prasad is hereby appointed for the post of Clerk typist for 15 days with effect from 10-10-68 or a salary of 148 per mensem plus usual dearness allowances.

2. The appointment will be deemed to have come to an end on the expiry of the above-noted period unless in the meantime it is extended for a further period or periods at the discretion of the Bank.

3. Please note that no claim whatsoever for absorption in the permanent cadre or forgiving an appointment in the Bank will be entertained on this account.

4. Shri Prasad's services can be terminated at the option of the Bank any time without assigning any reason therefor.

5. Ordinarily, however, the temporary employee if he desires may submit a 14 days notice in writing to leave the temporary services; if not he will be liable to the Bank for 14 days' salary in lieu thereof."

Thereafter his services were extended from time to time as per the orders Exts. M-10 to M-27. Exts. M-10 to M-27 are identically worded and it is sufficient if the last order Ext. M-27 dated 31-1-70 which is given below is noticed :

"With reference to my Memorandum No. ..... dated 31-12-69 the temporary services of Shri Prasad as Clerk-typist is extended for further period of 18 days i.e. upto 18-2-70 under the terms and conditions mentioned period therein. The appointment will be deemed to have come to an end at the expiry of the aforesaid period, unless in the meantime it is extended at the discretion of the Bank for a further period or periods.

Agent"

With effect from 19-2-70 the services of the workman were terminated. Before considering the question whether the order terminating the services of the workman is retrenchment within the meaning of Section 2(00), the facts giving rise to this dispute may be briefly narrated.

On 2-3-69 the workman (WW-1) appeared for the test conducted for the clerical post under the Regional Recruitment System. From para 10 of the written statement of the S.B.I. it appears that he secured 33 marks in the written test and thus qualified himself for the interview. In the typing test he secured 'O' marks and at the viva-voce 30 marks. Thus he secured 63 marks out of a total of 200 marks. The minimum marks being 70 out of 200 the workman was declared unsuccessful at the qualifying test. It is not disputed that even after the workman had ceased to be in the Bank's service he was allowed to sit for this test once again on 7-6-70. This time he secured only 26½% in the written test which was not a pass mark. The answer papers and the assessment at the viva-voce of the workman at the test held in 1969 are marked as Exts. M-3 to M-5 Ext. M-30 shows his performance at the typing examination held in 1969. Ext. M-6 and M-7 are the answer papers submitted by the workman at the test held on 7-6-70. Ext. M-2 show his performance at the type test held on the same date viz. 7-6-70. It is the Bank's case that though the workman was initially recruited on a purely temporary basis they were prepared to absorb him in their service on a permanent basis provided he passed the requisite test. Because of his failure to pass the test held in 1969 they say his services were terminated with effect from 18-2-70. If the workman had passed the test in June '70 i.e. long after his termination, the Bank would have favourably considered his case for permanent absorption. Thereafter the workman went on addressing letters to S.B.I. authorities to reconsider his case which are marked as Exts. W-31 to W-34. The tenor of these letters addressed by the workman before approaching the union is altogether different from the stand taken by him after approaching the union. In the letter Ext. W-31 dated 31-12-71 and the letter dated 13-9-72 which is Annexure I to the statement of claim, he prayed the Bank to permit him to sit for the examination once more. The letters Ext. W-32 and W-33 written in July '72 show that the workman is aware of the fact that the Bank's refusal to keep him in service was on account of his failure to pass the requisite test. But still he does not request the Bank to give him another opportunity to appear for the test, but simply says that his case might be considered on sympathetic ground particularly in view of the fact that he had already attained the age of 25 (After the 25th year a person is barred to seek employment in a Bank). In the letter Ext. W-34 dated 9-8-72 paragraph 3 he complains that the Bank did not disclose any reason whatsoever for termination of his services. He also says that the result of the examination held in 1969 was not communicated to him. On 22-8-72 the workman addressed the letter Ext. W-35 to the President of the National Organisation of Bank Workers to take up his case. Thereafter the union addressed the letters Ext. W-40 and W-41 to the Bank authorities. In March '73 the union approached the A.L.C.(C), Ranchi to take up the matter in conciliation. The matter was pending before the A.L.C. from 73 till 75. Towards the end of 1975 the A.L.C. submitted his failure of conciliation report. Thereafter the Bank in order to settle the dispute amicably offered the workman the post of Clerk-cum-Typist on a purely temporary basis for a period of one month with a clerk understanding that the question of continuing his temporary services or absorption in the permanent service would depend upon his being found suitable in the written test/interview vide Ext. W-6. The workman in his reply to this offer declined to avail himself of this opportunity in the following words :

"I acknowledge receipt of your kind letter No. 21/585 dated 26-10-1976 offering me temporary appointment for one month. I am sorry to accept this offer.

I have already approached you number of times directly as well as through my union viz. National Organisation of Bank Workers whereby I and my union has already brought to your kind notice that my services were illegally terminated despite my having qualified the test held by you. I, therefore, request you to rein-

state me in Bank service with full back wages and thus settle the long outstanding dispute.

Sd/- Kameshwar Prasad"

Thereafter the present dispute is referred to the Tribunal for adjudication.

Though several pleas have been taken on behalf of the workman the one that has been pressed most is that the order removing the workman from service amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(00) and therefore the termination of the workman's services without payment of notice pay and other dues as provided U/s 25-F is illegal. It is said that since the order of retrenchment is not in accordance with the provisions of Sec. 25-F the workman must be deemed to be continuing in service. Therefore they pray for reinstatement with full back wages and continuity of service. The workman also claims the status of a permanent employee. Reliance is placed on the case reported in 1976 (I) LLJ page 478 State Bank of India Vs. Sunderamoney (S.C.) For the Bank Sri Goel submits that the instant case is not one of retrenchment within the meaning of Section 2(00) but discharge simpliciter on account of the workman's failure to comply with the essential requirements of service viz. a pass in the test. According to him the word retrenchment as defined in Section 2(00) and as used in Section 25-F means discharge of surplus labour or staff by the employer for any reason whatsoever other than as punishment inflicted by way of disciplinary action and for any of the reasons mentioned in Sub-clauses A to C of Section 2(00). He further submits that the decision of the Supreme Court reported in A.I.R. 1957 S.C. page 121 Barsi Light Railway Co. Ltd., Vs Joglekar is an authority for this proposition. He further submits that the law laid down in the aforesaid decision of Supreme Court which is rendered by a Bench of five Judges should be followed in preference to the Supreme Court decision reported in 1976 (1) LLJ page 478 rendered by a bench of two judges only.

The facts of the case in 1976 (I) LLJ 478 may be gathered more clearly from the judgment of Mr. Justice K. N. Mudaliar reported in 1973 (II) LLJ page 551. It may be seen that the workman Sundermoney approached the Madras High Court with a writ petition challenging the order of termination of his services. The first Court allowed the petition and a writ Appeal preferred by the Bank against the judgment of the Single Judge was dismissed. Thereafter the Bank carried the matter in Appeal to the Supreme Court. Sunderamoney was employed as a Cashier in one of the Branches of the S.B.I. from 4-7-70 to 18-11-72 with intermitent breaks in service. He was appointed on a temporary basis although the Cashier's work in the Bank was of a permanent nature Even after his termination another person was immediately appointed in his place. The petitioner contended that for the two and half years of continuous service he had put in. the Bank should have paid him the statutory retrenchment compensation U/s 25-F of the Industrial Disputes Act. Since the termination of the service was not in accordance with the provisions of Section 25-F he should be deemed to have been in service even after the date of the illegal order of termination of his service The Bank pleaded that the order appointing Sundermoney being of a composite character appointing the petitioner as a temporary employee for the period mentioned therein and on the expiry of that period the employment itself automatically ceasing, it is submitted, that on and from 18-11-72 Sundermoney had ceased to be an employee of the Bank. The order of appointment having worked itself out, without any further action on the part of the Bank, the services of Sundermoney stood terminated. The employee's services having come to an end by affux of time, the provisions of Section 2(00) and Section 25-F of the Industrial Disputes Act are not attracted. It was further pleaded that since Sudermoney had failed to qualify himself at the written test held by the Bank for recruitment of Clerks and Cashiers on a permanent basis, the Bank could not consider him for permanent absorption in their service. Since he had also completed the age of 25 years on 20-11-72 the Bank could not consider him for permanent employment. It was also contended on behalf of the Bank that since there had not been any reduction in the quantum of work in the Branch the order of termination could not amount to retrenchment and that unless there was surplus labour the petitioner could not be said to have been retrenched. On the facts it was found by the first Court the termination of service of the petitioner Sundermoney amounted to discharge of surplus labour or staff. In the light of this finding it was held that the termination of service of Sundermoney was by way of retrenchment and the management not having satisfied the conditions prescribed in Section 25-F before retrenching him, the order of termination was quashed. Before the Supreme Court it was contended that when the order of appointment carried an automatic cessation of service the period of employment worked itself out by efflux of time and not by an act of the employer and such cases are outside the concept of retrenchment as defined in the Industrial Disputes Act. This contention was not accepted in view of the very wide definition of the word retrenchment (termination . . .) given in Section 2(00) of the Industrial Disputes Act.

The facts of the present case are also quite similar to the facts of the reported case. As in the reported case the workman was appointed on a temporary basis from 10-10-68 till 18-2-70 under several orders of appointment. There was no break in service. The last order of appointment Ext. M-27 extracted above is couched in the same words as the order of termination in the reported case, in that he was specifically told therein that his services would be deemed to have come to an end on expiry on 18-2-70. As in the reported case his services were terminated because they were rendered surplus. This can be clearly gathered from para 12 of the Bank's written statement wherein it is stated that the workman was appointed on a purely temporary basis in connection with the temporary increase in work and not against any permanent sanctioned vacancy. MW-1 who worked in Daltongunj Branch office during the relevant period deposed that there was no temporary increase in work necessiating the appointment of the workman as a Clerk.typist and that he was appointed in a leave vacancy. Since this evidence of his goes against the pleading of the Bank, the same cannot be accepted. It follows that after the temporary increase in work was satisfactory attended to the services of he workman were rendered surplus and consequently he was discharged from service.

In the case reported in 1979 (1) LLJ page 211 (of Kerala High Court Full Bench) at page 224, while discussing Sundermoney's case it is observed that it (Sunderamoney's case) was a case where the appointment order given to the employee itself specified that his services were not required after the expiry of the period mentioned there whereupon the employee would become surplus hand. The wording of the order of appointment in the instant case being very similar to the one considered in Sundermoney's case, it must be held that after the expiry of the period mentioned in that order, the workman herein was rendered surplus.

For the aforesaid reasons the argument of Sri Goel that there is no element of surplus in the instant case and therefore the view taken in A.I.R. 1957 S.C. 121 (Barsi Light Railway Vs Joglekar) should be followed in preference to the view taken in sundermoney's case to repeal the contention of the workman that his is a case of retrenchment cannot be accepted.

Point (1) held in favour of the workman.

Point (2)— Admittedly the Bank has not followed the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act before retrenching the workman herein.

Before concluding another point raised by Sri Goel may be adverted to. He argues that the plea that the termination of the services of the workman herein was retrenchment and since the provisions of Section 25-F were not followed before he was retrenched he was entitled to reinstatement was not taken till the date of the filing of the statement of claim in this case. For that reason he submits it must be held that since the demand was not raised in the proper form before the management in the first instance, the reference should be rejected. I do not agree. The workman and the union were questioning the validity of the order of termination of the service. They were also praying for reinstatement. The legal plea on which reinstatement was prayed for might not have been clearly put forward. Further the plea now put forward by the union is based on the judgment of the Supreme Court in Sundermoney's case rendered on 16-1-76. The union or the workman could not have anticipated this plea in 1970 when the dispute arose.

Point (3)—In view of the findings on points 1 and 2, it follows that the order of termination is illegal and that the workman is enttiled to reinstatement. The workman is entitled to the same relief as is given by the Supreme Court in Sundermoney's case viz.

> "The respondent shall be put back where he left off, but his new salary will be what he would draw were he to be appointed in the same post today de novo. As for benefits, if any, flowing from service he will be ranked below all permanent employees in that cadre and will be deemed to be a temporary hand upto now. He will not be allowed to claim any advantages in the matter of seniority or other priority inter-se among temporary employees on the ground that his retrenchment is being declared invalid by this Court."

In assessing the back wages reference may be had to the certificate issued by the Assistant Branch Manager, Life Insurance Corporation, Baltongunj, Sub Office to the effect that the workman herein was an Agent of the Corporation during the period 13-4-74 to 30-4-1976 and that during that period he earned a total sum of Rs. 1626.78 paise. Less this sum, the workman is held entitled to back wages at the rate indicated above.

Point (3).—In the result this reference is answered as follows :

The termination of the services of the workman herein is not justified.

He is entitled to the relief of reinstatement as per the terms and conditions set out above viz.

(1) Back wages at the rate payable to the latest recruit as on the date of the award, less the sum of Rs. 1626.78 paise earned by him by way of commission from the Life Insurance Corporation from the date of termination till the date of reinstatement.

(2) He should be put at the bottom of the list of temporary employees serving in the Bank as on the date of the award. He will not be allowed to claim any advantages in the matter of seniority or any other priority inter-se among temporary employees on the ground that his retrenchment is being declared invalid.

P. RAMAKRISHNA, Presiding Officer.

[No. I-12012/1/76-D.II.A.]

S. K. MUKERJEE, Under Secy.

New Delhi, the 21st September, 1979

S.O. 3379.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to Shri Ram Baboo, Mine Owner, Tanki Area Masonry Stone Mine, resident of Dhakadkhori, District Kota and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th September, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI.

I.D. No. 13 of 1978

In re :

The President,

Pathar Khan Mazdoor Sangh,

E-3/91, Near New Railway Colony,

Kota-324002 (Rajasthan) ..Applicant

Versus

Shri Ram Baboo, Mine Owner,

Village Post Dhakhedkheri,

District Kota (Rajasthan) ...Respondent

AWARD

The Central Govt. as appropriate Govt. vide its order No. L-29012/41/77-D.III.B dated the 19th January, 1978 made a reference u/s 10 of the I.D. Act to this Tribunal in the following terms :

> 'Whether the action of Shri Ram Baboo, Village and Post Dhakhedkheri, District Kota in terminating the services of S/Shri Raju, Krishnan, Kanswamy, Ramu and Moti, Cutters in the Masonry Stone Mines at Tanki area w.e.f. 22nd August, 1977 is justified? If not, to what relief the workmen are entitled ?'

2. On receipt of the said reference usual notices were sent to the respective parties for appearance. Whereas Shri Mahabir Prashad Sharma put in appearance on behalf of the workmen, none has appeared on behalf of the Management in spite of registered and ordinary notices. With the result ex-parte proceedings were ordered against the Management vide my order dated 29-6-79 and ex-parte evidence was ordered to be recored. The ex-parte evidence consists of statement on affidavit of Shri Mahabir Prashad Sharma, the President of the Pathar Khan Mazdoor Sangh, Kota and from the perusal of his affidavit I find that he has failed to establish his claim for reinstatement of these workmen. He has further failed to establish that the services of five workmen referred to in the order of reference were terminated illegally or unjustifiably. From the perusal of his affidavit I find that only thing stated therein is that the services of these five workmen were terminated on 22-8-1977 without any charge-sheet or notice and a dispute was raised in this behalf. However mere fact that the services have been terminated would not by itself enough to establish the claim of of the workmen. It must inter-alia be established that the services were terminated illegally and unjustifiably. It has not been established as to from which date the workmen were employed with this establishment. It is not thus possible to come to a conclusion that there was any violation of any industrial law in the termination of services of these workmen. It is nowhere stated as to the nature of employment of these workmen. There is nothing to suggest that these workmen were not casual workers. In any case there is nothing to establish that these workmen were regular workmen or that there was any violation of Sec. 25-F of the I.D.Act, 1947 or for that matter any other provisions of I.D. Act. It has also not been shown as to what are the standing orders of the respondent-Management. Even the appointment letters of these workmen have not been produced which could show the appointment of these workmen or the conditions of appointment. The burden of establishing of these facts was upon the workman which the workmen have failed to discharge and in these circumstances it cannot be said that the services of these workmen were terminated illegally or unjustifiably and in the absence of such a conclusion it cannot be said that the termination of these workmen was illegal or unjustifiable or that the workmen were entitled to any relief whatsoever. Accordingly it is awarded that the workmen have failed to establish that the termination of their services was illegal or unjustified or that they were entitled to any relief whatsoever. Parties however are left to bear their own costs.

Dated : the 20th August, 1979

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer.

[No. L-29012/41/77-D.III(B)]

S.O. 3380.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Tapukara & Dhaneshwar Sand Stone Mines, District Bundi (Rajasthan) and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th September, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 107 of 1978

In re :

The President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E-3/97, Near New Railway Colony, Kota ...Applicant.

Versus

Shri Kanhayalal Ghatiwala, Mine Owner, C/o Kanhayalal Rameshwardas, Kunadi, Kota. ...Respondent

AWARD

The Central Government as appropriate Government made a reference vide its order No. L-29012/10/78-D. III. B dated the 4th December, 1978 to this Tribunal in the following terms :

(a) whether the demand of the workmen of Tapukara and Sand Stone Mines (District Bundi) of Shri Kanhayalal Ghatiwala for the payment of Bonus for the Accounting Year 1975-76 at 20 per cent of their wages is justified ? If so, to what quantum of bonus are the workmen entitled ?

(b) Whether the demand of the aforesaid workmen for enhanced wages to un-skilled, semi-skilled and skilled and monthly rated workmen is justified ? If so, to what quantum and from which date ?

(c) Whether the demand of the aforesaid workmen for the supply of three summer and one winter uniforms, shoes etc. per year to Truck Drivers and Cleaners is justified ? If so, to what quantum these workmen are entitled ?

2. Upon receipt of this reference usual notices were sent to the parties and in pursuance thereof a statement of claim was filed on behalf of the workmen. None had appeared for the Management until ex-parte proceedings were ordered against the Management vide my order dated 29th June, 1979 and the case was adjourned for ex-parte evidence to 13th August, 1979 On the 13th August, 1979 Shri Mahabir Prashad Sharma, the authorised representative of the workmen appeared and has filed a compromise application Ex. S/1 in this matter. From the perusal of application Ex. S/1 I find that it has been signed by one Rameshwar Dass as Attorney for Kanhayalal Ghatiwala and it shows that both the parties have arrived at a settlement. The said settlement is Annexure to the above mentioned letter and from the perusal thereof I do find that the settlement is for the benefit of the workmen and also that the workmen and the Management has settled the dispute in a proper way. Statement of Shri Mahabir Prashad Sharma was therefore recorded in which it is stated by him that 'the above case has been settled between the parties and now there is no dispute left between the parties. I hereby file a settlement which has been arrived at between the parties and has been signed by representatives of both the parties and a no dispute award as per Ex. S/1 be made'. In view of the statement of Shri Mahabir Prashad Sharma reproduced above I hold that the parties have arrived at a settlement and as such a no dispute award is hereby made in this matter. Parties would be bound by the terms of settlement Annexure to letter Ex. S/1. Parties would bear their own costs.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

[No. L-29012/10/78-D. III. B]

New Delhi, the 24th September, 1979

S.O. 3381.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Shri Mohammed Hanif, Mine Owner, Baroda and his workmen, which was received by the Central Government on the 5th September, 1979.

BEFORE SHRI MAHESH CHANDRA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

I.D. No. 27 of 1977

In re :

President, Pathar Khan Mazdoor Sangh, E-3/97, Near New Railway Colony, Kota-2 . . .Petitioner.

Versus

Shri Mohammed Hanif, Mine Owner, Village Badora, Post Atru, Kota. ..... Respondent.

AWARD

The Central Government as appropriate Government made a reference u/s 10 of the I.D. Act vide its order No. L-29011/5/77-D III, B. dated the 21st March, 1977 to this Tribunal for adjudication. The schedule of the said reference order reads as under :

"Whether the workmen employed in Badora Sand Stone Mines" in the District of Kota (Rajasthan) of Shri Mohammed Hanif, Mine Owner, Post Atru, District Kota are entitled for grant of any paid national and festival holidays ? If so, on what occasions and from which year.

2 On receipt of the reference usual notices were sent to the parties to appear on the 26th April, 1977. None appeared on 26th April, 1977 and fresh notices were ordered to be issued for the 6th July, 1977. Once again none appeared for the parties and fresh notices were issued for 1st August, 1977 when Shri M P. Sharma appeared for the workman but none appeared for the Management and in consequence Regd. A.D. notice was issued for the 2nd September, 1977. Thereafter a number of Regd A D. notices were issued to the respondent mine owner and the cases were even fixed at Udaipur and Jaipur but during all this period none has appeared for the Management with the result that finally ex-parte order was passed against the Management vide my order dated 21-10-78 at Jaipur Camp and ex-parte evidence was ordered to be recorded Now the ex-parte evidence has been recorded which consists of statement on affidavit which is Ex. W/1. From the perusal of the affidavit I find that the workmen have also submitted a copy of notice purported to have been sent Regd. A D. to the respondents which is dated 21 4-1976. There is copy of another copy of notice dated 22-11-1976. A Regd. acknowledgement is also on record. From the perusal of these three documents I do find that the workmen of Sand Stone Mine, Badora have been claiming 10 annual leaves with wages on account of national holidays and religious festivals. From the persual of the affidavit of Shri Mahabir Prashad Sharma also I find that the workmen have claimed 10 days paid holidays on account of national holidays and festivals. It is stated in the said affidavit that Shri Mahabir Prashad Sharma is the President of Pathar Khan Mazdoor Sangh Kota which is a registered trade union under the Trade Unions Act, 1926, and the workers of Sand Stone Mine, Vadhora were also member thereof. It is also stated that notice dated 21-4-76 and 22-11-76 to the Management copies to Asstt. Labour Commissioner (Central) were sent but no settlement or compromise has been effected so far in respect of the national holidays and festival holidays. Thus from the perusal of this evidence it is established that a demand for paid national and festival holidays was raised with the Management and that in consequence nothing has come out of the said demand and in consequence this reference was made.

2. From the perusal of statement of claim fixed on behalf of the workmen I find that these workmen have claimed a right to paid holidays on account of national holidays and festivals. I have heard Shri Mahabir Prashad Sharma on this matter and have given my considered thought to the matter before me and I have come to the conclusion that it is in the fitness of things that the workmen are awarded paid holidays for the three national holidays namely 26th January, on account of Republic day, 15th August on account of Independence day, and 2nd October on account of Mahatma Gandhi Jayanti. The employers' would be liable to grant these three paid national holidays to the workmen and it is awarded that the workmen of Badhora Sand Stone Mines are entitled to grant of three national holidays above mentioned that the 26th January, 15th August and 2nd October in a year. I am not oblivious of the fact that the workmen have not produced any evidence to suggest that these holidays are being allowed in any other concern in the neighbourhood. However, I am purported to grant the benefit of these three national holidays by the fact that these would enable these workers in Sand Stone Mines to join the main stream of the nation in celebrating these days of national importance. It would have the effect of a national integration as well.

3. I do not think any case has been made out by the workmen for grant of any other paid festival holidays. In fact no evidence has been led to show that there is any agreement between the Management and workers union in this behalf. They have also not led any evidence to establish that there is any practice of granting festival holidays in other mines

or Industrial establishments of the area except those statutarily covered The workmen have also failed to show figures of their output and production or to bring out the financial burden or expenditure which would be involved if a practice to grant festival holidays is introduced While agreeing that there is need for standardisation of service conditions including those relating to grant of festival holidays, I am afraid time is not yet ripe to grant festival holidays except where there are agreements between the parties The workmen have not established that there are any standing orders granting any festival holidays The model standing orders under the Industrial Employment (Standing Orders) Act 1946 apparently are not applicable to these workmen Keeping in view of those facts I am of the opinion that no case has been made out for grant of any paid festival holidays in these Sand Stone Mines and accordingly I hold that the workmen are not entitled to any paid holidays over and above these three national holidays awarded above

4 In view of my discussions and findings above it is awarded that the workers shall be given three paid national holidays for the 26th January, 15th August and 2nd October in a year by the employers The workmen would also get costs of this petition which is assessed at Rs 250.

MAHESH CHANDRA, Presiding Officer

Dated the 20th August, 1979

FURTHER AWARDED :

That the requisite number of copies of this award may be sent to the appropriate Government for necessary action at their end

MAHESH CHANDRA Presiding Officer

Dated the 20th August, 1979

[No L-29011/5/77-D. III (B)]

S.O. 3382.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur (M P) in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Banmore Cement Works of A C C Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st August, 1979

BEFORE SHRI S N JOHRI, B Sc, LL M PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M P)

Case No CGIT/LC(R)(14)/1978

PARTIES

Management of Banmore Cement Works of A C C Ltd, and their workmen represented through the President, Shri Bahadur Singh Thakar, A C C Pathar Khadan Mazdoor Sangh, Kailaras/Semai, Distt Morena, Shri Ram Mohan, Secretary, Samyukta Cement Shramik Sangh, Cement Factory, District Banmore, Morena and Shri Ranjit Singh Badoria, President, Cement Khadan Mazdoor Sangh, Kailaras/Semai, Distt Morena (M P)

APPEARANCES :

For Workmen—(1) Shri Bahadur Singh Dhakar, President, ACC Pathar Khadan Mazdoor Sangh, Kailaras

(2) Shri Ram Mohan, Secretary, Samyukta Cement Shramik Sangh

(3) Shri Ranjit Singh Bhadoria, President, Cement Khadan Mazdoor Sangh

For Management—(1) Shri P S Nair, Advocate

(2) Shri S K Dubey, Advocate

(3) Shri B N Wadhwani, Personnel Manager

INDUSTRY : Cement DISTRICT : Morena (M P)

AWARD

Jabalpur, the 21st August, 1979

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour vide Order No L 29011/4/78 D III B dated 1st March, 1979, for the adjudication of the following industrial dispute —

'Whether the action of the management of Kailaras and Semai Quarries of Associated Cement Co Ltd Banmore, Morena District, Madhya Pradesh in not granting to 23 workmen (list enclosed) permanent status or first preference in regular employment according to seniority is justified ? If not, to what relief the said workmen are entitled and from what date ?"

LIST OF WORKMEN

1 Shri Pati Ram S/o Jhugiriya.
2 Shri Pat Ram S/o Vijlu
3 Shri Ram Singh S/o Lalu
4 Shri Budhi S/o Dhannu
5 Shri Arjun S/o Lal Krishna
6 Shri Maveshya S/o Baldev
7 Shri Durjan S/o Chimman.
8 Shri Hira S/o Dhan Pal
9 Shri Naktu S/o Patoriya
10 Shri Gajua S/o Chotiya.
11 Shri Chhantu S/o Dhasiya
12 Shri Ramswaroop S/o Mohan Lal
13 Shri Ghoji S/o Chhotiya.
14 Shri Bhola S/o Guti.
15 Shri Jodha S/o Ganesha
16 Shri Anta S/o Fodahiya
17 Shri Naktu S/o Sukku
18 Shri Chantoli S/o Mool Chand
19 Shri Parmal S/o Dayaram
20 Shri Dayaram S/o Ganga
21 Shri Dhoji S/o Smahiya
22 Shri Bhag Chand S/o Mangtra.
23 Shri Pati Ram S/o Bala

2 The management, Sanyukta Cement Shramik Sangh and A C C Pathar Khadan Mazdoor Sangh filed a settlement dated 29th May, 1978 Cement Khadan Mazdoor Sangh Union raised an objection to the settlement After making the needful enquiry the settlement was rejected by the order of this Tribunal dated 28-5 1979 as unreasonable on the ground that it envisaged reduction in the pool causing hardship of retrenchment and unemployment to about 43 workmen against which the gain to the workers was comparatively nominal Another ground for the rejection of the settlement was that the workmen were made to agree to the purchase of 3000 tonnes of good quality of limestone from outside which appeared to me to be minimising the opportunity of engagement of more labourers that would have been required from mining that much of limestone from these quarries

3 Now the management has by an application today deleted the clause relating to the reduction in the pool Moreover, since C K M S and the management agree that good quality limestone is not available in these mines so that the same will have to be purchased from outside Shri B N Wadhwani, Manager Personnel at the headquarter has given an oral assurance that this purchase from outside market would not lead to any retrenchment In view of the deletion of the said clause and the oral assurance so given at the bar by Shri Wadhwani, the agreement now assumes a reasonable shape and now therefore opposing Union Cement Khadan Mazdoor Sangh, has also no objection to the award being passed in terms of the settlement Consequently Shri Ranjit Singh Badoria wtihdraws his opposition to the settlement This amendment of settlement by the management is wholly favourable to the workers hence the

consent of the unions which already signed the settlement and are absent today, need not be obtained. Their implied consent to an amendment in their favour is presumed. As such the award is given in terms of the settlement. The portions of the settlement relevant to the reference shall form part of the award.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

Dated: 21-8-1979.

ANNEXURE

TO

Award in Case No. CGIT/LC(R)(14)/78

Associated Cement Company Ltd. Banmore Cement Works, Morena Vs. Workmen.

RELEVANT PORTION OF THE TERMS

OF SETTLEMENT

1. The Company stated that originally the Railways supplying 14 raks per week, each rake consisting of 10-1/2 wagons. Since long the operation of railways deteriorated on account of poor condition of loco engine resulting in reduction of hauling capacity which led to less supply of wagons in a rake and reduced number of rakes per week. The wagons in a rake were reduced from 14 to 11.5. However, the railways have improved its operation of late and have started supplying 13 takes per week on an average and each rake consisting of 10 wagons. This resulted in greater job opportunity for casual workers. With the above better performance of railways, the Company is in a position now to provide for 8 to 10 days work in a month to each of the casual workers of the pool. The Company agrees to provide increased number days work if the railways continue the above performance. However if the performance of the railways in supply of wagons and number of rakes goes down the Company does not give any guarantee of employment for such increase in number of days of work.

2. *** *** ***

3. It is agreed by the Company that it shall fill up 8 future vacancies likely to be caused by the retirement of permanent workers from amongst these 23 casual workers on the basis of seniority-cum-merit within one month from the date of passing of an award by the Tribunal in terms of award.

4. The Company further agrees that whenever it decided to fill up further future vacancies due to exigencies of work, the remaining 15 casual workers out of these 23 casual workers will be considered for permanent employment on the basis of seniority-cum-merit, as early as possible.

5. The Company as a gesture of goodwill, has already paid an advance of Rs. 250 to each of the 18 workers who resorted to strike and Dharna. This advance will be recovered in easy instalments of Rs. 2 from wages of one days attendance. Such recoveries will be made after 15th April, 1978. The copy of such an agreement is enclosed.

7. The Unions undertake that the strike and agitation by the casual workers will be withdrawn forthwith and Unions shall give full cooperation in maintaining full output, discipline and good industrial relations.

8. The parties agree that this agreement will be filed before the Tribunal with a request to pass an Award in terms of this Agreement.

Signed this 29th day of May, 1978.

Sd/-

ACC PATHAR KHADAN MAZDOOR SANGH, KAILARAS/SEMAI

Sd/-

President

SAMYUKTA CEMENT SHRAMIK SANGH, BANMORE

Sd/-

RAM MOHAN DIXIT, Secretary.

ASSOCIATED CEMENT COS. LTD.,
BANMORE CEMENT WORKS.
Sd/-
Gen. Manager
Agent

Kailaras & Semai Quarries.

PART OF AWARD

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

Dated: 21-8-1979

[No. 29011/4/78-D.III.B]
A. K. ROY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979